हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 मार्च, 2008

खण्ड-1, अंक-2

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

सोमवार, 24 मार्च, 2008

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11) 1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(11)19
वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11) 20
बैठक का स्थगन	(11) 35
वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11) 35
विधान कार्य--	(11) 56
1. दि हरियाणा लेजिसलेटिव असैम्बली (एलाउंसिज एंड पेंशन ऑफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2008	(11) 56

मूल्य : 66

2. दि हरियाणा स्पेशल इकोनोमिक जोन (अमैंडमैंट) बिल, 2008 (11) 59

बैठक का समय बढ़ाना (11) 61

दि हरियाणा स्पेशल इकोनोमिक जोन (अमैंडमैंट) बिल, 2008 (पुनरारम्भ) (11) 62

3. दि हरियाणा स्टेट लेजिसलेचर (प्रिवैंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 2008 (11) 64

वाक-आउट (11) 64

दि हरियाणा स्टेट लेजिसलेचर (प्रिवैंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 2008 (पुनरारम्भ) (11) 65

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 24 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सवाल जवाब होंगे।

Separate Division /Sub-Division for Meham Constituency

***960. Sh. Anand Singh Dangi** : Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that the area of Meham constituency falls in three Divisions i.e. Rohtak, Jind and Bhiwani due to which the farmers have to face a great difficulty; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to form a separate Division or Sub-Division for whole of the area of the Meham Constituency ; and

(b) if so, the time by which such a proposal is likely to be materialized ?

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) मदीना जल सेवाएं उपमण्डल रोहतक का मुख्यालय महम में स्थानान्तरित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तदानुसार, बोन्द जल सेवाएं मण्डल, भिवानी तथा जल सेवाएं मण्डल, भिवानी के कुछ क्षेत्र जोकि महम निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है, को भी प्रस्तावित महम उपमण्डल के साथ संयोजन करने की भी प्रस्तावना है।

(ख) महम में उपमण्डल जून, 2008 में खोले जाने की संभावना है।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मदीना जल सेवाएं उपमण्डल रोहतक का मुख्यालय महम में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव लगभग मान लिया है । अध्यक्ष महोदय, महम हल्के के किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि महम हल्का तीन डिवीजनों में बंटा हुआ है । महम हल्के का कुछ एरिया भिवानी में, कुछ एरिया जींद में और कुछ एरिया रोहतक में पड़ता है जिससे किसानों को अपने काम-काज करने के लिए आने जाने में बहुत असुविधा होती है । इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि महम निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी माईनर्ज हैं, वे जितने भी डिवीजनों और सब-डिवीजनों में पड़ते हैं उनको एक डिवीजन में जल्दी से जल्दी कर दिया जाये ताकि वहां के किसानों को समस्या न हो । मंत्री जी ने अपने जवाब में जहां 'संभावना' शब्द का इस्तेमाल किया है इसकी जगह वे आश्वासन दें कि महम हल्के के सभी माईनर्ज को एक डिवीजन में कर दिया जायेगा ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि नहर विभाग निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर डिवीजनों का गठन नहीं करता । लेकिन इस स्पेसिफिक केस में माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि नहर विभाग की पोलिसी यह है कि एक सब-डिवीजन या डिवीजन का कंट्रोल हैड से लेकर टेल तक एक ही डिवीजन या सब डिवीजन के पास रहे । यह सरकार की मूलभूत नीति है । लेकिन मेरे माननीय साथी के क्षेत्र के अंदर जो इलाका पड़ता है उसमें कई माईनर्ज हैं जिनकी टेल इनके यहां आकर खत्म हो जाती है और उनका कंट्रोल भी भिन्न-भिन्न डिवीजनों में होने की वजह से दिक्कत आ रही है । इसलिए निर्णय लिया है कि महम हल्के के लिए अलग से डिवीजन बनाया जायेगा जिसके बारे में मैंने अपने जवाब में भी चर्चा की है । जहां तक माननीय साथी ने 'संभावना' शब्द की बात की है इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इसको यथार्थ में बदला जायेगा ।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय बिजली मंत्री जी ने जो बताया है उससे मैं संतुष्ट हूं । लेकिन मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि महम हल्के में केवल दो माईनर्ज ऐसे हैं जिनका हैड किसी दूसरे हल्के में पड़ता है जिनका सब डिवीजन जुलाना है । दो माईनर्ज के अलावा जितने भी माईनर्ज हैं उनके हैड और टेल महम हल्के में ही पड़ते हैं इसलिए जल्दी से जल्दी वहां अलग से डिवीजन बनाया जाये ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में बताया है कि हम आलरैडी डिवीजन बनवा रहे हैं और जो सीमित समय दिया है उस समय सीमा तक काम पूरा कर दिया जायेगा ।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महम के लिए अलग डिवीजन बनाने पर बोन्द जल सेवाएं, भिवानी तथा जल सेवाएं मण्डल, भिवानी का हैडक्वार्टर भिवानी में ही रहेगा या शिफ्ट कर दिया जायेगा । मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि बोन्द जल सेवाएं, भिवानी तथा जल सेवाएं मण्डल, भिवानी का हैडक्वार्टर भिवानी में ही रहे ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी की चिंता वाजिब है लेकिन हमने पहले से ही सुनिश्चित किया है। मेरे माननीय साथी प्रश्न के जवाब को पढ़ें उसमें लिखा है कि उसके कुछ क्षेत्र निकाले जायेंगे मगर हैडक्वार्टर नहीं बदला जायेगा । मैंने अपने जवाब में कहा है कि तदानुसार, बोन्द जल सेवाएं मण्डल, भिवानी, तथा जल सेवाएं मण्डल, भिवानी के कुछ क्षेत्र जोकि महम निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग हैं उनको अलग करेंगे । हम माननीय साथी का इलाका नहीं बदल रहे हैं और न ही हैडक्वार्टर बदल रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इसमें इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आयेगी । यह एक कोपरेशनल बात है जो सरकार की समझ में आई है इसलिए इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पहले बोंद डिस्ट्रीब्यूटरी और भिवानी सब-डिवीजन है वे वही रहेंगे या बदल दिये जायेंगे ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने माननीय सदस्य श्री भारद्वाज के जवाब में भी बताया है। मैं माननीय सदस्य चौधरी रणबीर सिंह महेन्द्रा जी को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो एगजिस्टिंग सब-डिवीज़नस और डिवीज़नस हैं उनमें हम केवल इतना ही परिवर्तन कर रहे हैं कि

जहां पर टेलेन्ट और हैड्स हैं वे महम के क्षेत्र में पड़ते थे और उन्हें इनके साथ जोड़ने से ऑपरेशनल प्रॉब्लमज़ थी इसलिए केवल उस इलाके को ही हम निकाल रहे हैं । इसके अलावा न तो हम डिवीजनस खत्म कर रहे हैं और न ही बदल रहे हैं ।

Inspection of Jails

***860. Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of jails in the State togetherwith the total number of inspections/raids conducted by concerned authorities of State and the unlawful activities noticed or material seized in such inspection/raids since April, 2007 till date ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : दिनांक 1-4-2007 से 29-2-2008 की अवधि के दौरान राज्य की विभिन्न जेलों पर भिन्न-भिन्न अथॉरिटी द्वारा 464 निरीक्षण/जेल विजिट की गई। इन निरीक्षणों के दौरान कई अनियमितताएं नोटिस में आई और जहां आवश्यकता हुई वहां कानूनी व अनुशासनिक कार्यवाही की गई। इस अवधि के दौरान राज्य की विभिन्न जेलों पर निरीक्षणों के दौरान 39 मोबाईल फोन बरामद हुए। अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे पास 19 जेल हैं जिनमें 2 सैन्ट्रल जेल भी शामिल हैं । यह 19 जेलों का जिक्र जो हमने जो जवाब दिया है उसमें होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसके लिए मैं आपके माध्यम से सदन से और आपसे क्षमा याचना करता हूं ।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार के नोटिस में है कि जेलों के अन्दर से अपराधियों ने आपराधिक गतिविधियां चलाई हुई हैं और लोगों से फिरौतियां भी मांगी जा रही हैं । इसके अलावा क्या हरियाणा प्रदेश की सभी जेलों के अन्दर सैलफोन ऑपरेट न हो सकें इसके लिए सैलफोन जैमर्ज़ लगाये जा रहे हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं अपने काबिल दोस्त की तारीफ करूंगा कि कम से कम उन्हें प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिंता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था हो इसके लिए प्रदेश के हर काबिल नागरिक को इसकी चिंता करनी चाहिए ताकि प्रदेश के अन्दर और जेल के अन्दर या बाहर से कोई भी अपराध न हो। न प्रदेश के मुखिया, न प्रदेश के मुखिया के बेटे का, न ही प्रदेश के किसी और व्यक्ति का संरक्षण हो । अध्यक्ष महोदय, रोहतक की जेल का उदाहरण आपके सामने है क्योंकि रोहतक आपका पुराना जिला रहा है । एक समय में ऐसा हुआ करता था और यह सर्वविदित भी है कि कृष्ण पहलवान से जेल के अन्दर मिलने कौन जाया करता था और जेल के अन्दर से किस प्रकार से फिरौती मांगी जाती थी । अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के आदेशानुसार हमने राज्य के कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, भिवानी, कैथल और गुड़गांव में स्थित जेलों में मोबाईल फोन जैमर्ज़ लगाये हैं । इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिए हैं कि जिन जेलों में अभी तक मोबाईल फोन जैमर्ज़ नहीं लगाये गये हैं उनमें भी जल्दी से जल्दी मोबाईल फोन जैमर्ज़ लगाये जायें । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक मोबाईल फोन जैमर लगाने पर 45 से 50 लाख रुपये की राशि खर्च होती है । मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि चाहे ये मोबाईल फोन जैमर कम्पनियों के माध्यम से लगवायें जायें चाहे सरकार अपने खाते में से यह पैसा दे और जिन जेलों में मोबाईल फोन जैमर नहीं लगे हैं उनमें भी

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

मोबाईल फोन जैमर लगाये जायें । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही माननीय सदस्य की चिंता से अपने आप को जोड़ते हुए मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कई ऐसे कुख्यात अपराधी भी थे जब उन्हें कई बार पेशी पर ले जाया जाता था तो कई वारदातें हुआ करती थीं। कई बार ऐसा हुआ कि बंगलौर से कुख्यात अपराधियों को जो किसी अगुवाई के काण्ड के अन्दर संलिप्त थे डबवाली के अन्दर मुकद्दमें दर्ज करके लाये गये और अगले दिन फरार हो गये और फिर वर्षों तक वे एक पूर्व मुख्यमंत्री के फार्म हाऊस पर रहे । इसकी बाकायदा वीडियो रिकार्डिंग भी है । इसलिए यह भी चौधरी भपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सुनिश्चित किया और उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट चलाया जिसकी कुल लागत होगी 1375 लाख रुपये और इसके तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिन जेलों में बहुत डेंजरस प्रिजनर्ज हैं जिनसे पूरी सोसायटी को खतरा है और ट्रांजिट से कहीं वे भाग न सकें और कोर्ट के अन्दर भी कोई वारदात न हो तो उसके लिए सरकार ने यह किया कि उनकी गवाही भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वहीं पर हो सके और इसके लिए हमने टैण्डर्ज भी फाईनालाईज कर लिए हैं और इसके लिए हम 25 स्टूडियोज मुख्तलिफ जेलों में बनायेंगे और 39 वीडियो स्टूडियोज हरियाणा की अदालतों के अन्दर बनायेंगे । इस पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमानत: 1375 लाख रुपये की लागत आयेगी। इस सारी प्रक्रिया को भी इस वर्ष के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा । इस बात को लेकर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार बहुत चिंतित है । सवाल के जवाब में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि 464 इंस्पैक्शन्ज किये गये । ये 464 इंस्पैक्शन्ज इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार इस मामले में कितनी गम्भीर है । जहाँ-जहाँ लोग दोषी पाये गये, चाहे वे सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वे कैदी थे, जहाँ-जहाँ कानून का उल्लंघन हुआ है वहीं पर हमने कड़ी कार्यवाही की है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि जैमर्स लगाये गये हैं लेकिन जैमर्ज लगे होने के बावजूद भी अभी तक जेलों में सैलफोन ऑपरेट हो रहे हैं । वे किस की मिलीभगत से हो रहे हैं ? क्या जेल अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे हैं? क्या सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक है कि जहाँ-जहाँ जैमर्ज लगे हुए हैं, वहाँ जैमर्ज लगने के बाद सैलफोन पर किसी प्रकार का कोई सिगनल नहीं आना चाहिए । जैमर्स लगाये ही इसलिए जाते हैं कि किसी प्रकार का कोई सैलफोन सिगनल न आये । जहाँ तक कार्यवाही का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में हमने इस बारे में एफ०आई०आर० दर्ज करवाई है । एक अधिकारी को सस्पैंड कर दिया गया है और दो अधिकारियों को वहाँ से ट्रांसफर कर दिया है । इसी प्रकार से एक और वाकया कुरुक्षेत्र में हुआ था । वहाँ पर भी हमने धारा 221, 120 of Section 54 of Prisons Act के तहत एफ०आई०आर० दर्ज करवाई है । गुड़गाँव में भी एफ०आई०आर० नं. 511, दिनांक 29.12.2007 को दर्ज करवाई गई है। ऐसी सब जगह जहाँ हमने एफ०आई०आर० दर्ज करवाई हैं वहाँ जो भी दोषी पाया जायेगा चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कैदी हो, उन सबसे सख्ती से निपटा जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार इस बात को लेकर बहुत चिंतित और गम्भीर है कि एक भी दोषी व्यक्ति जो समाज और प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा है उसके लिए हरियाणा में ढिलाई की कोई जगह नहीं होगी । इसी वजह से 1999 से 2005 के बीच में जो लोग सरकार के संरक्षण के अन्दर सैलफोन ऑपरेट करते थे,

आज वे लोग हरियाणा को छोड़ कर भाग चुके हैं या जेलों की सलाखों के पीछे हैं और उनकी जगह भी वहीं पर है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पुराने समय की बात की है लेकिन मैं तो इस समय की बात कर रहा हूँ । अभी कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र की जेल के बारे में आई०जी० प्रिजन का स्टेटमैंट आया था कि कुरुक्षेत्र जेल से 2007 में ही फिरौती मांगी गई थी । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो जैमर्ज लगाये गये हैं क्या वे सभी कम्पनियों के सैलफोन को जाम कर सकेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, दो पृथक प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछे हैं । कुरुक्षेत्र की जेल के मामले को लेकर हमने पुलिस स्टेशन थानेसर में ऐरिंग ऑफिशियल्स के खिलाफ एफ०आई०आर० नं० 22, दिनांक 17.1.08 को अंडर सैक्शन 221, 120 बी० ऑफ सैक्शन 54 ऑफ दा प्रिजन एक्ट, 1894 के तहत दर्ज करवाई है । इन सबके खिलाफ एक्शन लिया गया है । अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक जैमर्ज का प्रश्न है, जैमर जेल में सिगनल को जैम करता है न कि कम्पनियों के सैलफोन को जैम करता है । जो भी जैमर्ज लगाये गये हैं और जिन जगहों पर लगाये जाने हैं वहाँ पर भी हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर प्रकार के सैलफोन का सिगनल जैम हो । अगर फिर भी माननीय सदस्य को किसी विशेष कम्पनी का सिगनल पकड़े जाने की शिकायत मिली हो तो वे माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर भिजवा दें, हम यह सुनिश्चित कर लेंगे और जैमर्ज को रिथैक भी करवा लेंगे ।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि जेलों के अन्दर से फिरौती की बात होती थी उसके बारे में मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह काम ज्यादातर वर्ष 2000 से 2005 के शुरू तक होता रहा है । उस पीरियड की स्थिति क्या है, कितने लोगों को ऐरैस्ट किया गया, कितने लोग विदेशों में हैं और कितने लोग देश में हैं, क्या मंत्री जी इसका ब्यौरा देंगे ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छी बात कही है। इस बात को पूरा प्रान्त जानता है और यह बात सर्वविदित भी है कि एक समय ऐसा था जब जेल के अन्दर जो अपराधी थे वे सैलफोन ऑपरेट करते थे और सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त था । कृष्ण पहलवान की मैंने चर्चा भी की । अध्यक्ष महोदय, यह आपका पुराना जिला भी रहा है इसलिए यह आप भी जानते हैं कि उस समय के मुख्यमंत्री और उसके बेटे रोहतक की जेल में कृष्ण पहलवान से मिलने जाते थे । इसी प्रकार से डिम्पी, जिसकी बाद में चण्डीगढ़ में हत्या कर दी गई थी उनको एक केस में प्रोडक्शन वारन्ट पर ले गये थे। वह कुख्यात अपराधी था और उसने अपहरण किया था। उसको प्रोडक्शन वारन्ट लेकर डबवाली लाया गया था और फिर वहां से उसको भगा दिया गया था। वह पूर्व मुख्यमन्त्री के निवास पर भी रहा। इसके पक्के सबूत भी हैं। अब तो उसकी हत्या कर दी गई है। इसी प्रकार से और बहुत सारे अपराधी थे। स्पीकर सर, जिस दिन चौधरी भूपेन्द्र सिंह की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में अपना कार्यभार सम्भाला उसके 24 घण्टे के भीतर ही वे सभी अपराधी तड़ीपार हो गये थे और हरियाणा की सीमा से बाहर चले गये थे। या तो वे जेलों की सलाखों के पीछे हैं या फिर उनसे हरियाणा छुड़वा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था वे कुख्यात अपराधी 40 के करीब थे जो पुलिस के साथ एनकाउंटर के अन्दर मारे गए हैं जिन्होंने कई काण्ड किये थे और पुलिस पर हमला कर गुण्डागर्दी की कोशिश की । मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की नीति पूर्णतया स्पष्ट है।

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमन्त्री और उनके बेटों के बारे में माननीय मन्त्री महोदय बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। जो प्रश्न मैंने पूछा है वह वर्ष 2007 के बारे में है। Jail is becoming safe and heaven for criminals. हमारी सरकार के समय की बात नहीं है बल्कि वर्तमान सरकार के समय की बात है।

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें पूछे गये सवाल का पूरा जवाब नहीं आया है। सवाल यह था कि कितने कुख्यात अपराधी जेलों से टैलीफोन किया करते थे, फिरौतियां मांगते थे ? अध्यक्ष महोदय, सुरजेवाला साहब ने केवल दो आदमियों के नाम लिये हैं, कृष्ण पहलवान और डिम्पी। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे और लोग भी हैं ? उनके नोटिस में कितने ऐसे अपराधी थे और वे अपराधी किस-किस के साथ जुड़े हुए थे ? यह सारी बात क्लीयर हो जाए कि कौन-कौन आदमी थे और किस-किस से जुड़े हुए थे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े स्पष्ट तौर पर जवाब दिया है। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, मैंने पूरी जानकारी और वस्तुस्थिति से सदन को अवगत करवा दिया है कि वे किस के बेड़े के अन्दर बैठते थे। मैं माननीय सदस्य को बता देता हूं कि वे चौटाला साहब के बेड़े में बैठते थे और उनके फार्म हाउस के अन्दर बैठते थे यह बात सब लोग जानते हैं। उनकी वीडियो सी०डी० और फोटो भी है जिसमें डॉ० सीता राम जी भी बैठे हुए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैंने इन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है इसलिए यह उसको व्यक्तिगत तौर पर न लें (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, डॉ० सीता राम जी के बारे में यह कोई टिप्पणी नहीं थी और न ही उनके बारे में कोई इल्जाम है कि इनके किसी अपराधी से सम्बन्ध हैं इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही अच्छे और सज्जन आदमी हैं इनके आगे जो बैठते हैं वे उनके साथ बैठे हुए थे वे गलती से उस फंक्शन में गए हुए थे (विघ्न)

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पब्लिक प्लेस को व्यक्तिगत तौर पर न लें। अपराधी किस्म के लोगों से हमारा कोई नाता नहीं है। पब्लिक मीटिंग में कोई भी किसी भी किस्म का व्यक्ति बैठा हुआ हो सकता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, उनके इनकी पार्टी के लोगों के साथ सम्बन्ध थे। माननीय सदस्य बहुत ही अच्छे और सही आदमी हैं इनके आगे जो बैठे हैं ये उनको पहचान सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठने से पहले आगे-पीछे देखना पड़ता है।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय बड़े अथॉरिटी से कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमन्त्री और उनके बेटों का संरक्षण उनको प्राप्त था। क्या उनके खिलाफ माननीय मन्त्री जी कार्यवाही करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के गठन के फौरन बाद ही चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार आने के बाद एक कॉप्रहैंसिव चार्जशीट बनाई गई है जिसमें जिन लोगों का अपराधियों से लिंक हैं उसका एक पूरा चैप्टर उसके अन्दर है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने वह सारी चार्जशीट केन्द्रीय जांच ब्यूरो के हवाले कर दी है जिस पर इस समय जांच चल रही है।

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे जेल के बारे में इन्होंने कहा कि 464 जेलों का निरीक्षण हुआ और जेलों के निरीक्षण के दौरान इन्होंने स्पष्ट रूप से माना है कि अनियमितताएं हुई। सरकार की तरफ से भी इस बात को माना गया है कि अनियमितताएं हुई हैं। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर अनियमितताएं हुई हैं और वर्तमान सरकार ने अपनी इस असफलता को माना है तो क्या वर्तमान मन्त्री और मुख्यमन्त्री जी उन उच्च अधिकारियों जिनकी अनियमितताओं में संलिप्तता पाई गई है, उनके खिलाफ भी इन्कवायरी करवाएंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया है कि स्पैसिफिकली प्रश्न यह था कि क्या कोई सैलफोन का यूज जेलों में मिला है, मैंने इसके जवाब में कहा है कि 'हां'। 3-4 जेलों के अन्दर जहां-जहां सैलफोन का यूज मिला है और जिस-जिस से मोबाईल रिकवर हुए हैं, उसके बारे में हमने जवाब में लिख दिया है कि उन सबके ऊपर एफ०आई०आर० दर्ज करवाई गई है जो ऑफिशियल दोषी पाए गए हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है और यदि उन्होंने कोई कोताही की है तो उनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करवाई गई और डिसीप्लनरी एक्शन भी लिया गया है । जो इस सरकार के आने से पहले अनियमितताएं हुई हैं उस बारे में सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टीगेशन एजेंसी इन्कवायरी कर रही है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सदन में चर्चा हो रही है इस बारे में सबको मालूम है कि उस समय ऐसे अपराधियों को छोड़ा गया था जो कि कातिल थे । बाद में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्ज के द्वारा उन अपराधियों को दोबारा से जेलों में लोका गया । जब हमारी सरकार बनी और बनते ही मैंने जो पहली प्रैस कांफ्रैंस की थी, उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जो भी अपराधी किस्म के तत्व हैं वे या तो मुख्य धारा में आ जाएं या भारत छोड़ कर चले जाएं ।

श्री अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया उस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के वक्त में जिन्होंने अपराध किए थे उनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की जाती थी । उस वक्त की सरकार में जो बदमाश थे वे लोगों के ट्रैक्टर, मोटर साईकल और ट्रक आदि की चोरी कर लेते थे और जब लोग थानों में उनके खिलाफ अपनी एफ०आई०आर० दर्ज करवाने जाते थे तो उनकी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की जाती थी । जब अधिकारियों से इस बारे में कहा जाता था तो वे कहते थे कि हमें ऊपर से आर्डर है । अध्यक्ष महोदय, उस वक्त की सरकार की मंशा थी कि अगर एफ०आई०आर० दर्ज नहीं होगी तो उनके वक्त में क्राईम का ग्राफ बहुत नीचे आ जाएगा । लेकिन उनके इस अलिखित आर्डर की वजह से हमारे लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जिन लोगों की जो मोटर साईकल, ट्रक और ट्रैक्टर चोरी हुए हैं उनको आज भी डर है कि कहीं वे बदमाश लोग चरस, अफीम आदि की तस्करी न करते हों या वे अपराधी लोग किसी को उनकी गाड़ियों के नीचे कुचल कर मार न दें ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बात कहते हुए जो चिन्ता जाहिर की है वह बहुत ही वाजिब है । पिछली सरकार के पांच वर्षों के राज में यह अलिखित हिदायतें थीं कि कोई भी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं करी जाए ताकि क्राईम की फीगर को फर्जी करके दिखाया जा सके । जब मौजूदा कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तब हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यह स्पष्ट तौर पर सभी को कह दिया था कि किसी पर कोई दबाव नहीं है और अगर कोई कॉग्नीजेबल

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

अफैंस है तो उसकी एफ०आई०आर० जरूर दर्ज करें । यह हमारी सरकार की डिक्लेयरड नीति है कि जहां कहीं भी कॉग्नीजेबल अफैंस होगा वहां पर हम पर्चा दर्ज करते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह कहना चाहूंगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत या दरख्वास्त लेकर आएगा हम उसको एग्जामिन करवा लेंगे । अगर इनके क्षेत्र के लोगों की तरफ से लिखित में उस बारे में कोई शिकायत हमारे विधायक साथी के पास है तो ये हमें दे दें, उस बारे में हम एफ०आई०आर० भी दर्ज करवा देंगे ।

श्री अर्जन सिंह : धन्यवाद जी ।

To Develop a Housing Board Colony

***942. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a Housing Board Colony at Circular Road, Bhiwani near Dadri gate ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Yes Sir.

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, भिवानी सर्कुलर रोड़ के पास हाऊसिंग बोर्ड कालोनी बनने जा रही है । लेकिन उस कालोनी के साथ ही बाल्मिकि बस्ती है । वह बस्ती वहां पर बहुत सालों से बनी हुई है और वहां पर बहुत सालों से गरीब लोग रह रहे हैं । अगर यह हाऊसिंग बोर्ड की कॉलोनी उस बस्ती से सट कर बनती है तो वहां से जो रास्ता निकलता है वह अवरूद्ध हो जाएगा । इसकी वजह से वहां पर न तो पानी की और न ही सीवरेज की लाईन डाली जा सकेगी और वे लोग वहां पर अपनी ट्रैक्टर ट्राली नहीं ले जा पाएंगे। यहां तक कि अगर किसी ने उस बस्ती में मकान बनाना है तो वहां पर वह ईंटों का ट्रक भी नहीं ले जा सकेगा । इस हाऊसिंग बोर्ड की कालोनी बनने की वजह से लोगों के लिए वहां पर कोई भी रास्ता नहीं रहेगा जिससे उनको बहुत ही दिक्कतों का समाना करना पड़ेगा । क्या सरकार उन बाल्मिकि बस्ती वालों के लिए 20 या 25 फुट चौड़ा रास्ता वहां पर छोड़ेगी ताकि उन लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े ? इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में दूसरा प्रश्न लाना चाहूंगा कि भिवानी में नई और पुरानी जो हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनिज़ हैं, वे बहुत ही लो-लाईनिंग हैं । वहां पर अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो वे कॉलानीज़ जलमग्न हो जाती हैं । अध्यक्ष महोदय, इसलिए वहां के लोगों का मत है कि अगर यहां पर भी यह कॉलोनी बन जाएगी तो वह बाल्मिकि बस्ती भी स्लम बन जाएगी । भिवानी में जो ड्रेनेज़ हैं उनमें पहले ही बहुत कंजैशन है । क्या मंत्री जी इस कालोनी को भिवानी के बाहर जहां बहुत सी जमीन खाली पड़ी हुई है वहां पर शिफ्ट करेंगे ? अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे पैसे का सद्-उपयोग होगा । मंत्री जी यह भिवानी के लोगों की बहुत बड़ी तकलीफ है । अगर यह कॉलोनी भिवानी से बाहर बन जाए तो इससे वहां के लोगों की तकलीफ दूर हो जाएगी ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो पृथक प्रश्न पूछे हैं। इनका पहला प्रश्न बाल्मिकी बस्ती को लेकर है। यह प्रश्न इनका सीधा मेन प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर भिजवा दें। मगर मैं इनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार की नीति इस बारे में बड़ी स्पष्ट है कि हमारे गरीब भाईयों की जो बस्तियाँ हैं उनका रास्ता कोई रोक न पाए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी बस्तियों का वाजिब रास्ता जरूर रहे। हम यह बिल्कुल

नहीं होने देंगे कि ऐसी कोई बस्ती भी हरियाणा में हो जिसके लिए कोई रास्ता न हो। यह असंभव है। यह हम पहले सुनिश्चित कर लेंगे कि हम कितने फुट रास्ता छोड़ सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह मामला महकमा ऐग्जामिन कर लेगा और जो रीजनेबल चौड़ाई का रास्ता होगा वह हम छोड़ेंगे। जहां तक इनका दूसरा प्रश्न है इन्होंने यह पूछा है कि क्या इसकी लोकेशन चेंज करने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 11.44 एकड़ यानी तकरीबन साढ़े ग्यारह एकड़ जमीन हाऊसिंग बोर्ड ने हरियाणा हैंडलूम एंड हैन्डीक्राफ्ट कोरपोरेशन से दिसम्बर 2006 में ली थी। इसमें 144 लो-इन्कम ग्रुप, 206 मीडियम इन्कम ग्रुप, और 140 हाई इन्कम ग्रुप डबल स्टोरी हाउसिज को बनाने के लिए हमने यह स्कीम फ्लोट की थी। यह स्कीम 2 जुलाई, 2007 से लेकर 31 जुलाई, 2007 तक थी। हमें इसका ओवरवेलमिंग रिसपोंस भी मिला था। हमने इसका ड्रा जनवरी, 2008 में निकाल भी दिया है। यह स्कीम पूरी है। इस स्कीम के तहत 1910 लाख रुपये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिज पर खर्चा आएगा। और 553 लाख 76 हजार रुपये का खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पर आएगा। Everything stands sanctioned. Sir, we have also proposed to complete this Scheme by May, 2009. So, location cannot be changed at this juncture.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की एक नीति है कि बड़े-बड़े शहरों में जहां आवश्यकता है वहां चाहे हाई-इन्कम ग्रुप्स हों, चाहें मीडियम इन्कम ग्रुप्स हों या चाहे लो-इन्कम ग्रुप्स हों, उनके लिए आवास बोर्ड या अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से आवास की व्यवस्था की जाएगी। यह हमारी सरकार की नीति है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आवासीय बोर्ड और प्राईवेट को-ऑपरेटिव सैक्टर भी जिन जिन शहरों में बहुत ज्यादा आबादी बढ़ी है विशेषकर फरीदाबाद में वहां पर आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं लेकिन फरीदाबाद की स्थिति के बारे में मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात लानी होगी कि वहां पर तकरीबन तीस हजार से भी ज्यादा झुग्गी झोंपड़ी डिवैल्प हो गयी है। यह उनके लिए तो तकलीफ है ही साथ ही बाकी शहर के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए आवासीय बोर्ड या दूसरी एजेंसीज के माध्यम से एकमुश्त तौर पर लो इन्कम ग्रुप्स के लिए अलग कॉलोनीज की व्यवस्था सरकार करेगी ताकि समस्या का समाधान हो सके ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आशियाना किसी भी व्यक्ति को देना खास तौर से इस प्रान्त में देना इस सरकार की प्राथमिकता का केन्द्र बिन्दु है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में भी हाऊसिंग बोर्ड की तरफ से 809 डुपलैक्स टाईप हाउस और 27 हाउस चार स्टोरीज के लिए फ्लोट करने जा रहे हैं और फ्लोट की प्रक्रिया भी इस समय प्रोग्रैस में है। अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा में इस समय भिन्न भिन्न शहरों में 4384 मकान बनाए जा रहें हैं और इन पर 457 करोड़ 2 लाख रुपये खर्चा होगा। जहां तक झुग्गी झोंपड़ियों के लिए आवासीय योजना बनाने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इनका यह एक पृथक प्रश्न है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम या दूसरे अन्य प्रोग्राम्ज जैसे जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन के तहत 100 करोड़ रुपयों की राशि भारत सरकार से फरीदाबाद के लिए मंजूर हो चुकी है। इसके अलावा इस प्रकार की अन्य हरियाणा सरकार की स्कीम्ज और भारत सरकार की भी जो स्कीम्ज हैं, उनमें भी हम इन सारी अनऐप्रूव्ड कॉलोनीज या झुग्गी झोपड़ी की डिवैल्पमैंट के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। फिर भी माननीय सदस्य अपना सुझाव इस बारे में लिखकर भिजवा दें, हम उस पर गंभीरता से विचार कर लेंगे।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो हाउसिंग बोर्ड का कार्यक्रम बना है यह तो बहुत अच्छी स्कीम बनी है इससे प्रत्येक गरीब आदमी को भी मकान मिल जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जमीन ऐक्वायर करने में प्रौब्लम आएगी और उसमें 1-2 साल लग जाएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि जहां पर आर जोन में जमीन नहीं है वहां पर प्राइवेट लोगों से जमीन लेकर गरीब लोगों के लिए मकान बनाने का प्रावधान करेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड अपने सीमित साधनों के अंदर फ्लैट बनाता है जैसा हमने भिवानी में किया है। यहां हैंडलूम कॉर्पोरेशन से हमने जमीन 10 लाख रुपये प्रति एकड के भाव से ले ली है। इसी प्रकार से जहां जमीन ऐक्वायर करने की जरुरत पड़ेगी, वहां फ्लोर रेट नीति बड़ी स्पष्ट है । परन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस सरकार के गठन के बाद इस समय जो स्कीम हमारे अंडर कंसीड्रेशन है वह पंचकूला में 170 मकान की, कुरुक्षेत्र में 300 मकान ट्रिपल स्टोरी और करनाल में 195 ट्रिपल स्टोरी , सोनीपत में 112 ट्रिपल स्टोरी और 544 डबल स्टोरी, मतलौडा में 82 सिंगल स्टोरी, बहादुरगढ़ में 354 ट्रिपल स्टोरी और 89 सिंगल स्टोरी, भिवानी में 490 दो मंजिल, गुड़गांव में 259 नाइन मंजिल और 404 ट्रिपल स्टोरी, धारूहेड़ा में 552 डबल मंजिल, फरीदाबाद में 809 डुप्लैक्स और 27 मकान फोर स्टोरी बना रहे हैं। इसके अलावा हुडा के साधन सीमित हैं क्योंकि हुडा कर्वआउट करके जमीन देता है फिर भी उन्होंने बहादुरगढ़ में 6.7 एकड़, हिसार में 18 एकड़ जमीन कालोनी बनाने के लिए दी, जींद में 10 एकड़, कैथल में 7.5 एकड़ जमीन, सिरसा में 22.7 एकड़ जमीन और एच.एस.आई.डी.सी. बावल में 5 एकड़, गढ़ी में 10 एकड़ जमीन दी है और इसमें हम हाउसिंग कालोनीज विकसित करेंगे और अध्यक्ष महोदय, जहां जरुरत पड़ी, वहां ऐक्वायर भी करेंगे।

श्री बचन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 11 जून, 2006 को सफीदों में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और हुडा सैक्टर की घोषणा करके आए थे और उस पर अमल भी हुआ। वहां पर 7,8 और 9 सैक्टर की घोषणा कर दी गई और सैक्शन -4 के तहत नोटिस भी लगा दिया गया । उसके बावजूद भी वहां एस.डी.एम और अन्य उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई और उन्होंने रिपोर्ट दी कि सैक्टर -7 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बननी चाहिए । क्या मंत्री जी इस बारे में जानकारी देंगे कि डेढ़ साल से ज्यादा समय बीत गया है लेकिन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो कि वहां के लोगों की मांग है, नहीं बनी है।

Mr. Speaker : It is very difficult to reply.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि अगर वहां पर मांग है, सफीदों क्योंकि ग्रोइंग शहर है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुडा वहां जैसे ही अधिग्रहण समाप्त कर लेगा, वहां हुडा से जमीन अलॉट करवा के उसी लौट में प्रयास करेंगे कि वहां भी हाउसिंग बोर्ड कालोनी बनाई जाए। इस बारे में यदि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है तो अब तो यह हमारे लिए कानून की तरह है और उसे हम जरुर लागू करेंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि तीन चार साल पहले करनाल में हाउसिंग बोर्ड का एक एस्टेट मैनेजर कोई गौतम था जिसने कि बहुत बड़ा स्कैंडल किया था । उसने वहां हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट बुक किए और लोगों से फुल एंड फाइनल पेमेन्ट ले ली। उसने एक जाली रसीद बुक भी छपवा रखी थी, उससे रसीद भी काटकर देता

गया । मैं मंत्री जी से यह नहीं जानना चाहूंगी कि उस कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, किन्तु यह अवश्य जानना चाहूंगी कि जिस भोलीभाली जनता ने यह समझकर कि सरकारी अफसर है, पैसे जमा करा दिए, फुल एंड फाइनल पेमेन्ट जमा करा दी क्या उनको सरकार द्वारा फ्लैट दिये जाएंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक पृथक प्रश्न है इसलिए इस समय मेरे पास इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्या को यह जरुर कहना चाहूंगा कि आप इस बारे में हमें लिखकर भिजवा दें । पूरी जानकारी सहित मैं उत्तर भेज दूंगा । अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोई प्राईवेट आदमी सरकार के नाम पैसा लेकर ठगी करता है तो सरकार उस पैसे को रिफण्ड कैसे करें । शायद यह संभव नहीं है । शायद माननीय सदस्या भी इस बात से सहमत होंगी ।

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, वह गवर्नमैंट एम्पलाई था ।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, this is a preliminary reply. I do not know the facts and it does not relate to the question in hand. She should write to me and I will give her a full reply.

श्री हरि राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि झज्जर और बहादुरगढ़ शहरों में पिछले 20-25 सालों से गरीब गाढ़े लुहार रह रहे हैं, क्या सरकार उनको भी प्लॉट या मकान बनाकर देगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है । बागड़ी गाढ़े लुहार हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और उनको भी रहने का एक समान अधिकार है । जहां तक हाउसिंग बोर्ड की स्कीम का प्रश्न है, यह एक ओपन एंडिड स्कीम है इसके लिए कोई भी व्यक्ति दरख्वास्त दे सकता है । इसमें लोअर इन्कम ग्रुप, मिडिल इन्कम ग्रुप और हायर इन्कम ग्रुप के मकान होते हैं । इसी प्रकार हुडा में इकोनोमिकली वीकर सैक्शन के लिए मकान बनाये जाते हैं। उनके लिए ये भाई अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त देने के बाद जो बाकी की कैटेगरीज को मकान दिए जाते हैं उनके साथ इनकी दरख्वास्त को भी कंसीडर किया जायेगा ।

Construction of Bus Stands

***917. Dr. Sushil Indora :** Will the Transport Minister be pleased to state the number of bus-stand-constructed or being constructed during the last three years togetherwith the number of those Bus Stands which have not started functioning even after the completion of construction work ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : पिछले तीन वर्षों के दौरान 6 बस अड्डे निर्मित किये गये तथा इस समय 7 बस अड्डों पर निर्माण का कार्य चल रहा है। पिछले तीन वर्षों में ऐसा कोई भी बस अड्डा नहीं है जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हो तथा प्रयोग न हो रहा हो।

डॉ. सुशील इन्दौरा: स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने छोटे से शब्दों में अपना जवाब दे दिया । बस अड्डे इस लिए बनाये जाते हैं कि जनता को सुविधा मिले और उस सुविधा के साथ उनका प्रयोग हो । लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा आया है कि कुछ बस अड्डे ऐसे हैं जिनका उद्घाटन हो गया और वे

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

बनकर भी कम्पलीट हो गये उसके बावजूद भी अब तक वे बस अड्डे जनता के लिए प्रयोग नहीं हुए हैं जैसे जुलाना, बवानी खेड़ा, उचाना, इसराना, रानियां, राजौंद आदि ऐसे कई बस अड्डे हैं जो पिछले कई सालों से प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं । इनका प्रयोग में न आना सरकार के वित्तीय प्रबन्धन पर बड़ी भारी चोट है क्योंकि पैसा तो जनता का ही है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन बस अड्डों को कब तक जनता के प्रयोग में लाया जायेगा ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में तीन साल पीछे के टाईम में बस अड्डों के बारे में पूछा था कि पिछले तीन सालों में कौन से बस अड्डे प्रयोग में नहीं लाये गये हैं । इसके बारे में मैंने अपने जवाब में पूरा विवरण दे दिया है । जुलाना, उचाना के बस अड्डे पिछले तीन सालों से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से ऐसे ही पड़े हैं । कुछ बस अड्डे वर्ष 1982 में, 1985 में और कुछ पिछली सरकार के समय में बनाये गये थे । कम से कम 15 ऐसे बस स्टैण्ड हैं जो शहरों के साथ न होने के कारण पब्लिक के प्रयोग में नहीं आ सके । सरकार इस बारे में अब सोच रही है कि इन बस अड्डों को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाये या किसी दूसरे विभाग को दिया जाये ताकि पब्लिक का आना जाना शुरू हो जाये । 15 ऐसे बस अड्डे हैं जो तीन साल से पहले पूरी तरह से प्रयोग में नहीं आ पा रहे हैं ।

डॉ० सुशील इन्दौरा: स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछले कई सालों से बस अड्डे प्रयोग में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि शहर से उनकी दूरी है । क्या वे उदाहरण द्वारा बता सकते हैं ? क्योंकि रानियां का बस अड्डा तो बिल्कुल शहर के अन्दर है क्या वे इस बारे में सर्वे करवायेंगे ताकि सर्वे के आधार पर यह पता चल सके कि वे किन कारणों से प्रयोग में नहीं आ पा रहे हैं और इन बस अड्डों का सुचारू रूप से प्रयोग किस प्रकार किया जा सके ?

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने रानियां बस स्टैण्ड का जिक्र किया है कि इस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं है । इस बस स्टैण्ड का इस्तेमाल हो रहा है और अगर कोई ऐसी बात माननीय सदस्य के नोटिस में हैं तो वे लिखकर भिजवा दें । इस मामले में जरूर तहकीकात की जाएगी । 15 बस स्टैण्ड जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उनकी लिस्ट अलग है इनमें रानियां का नाम नहीं है ।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा करनाल बस स्टैण्ड के बारे में हर सैशन में सवाल लगता है । मैं अब यह नहीं पूछूंगी कि यह बस स्टैण्ड कब तक बनेगा ? हम जब भी इस बस स्टैण्ड के बारे में पूछते हैं तो हमें कहा जाता है कि इस पर कंसल्टैंटस के टैण्डर्ज हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि कंसल्टैंटस के टैण्डर्ज अभी तक हुए हैं या नहीं ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की यह बात ठीक है कि उनका करनाल बस स्टैण्ड का प्रश्न कई बार हाऊस में लगा है । मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि करनाल में बस स्टैण्ड आज भी बना हुआ है लेकिन सरकार ने महसूस किया है कि यह बस स्टैण्ड शहर

के बीच में पड़ता है जिसकी वजह से लोगों को काफी प्रोब्लम रहती है । सरकार का इस बस स्टैण्ड को शहर से बाहर शिफ्ट करने का प्रपोजल है । इसके लिए हुड्डा के सैक्टर में जमीन का पोजैशन ले लिया गया है । पहले एक ऐसा विचार हुआ था कि जो पुराने बस स्टैण्ड बनते जा रहे थे उनसे हटकर एक नये बस स्टैण्ड का सैम्पल लाया जाए । जैसा कि हरियाणा और बातों में पूरे देश में अग्रणी है उसी प्रकार एक नए मॉडल का बस स्टैण्ड करनाल में बनाने का सरकार का विचार है इसके लिए कंसल्टैंटस बुक किए गए हैं और उनको काम भी दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि थोड़ा इंतजार करें, करनाल में बस स्टैण्ड अवश्य बनेगा और वह बस स्टैण्ड हरियाणा का अद्वितीय बस स्टैण्ड होगा।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या कंसल्टैंटस के टैण्डर्ज हो गए हैं ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि कंसल्टैंटस के टैण्डर्ज हो गए हैं ।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, तावडू में बस स्टैण्ड के लिए 1996 में पत्थर रखा गया था लेकिन वह आज तक नहीं बन पाया और वहां के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । वहां प्राइवेट बसिज खड़ी रहती हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि तावडू में बस-स्टैण्ड बनाने बारे सरकार का कोई विचार है या नहीं ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि तावडू के अंदर न कोई बस स्टैण्ड है और न ही कोई बस स्टैण्ड बनाने बारे सरकार का विचार है ।

श्री नरेश मलिक: अध्यक्ष महोदय, 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी सांपला में गए थे और वहां बस स्टैण्ड बनाने की घोषणा करके आए थे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस स्थिति में हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सांपला में बस स्टैण्ड बनाएंगे ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि सांपला में बस स्टैण्ड बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने की होगी, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे पास मुख्यमंत्री महोदय की ऐसी कोई घोषणा नहीं आई है और जैसे ही यह घोषणा हमारे पास आएगी तभी उस पर विचार किया जाएगा ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सांपला बस स्टैण्ड के लिए जमीन ऐक्वीजिशन की प्रोसीडिंग्स चल रही है ।

श्री नरेश यादव: अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सैशन में मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि नांगल चौधरी में जमीन ऐक्वायर करके बस स्टैण्ड बनाया जाएगा तो मैं अब माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नांगल चौधरी में बस स्टैण्ड बनाया जाएगा या नहीं ?

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से माफी चाहूंगा कि नांगल चौधरी में बस स्टैण्ड बनाने का कोई प्रपोजल सरकार का नहीं है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में परिवहन व्यवस्था और तंत्र पूरी तरह से सुदृढ है । फरीदाबाद जिला आबादी की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है, वहां पर सैक्टर 12 में सामान्य बस अड्डा बनाया जाना है जिसकी शायद मार्च में नींव भी रखी गई थी । पिछले विधान सभा में सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने माना था कि फरीदाबाद में बस अड्डा बनाया जायेगा और मंत्री जी किसी कार्यक्रम में फरीदाबाद आये भी थे उस समय भी वहां बस अड्डा बनाने की घोषणा करके आये थे कि जल्दी ही बस अड्डा बनाने का काम शुरू करवा देंगे । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर बस अड्डा बनाने का प्रोविजन भी है और मंत्री जी ने कमिटमैंट भी किया हुआ है इसलिए क्या वहां पर मंत्री जी बस अड्डा बनाने की कृपा करेंगे और बनायेंगे तो कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा। पहले मैं पहले वाले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि सांपला के अंदर बस अड्डा बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है । दूसरा मेरे साथी महेन्द्र प्रताप जी ने फरीदाबाद के अंदर नया बस अड्डा बनाने की मांग की है । फरीदाबाद शहर दिल्ली के नजदीक बहुत अच्छा शहर है । इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हम फरीदाबाद में करनाल की तरह बहुत आधुनिक बस अड्डा बनाना चाह रहें हैं जिसको हम जल्दी ही फाईनल करने जा रहे हैं ।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो फरीदाबाद में नया बस अड्डा बनाने की मांग की है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में बस अड्डे के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रही थी । यह बहुत पुराना विवाद जमीन उपलब्ध न होने की वजह से चला आ रहा था । यदि मुझे सही याद पड़ता है तो 8-9 महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद में बस अड्डा बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए स्वयं मीटिंग ली थी तथा फरीदाबाद में सचिवालय के पास बस अड्डा बनाने के लिए जमीन कर्व आऊट करवा कर ट्रांसपोर्ट विभाग को दिलवाई है। यह जमीन बेशकीमती जमीन है और यहां पर बी.ओ.टी. बेसिज पर बहुत अच्छा बस अड्डा बनाया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 साल से गुडगांव और फरीदाबाद में बस अड्डे के लिए जमीन का विवाद चला आ रहा था । इन दोनों शहरों में बस अड्डे बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इंटरवीन करके कई सौ करोड़ रूपये की जमीन अधिग्रहण करके इन दोनों जगहों पर बस अड्डे बनवाने के लिए दिलवाई है और असंभव काम को संभव किया है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कलायत हल्का आज विकास की राह पर अग्रसर है लेकिन यह बस अड्डे से जुड़ा हुआ प्रश्न है इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कलायत के अंदर बस अड्डा बनाने के लिए 26 अक्तूबर, 2006 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था । वहां पर बस अड्डा बनाने के लिए जमीन नैशनल हाई वे नं० 65 पर है जो कि बस अड्डा बनाने के लिए बहुत अच्छी साईट है । वहां पर बस अड्डे के लिए जो जमीन थी उसमें मिट्टी भी डल चुकी है और मीटिंग्ज भी हो चुकी हैं लेकिन बस अड्डे का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है । इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वहां पर कब तक बस अड्डे का काम शुरू होगा ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा और माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि कलायत में पहले बस अड्डे के लिए जो नींव रखी गई और जो साईट बस अड्डे के लिए सिलैक्ट की गई

थी वह गलती से दूसरे प्लॉट की सिलैक्ट हो गई लेकिन जब वहां नींव रखने के बाद कार्य शुरू करने लगे तब आब्जैक्शन आ गया कि वह साईट हमारे विभाग की नहीं है । लेकिन उस मसले को अब हमने बड़ी मुश्किल से सुलझाया है और हमने उस जगह का पोजैशन ले लिया है । जमीन की फिलिंग भी कर दी गई है और जल्दी ही वहां पर बस अड्डा बनाना शुरू कर देंगे ।

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बस अड्डे शहर से दूर बनाये गये हैं उनका प्रयोग नहीं हो रहा है । जैसे कि इसराना का बस अड्डा शहर से दूर बना दिया गया जिसके कारण उसका प्रयोग नहीं हो रहा है । सरकार गोहाना में भी शहर से दूर नया बस अड्डा बनाने जा रही है इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कहीं गोहाना के बस अड्डे का भी वही हाल न हो जो इसराना के बस अड्डे का हो रहा है ।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इसराना के बारे में तो ये कह सकते हैं कि वहां पर बस स्टैण्ड शहर से दूर पड़ता है इसलिए वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है । मगर जहां तक गोहाना की बात है तो इसकी चिंता वे न करें क्योंकि गोहाना में इस बस स्टैण्ड ऐसी साईट पर ही बनायेंगे जहां पर उसका ठीक इस्तेमाल हो सके ।

Construction of Transport Training Institute at Garhi Padla

***843. Sh. Shamsher Singh Surjewala :** Will the Transport Minister be pleased to state :—

(a) whether Haryana Government and Ashoka Leyland Company have jointly decided to construct a Transport Training Institute at Garhi Padla, District Kaithal ;

(b) whether Gram Panchayat Garhi Padla had donated 14 acres of agriculture land for the construction of this project ; and

(c) the time by which project is likely to be started /completed, together with the total amount to be spent on this project ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) :

(क) जी हां, श्रीमान् जी।

(ख) जी हां, श्रीमान्जी। ग्राम पंचायत, गढ़ी पाडला ने 10 एकड़ शामलात भूमि उपहार के रूप में दी है। चार एकड़ अतिरिक्त भूमि तबदील करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) परियोजना प्रारम्भ कर दी गई है तथा यह अगले वित्त वर्ष 2008-09 में पूर्ण होने की संभावना है। इस परियोजना पर 16.95 करोड़ रुपये का खर्चा संभावित है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रोजैक्ट में कम्पोनैंटस क्या-क्या बनाये जायेंगे । जो ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट बनेगा उसमें किस-किस प्रकार की ट्रेनिंग का प्रावधान होगा ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि परिवहन विभाग में जो हैवी और लाईट व्हीकल ड्राईवर्ज हैं वे कम्पलीटली ट्रेंड ड्राईवर नहीं हैं जिस कारण बहुत से एक्सीडैंट्स हो रहे हैं जिसके कारण बहुत सी जान-माल का नुकसान हो रहा है । इन सब कारणों को देखते हुए सरकार ने महसूस किया कि हरियाणा प्रदेश में कम से कम तीन ड्राईवर ट्रेनिंग सैन्टर्ज़ खोले जायें जो कि क्रमश: बहादुरगढ़, रोहतक और कैथल में खोले जायेंगे । जो भी भविष्य में ड्राईवर बनना चाहेगा उसको इन ट्रेनिंग सैन्टर्ज में से लाईसैंस लेना पड़ेगा । उसको पहले इन ड्राईवर ट्रेनिंग सैन्टर्ज में से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी । जो व्यक्ति इन ट्रेनिंग सैन्टर्ज से ट्रेनिंग लेगा उसे ही लाईसैंस मिलेगा और उसको ही गाड़ी चलाने का अधिकार होगा । इसके साथ-साथ हमने टैस्टिंग सैन्टर बनाने का भी फैसला किया है । कई केसिज़ में हमने यह देखा कि कई बार एक्सीडैंट ड्राईवर की गलती से नहीं होता बल्कि गाड़ी में कमी भी कभी-कभी एक्सीडैंट का कारण बन जाती है । इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि गाड़ी की, स्पेयर पार्ट्स और दूसरे जो पार्ट्स हैं उनकी भी प्रॉपर टैस्टिंग होनी चाहिए । इसके लिए हमने टैस्टिंग सैन्टर बनाने की भी योजना बनाई जिसमें हरेक गाड़ी को एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रॉपरली चैक करके उसको दुरूस्त किया जायेगा और अगर उसके किसी पार्ट को बदलना जरूरी होगा तो उसको भी बदल दिया जायेगा ।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन ट्रेनिंग सैन्टर्ज में ड्राइवर्ज के अलावा क्या कण्डक्टर्स और परिवहन विभाग की वर्कशाप के दूसरे कर्मचारियों के लिए भी ट्रेनिंग की क्लासिज़ और होस्टल का भी प्रबन्ध किया जायेगा ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि इन ट्रेनिंग सैन्टर्ज में सिर्फ ड्राइवर्ज के लिए ही ट्रेनिंग दी जायेगी और जहां तक कण्डक्टर्स का सम्बन्ध है तो कण्डक्टर्स और दूसरे कर्मचरियों के लिए किसी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती । इसके अतिरिक्त होस्टल बनाने की योजना भी सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही होस्टल की व्यवस्था भी कर दी जायेगी । अगर उसमें कुछ कैंडीडेट्स ऐसे होंगे जो दूर से आकर दाखिला लेंगे तो उनके रहने की व्यवस्था भी कर दी जायेगी ।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस गांव ने इस परियोजना के लिए 14 एकड़ जमीन दी है उस गांव को इससे क्या लाभ होगा ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह एक पृथक प्रश्न है । इस प्रकार की बात मेरे नोटिस में नहीं है । इसके बारे में वे लिखकर भिजवा दें । इस बारे में इनको उचित जवाब भिजवा दिया जायेगा ।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमने फाईल पर यह निर्णय लिया हुआ है कि ड्राईवर ट्रेनिंग स्कूल के लिए जिस गांव द्वारा भूमि दी जायेगी वहां के बच्चों को बगैर कोई पैसा चार्ज किए उस ड्राईवर ट्रेनिंग स्कूल में सरकार द्वारा निशुल्क ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा ड्राईवर्ज ट्रेनिंग स्कूल के अन्दर क्लास 3 और 4 के जो लोग लगेंगे उनमें भी सरकार द्वारा उस गांव के बच्चों को नौकरी के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी ।

Construction of Roads

***965. Shri Naresh Yadav :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads:—

1. Mohlara to Ramchanderpura via Rattakalan;
2. Rattakalan to Kalwari;
3. Gokalpur to Bihali via Begpur Ateli;
4. Bhilwara to Nawdi Aashram (upto Narnaul to Rewari Road);
5. Mahasar to Ragunathpura (upto Girdharpur Mor);
6. Karia to Bochria; and
7. Saria to Shahpur Doyam;

(b) if so, the time by which the construction work of the above said roads is likely to be started ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Only road listed at Sr. No. 7 is being considered for construction.

(b) Time cannot be specified as the construction of road involves the clearance of a manned railway crossing from the Ministry of Railways, Government of India. Road work can be taken up only after such clearance.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मैंने जिन 7 रोड्ज का जिक्र किया है उनको प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जाये क्योंकि ये सभी सड़कें अटेली और महेन्द्रगढ़ को राजस्थान से जोड़ती हैं । इनकी लम्बाई भी बहुत ज्यादा नहीं है कोई एक किलोमीटर की है कोई डेढ़ किलोमीटर लम्बी है और कोई दो किलोमीटर लम्बी है ।

श्री अध्यक्ष: नरेश यादव जी, इन रोड्ज के बारे में मंत्री जी जवाब दे चुके हैं । अब आपका स्पैसिफिक प्रश्न क्या है?

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, अब मेरा स्पैसिफिक प्रश्न यह है कि इन रोड्स को जरूर बनाया जाये ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र को लेकर सरकार पहले ही चिंतित है क्योंकि यह क्षेत्र हमारा दक्षिण हरियाणा का वह क्षेत्र है जिसको पिछली सरकार ने विकास से महरूम रखा । अध्यक्ष महोदय, इसीलिए सरकार द्वारा 1888 लाख 38 हजार रूपये 54.87 किलोमीटर लम्बी विभिन्न सड़कें बनाने के लिए प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत दिये गये हैं । इन सड़कों में सरकार ने मुख्यत: अटेली खेड़ी रोड़ से राजस्थान बॉर्डर तक, नारनौल से

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

मंढाना राजस्थान बॉर्डर तक, महेन्द्रगढ़ से चामदेड़ा, भालखी, दोंगड़ा, सिलारपुर, अटेली रोड़ और अटेली से कनीना रोड, रेवाड़ी से नारनौल जो कि स्टेट हाईवे नम्बर 26 है और यहाँ से खोड, सिलारपुर, सीमहा, दड़ौली अहीर से लेकर स्टेट हाईवे नं० 17 तक की सड़कें बनाने के लिए मंजूर की हैं । इसके अलावा 2 सड़कें और हमने अटेली विधानसभा क्षेत्र की मंजूर की हैं । एक सड़क है अकोली से खुराना राजस्थान बॉर्डर तक जो कि 2.20 किलोमीटर लम्बी है जिस पर 17 लाख 31 हजार रुपये का खर्चा आयेगा और दूसरी सड़क शोभापुर से राजस्थान बॉर्डर तक की है जो कि आधा किलोमीटर लम्बी है जिस पर 5 लाख 55 हजार रुपये खर्चा आयेगा और जो सड़क हमने कहा है कि अंडर कंसीड्रेशन है इस पर भी 266 लाख रुपये अकेली पर खर्चा आयेगा । जो बाकी सड़कों की श्री नरेश यादव जी ने चर्चा की है उन सबकी पहले से ही कनैक्टिविटी है और जो मेरे माननीय साथी इन सड़कों की ड्यूअल कनैक्टिविटी चाहते हैं वह इस समय सम्भव नहीं है ।

श्री अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यमुनानगर में जो बी.के.डी. रोड़ है जो कि 100-150 गाँवों को जोड़ती है और जिस पर स्टोन क्रशर जोन भी पड़ता है, क्या मंत्री जी इसको बनवाने का कोई प्रावधान करेंगे ? इस पर ट्रक बहुत ज्यादा चलते हैं और बाहर की गाड़ियाँ भी बहुत आती हैं । यह रोड़ बिल्कुल टूटा पड़ा है । इस पर 40 किलोमीटर यू.पी. का एरिया भी आता है । अध्यक्ष महोदय, इस पर दूसरी स्टेट्स से ट्रक आते हैं और दूर-दूर तक बदनामी होती है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस सड़क को बनाया जाये ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न तो आप पहले भी पूछ चुके हैं ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बी.के.डी. रोड का नाम लिया है पहले भी इसका जिक्र हुआ था और माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल ठीक है कि इस रोड़ पर बहुत ट्रैफिक चलता है । मुख्य मंत्री जी ने निर्णय किया है कि इसको बी.ओ.टी. स्कीम के तहत बनाया जायेगा ।

श्री अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह कब तक बनकर तैयार हो जायेगी, क्या मंत्री जी इस बारे में कोई आश्वासन देंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, बी.ओ.टी. का अपना सिस्टम है, उनकी अपनी प्रणाली है, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि इसको जल्दी ही बनाया जायेगा ।

Construction of Roads

***943. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road between village Puranpura and Dhana Ladanpur in Bhiwani constituency ?

Power Minister (Sh. Randeep Surjewala) : No. Sir.

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, हमारे खजाने लबालब भरे पड़े हैं, फिर क्या कारण है कि हमारी ये छोटी-छोटी सड़कें नहीं बन पा रही हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर काफी पैसा सड़कें बनाने के लिए सरकार ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा के अन्दर तकरीबन समान तौर पर पैसे का वितरण हुआ है।

Mr. Speaker : Now the question hour is over.

नियम 45(I) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Providing Employment through Foreign Employment Bureau

***821. Dr. Sushil Indora :** Will the Labour & Employment Minister be pleased to state:—

(a) the names of the places where the Foreign Employment Bureau are located in Haryana;

(b) the numbers of persons to whom the employment has been provided by the above said Bureau so far; and

(c) the number of employment seeking persons registered with the Bureau so far ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री ए०सी० चौधरी) :

(क) विदेश रोजगार ब्यूरो का कार्यालय पंचकूला में स्थित है।

(ख) ब्यूरो द्वारा अब तक 11 प्रार्थियों को दुबई नौकरी के लिए भेजा गया।

(ग) बाहर जाने के लिए अब तक 7064 प्रार्थियों ने ब्यूरो के पास पंजीकरण करवाया है।

Fuctioning of Haryana Rural Development Authority

***967. Sh. Radhey Shyam Sharma Amar :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the Haryana Rural Development Authority will start its functioning ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की स्थापना एवं गठन अधिसूचना दिनांक 29-10-2007 के द्वारा किया गया है और इस प्राधिकरण ने हरियाणा पंचायत भवन, सैक्टर 28, चण्डीगढ़ में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

Recurring loss of Revenue

***811. Dr. Sita Ram :** Will the Industries Minister be pleased to state :-

(a) whether the land for setting up SEZ has been acquired in the State, so far; and

(b) if so, the recurring loss to be incurred to Government in the form of land revenue ?

उद्योग मन्त्री, (श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) :

(क) हां श्रीमान्।

(ख) सरकार को भूमि राजस्व के रूप में कोई हानि नहीं हुई है।

वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, discussion on the Budget Estimates for the year 2008-09 will resume Yesterday, Shri Ram Kumar Gautam was on his legs. Now, he may continue his speech on Budget Estimates for the year 2008-09.

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी सी इम्पोर्टैन्ट बात हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मैं बजट पर ही शुरू कर लेता हूं। जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है उसके बारे में जो बातें मेरी समझ में हैं वह मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। मैं कोई अर्थ-शास्त्री तो नहीं हूं लेकिन जितना बजट मेरी समझ में आया है मैं अपनी बात यहां रखने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे काबिल वित्त मंत्री चौधरी बिरेन्द्र सिंह जी ने पेश किया है उसको पढ़ कर पता चलता है कि डैफिनेटली वे बहुत ही काबिल आदमी हैं। भगवान की दया है कि वे पॉलिटिक्स में सही मौके पर आ गए लेकिन हम बूढ़े हो कर इस पालिटिक्स में लेट आए हैं। हमने साथ ही साथ पढ़ना शुरू किया था लेकिन 58-59 साल की उम्र में जाकर मेरा इसमें संसर बैठा जबकि भाई बिरेन्द्र सिंह जी ने 30 साल की उम्र में ही कच्चे काट लिए। (विघ्न) नैचुरली वे पॉलिटिक्स में ज्यादा मेच्योर हैं।

एक आवाज : गौतम साहब, आज इनका जन्म दिन भी है इसलिए इनको जन्मदिन की बधाई भी दे दीजिए।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको जन्मदिन की बधाई भी दे देता हूं। (विघ्न)।

एक आवाज : इनका जन्मदिन तो कल है आज तो चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी का जन्मदिन है।

श्री राम कुमार गौतम : मैं इनको कल भी जन्मदिन की बधाई दे दूंगा और आज तो मैंने इनको बधाई दे ही दी है। मैं चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी को भी जन्मदिन की बधाई देता हूं। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले समय मेरे कुछ भाईयों ने मेरे खिलाफ ऐसी बातें कही और बजट वाले दिन ऐसे-ऐसे इल्जाम लगाए कि गौतम तो कांग्रेस पार्टी में जाने वाला है, कांग्रेस के पे रोल पर है, मुझे कांग्रेस पार्टी का ऐजैंट कहा। अध्यक्ष महोदय, बी०जे०पी० मेरी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है। हिन्दुस्तान में दो ही पार्टीज हैं एक कांग्रेस पार्टी और एक बी०जे०पी० पार्टी और बाकी की जो पार्टीज हैं वे लूट-खसोट के गिरोह हैं। लोग जानते हैं कि इनमें से किसी का खेल कुछ भी नहीं है। वे सदस्य जो यहां पर बैठे हैं सारे मेरे भाई हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा वे सभी मेरे भाई हैं और मैं उन सबका दिल से रिगार्ड करता हूं। जो संविधान बनाने वाले हमारे बुजुर्ग थे और जो संविधान बना था उसकी कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डा० भीम राव अम्बेडकर थे और हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी के पिता श्री को भी यह सौभाग्य प्राप्त है कि वे उस संविधान सभा के मैम्बर हुआ करते थे (विघ्न) मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हमारे भाई जिनको आज दलित समाज कहा जाता है सोशल स्ट्रक्चर में उनको अधिकार दिये गये और वे आज एम०एल०ए०, एम०पी०, आई०ए०एस०, डॉक्टर, आई०पी०एस०, एच०सी०एस० आदि बड़ी-बड़ी सर्विसिज में आते हैं। ये किसी से कम नहीं थे। ये मार्शल बिरादरी के हमारे भाई थे। अध्यक्ष महोदय, जब मोहम्मद गजनवी ने हमारे देश पर हमला किया था तो इस मार्शल बिरादरी ने उसके एक बार नहीं कई बार दांत खट्टे कर दिये थे। इतिहास गवाह है जब कोई हार जाता है तो उसको पता नहीं क्या-क्या कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि रावण सारी सृष्टि में सबसे विद्धान था, सबसे काबिल था लेकिन लोग उसको आज राक्षस कहते हैं क्योंकि वह हार गया था। यह काम इनके साथ भी हुआ। They were actually defeated और वे कमजोर पड़ गए और शिडयूल्ड कॉस्ट और शिडयूल्ड ट्राईब्ज़ में आ गए। अब यह बात ये बेचारे भाई समझते ही नहीं हैं। महज एम०एल०ए० और एम०पी० बनने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां पर इनके बीज का नाश कर दिया गया है। इनका नेता जो है वह अपने समय में इन भाईयों का 10,000 का बैकलॉग छोड़ कर चला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार का बजट स्टडी कर रहा था तो उसमें मैंने देखा की एस०सी० और बी०सी० के लिए 21 प्रतिशत बजट रखा है। जब इनके नेता का राज था उस समय में यह बजट था ही नहीं, वह इनको लोगों में गिनता ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, अगर असैम्बली में और एम०पी० के लिए इनका रिजर्वेशन नहीं होता तो वह इनकी शक्ल को देखना ही पसन्द नहीं करता। He hates them. फिर भी पता नहीं इन भाईयों की क्या मजबूरी है जो ऐसी पार्टी में बैठे हुए हैं। मैं तो इनको कहता हूं कि ये मेरी तरह अच्छे काम करें तो जनता इनको जरूर मेरी तरह चुनकर भेजेगी, चाहे बुढ़ापे में मौका देगी पर मौका जरूर देगी क्योंकि जनता आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखती है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मुझे एक शब्द बहुत अखरा कि मेरे किसी भाई ने कह दिया कि राम कुमार गौतम एजैंट है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि मैंने आज तक किसी से एक भी पैसा नहीं लिया है। मैं उस आदमी को जो घर की इज्जत लूटवाता है और जो पैसा लेकर काम करता है या करवाता है, एक ही मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी ईमानदारी से इन बेचारे भाईयों को कहता हूं कि भाईयों मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी भी मायावती और कांशी राम जी को भी बुरा नहीं कहा है जो कि यह कहा करते थे कि "तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार।" तिलक में तो हम आ जाते हैं। (विघ्न) अब जाटों के बारे में पता नहीं क्यों कह दिया वे तो बेचारे वैसे ही पिछड़ी जाति में आते हैं। (हंसी)

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मायावती पहले तो यह कहती थी कि "तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार।" लेकिन जब सत्ता में आना था तो उस समय उसने यह नारा दिया था, "तिलक, तराजू और तलवार, इनकी बोलो जय जयकार।"

श्री राम कुमार गौतम : मैंने अपने जीवन काल में कभी कांशीराम और मायावती की बुराई नहीं की। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि गौतम तू फंलाने के खिलाफ बोला, तू फंलाने के खिलाफ भी बोला लेकिन तू कांशीराम या मायावती जो रोजाना गाली देते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता। मैंने उनको कहा कि जिन लोगों की लड़ाई वे लड़ रहे हैं मैं भी उन्हीं की लड़ाई लड रहा हूं, हम भी गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन तरीका अलग-अलग है। हमारे पास बैठे हुए भाईयों ने भी बहुत सी बातें कही हैं लेकिन मैं तो इन भाईयों का भी बुरा नहीं मानता हूं मैं इनसे प्यार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने दैनिक जागरण नाम से एक अखबार की वैबसाईट पढी थी। मैं कहना चाहता हूं कि जिस आजादी को पाने के लिए हमारे बजुर्गो ने लड़ाई लडी और जो आजादी हमें मिली है उसको कायम रखने के लिए हमारे जैसे चन्द लोग ही लगे हुए हैं लेकिन इनसे भी बहुत बड़ा रोल प्रैस का है। उनका छोटा रोल नहीं है। लेकिन प्रैस का कोई आदमी अगर मनचाही बात लिख दे तो ठीक नहीं है क्योंकि उसको न तो समझ है और न ही उसको हरियाणा की राजनीति का ज्ञान है। मैं इन भाईयों को इतना इशारा करना चाहता हूं कि प्रैस का रोल बहुत बड़ा रोल है। प्रैस ने ही आगे आने वाला राज बनाना होता है। प्रैस ही यह बताती है कि अगर 36 बिरादरियों का राज होगा तो वह कैसा होगा। अध्यक्ष महोदय, यह सब प्रैस पर बड़ा भारी डिपैंड करता है। अगर प्रैस वाले यह निर्णय कर लें कि करप्शन को जड़ मूल से मिटाना है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि करप्शन खत्म हो जाएगा। कोई ताकत रोक नहीं सकती । कैसे रोक देगी ? सबकी आंखें हैं सबको पता है कि कौन कैसे और कितने पैसे खा रहा है और हरियाणा में कितने ओफिसर्ज भ्रष्टाचारी हैं, जात पात का ढोंग रचाते हैं और मनचाही जगह पर वे पहुंच जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात हर आदमी जानता है। लेकिन मैं प्रैस वाले भाईयों को ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं जो उनके बारे में कहना चाहता हूं उसको उनको समझ जाना चाहिए। मेरे बारे में यह कहना कि गौतम तो भोंपू है। और कभी यह कहना कि यह तो चौटाला की बुराई करता है, कभी चौधरी भजनलाल की बुराई करता है और कभी कभार यह हुडा साहब की बढ़ाई कर देता है और कभी कभार एक आध बार यह सरकार की बुराई भी कर देता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो कंस्ट्रक्टिव रोल है मैं जिस दिन असैम्बली में चुनकर आया था उसी दिन मैने ऐलान किया था कि मेरे लिए पहले देश है फिर प्रदेश और फिर बी०जे०पी० है।

श्री अध्यक्ष : फिर नारनौंद हल्का है।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, जब मैं पहली बार चुनकर आया था उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था और उस दिन मैंने मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दी थी। मैंने उनसे यह कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप यह न समझना कि आप कांग्रेस पार्टी से हो इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैंने कहा था कि मैं तेरे खून की इज्जत करता हूं, तेरे से प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि तेरे में देशभक्तों का खून है, तेरे दादा, तेरे पिता फ्रीडम फाईटर रहे हैं इसलिए तू अच्छा काम करियो और 36 बिरादरियों का भला करियो। अगर 36 बिरादरियों का भला करेगा, सबके लिए अच्छा करेगा तो हम तेरा साथ देंगे, इसमें पार्टी बीच में नहीं आएगी लेकिन अगर बदमाशी करेगा तो तेरे सबसे बड़े दुश्मन हम हैं। मुख्यमंत्री जी को याद होगा मैंने पहले ही दिन मुख्यमंत्री जी को यह कहा था। अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग मेरी

मुखालफत करते हैं। मेरी पार्टी वाले भी कह देते हैं लेकिन मैं तो जो अच्छी बात समझ में आती है उसको कह देता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक भाई अगर दुनिया को बेवकूफ बना रहा है और अगर मैं लोगों को यह न बताऊं कि ये आदमी डाकू है, शैतान है, बेबकूफ बना रहा है तो लोग कैसे समझेंगे। अध्यक्ष महोदय, फर्ज करो लोग आपकी इस सरकार से नाराज हो जाएं तो वे ऐसे ऐसे डाकू शैतान को फिर से चुन लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे लोगों को अगाह करना, उनको बताना जरूरी है कि ये जो लोग चीफ मिनिस्टरी की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग किसी के भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी भिवानी में एक प्रैस कांफ्रैंस की थी और जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा मैं शुरू रखूंगा क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि कई लोग गलत ट्रैक पर चले जाएं। अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह बात कहने की घड़ी नहीं है क्योंकि भजनलाल जी के पोते का देहान्त हो गया है लेकिन मेरे मन में कई ऐसी बातें हैं जिनको कहने से मैं रोक नहीं सकता । कल चौधरी भजनलाल जी का ब्यान आया था जो उन्होंने हिसार से दिया था। वे कहते हैं कि अब तो लोकदल की सरकार चल रही है इस बारे में मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि हम तो लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, और जन हित के कार्य करेंगे। उनका कहना था कि मेरा बेटा भी जन हित में लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कौन किसका भला करेंगे और कौन मौका देगा भला करने का ? जितनी लूटपाट करनी थी वह हो चुकी। अब तो वही बात है कि खेल खत्म और पैसा हजम क्योंकि खेल ही कुछ नहीं है। जिन बैकवर्ड क्लास के भाइयों ने उनको अपना खून पिलाया और 32 हजार अपनी वोट दी, उनको कहता था कि मैं नॉन-जाट का चैम्पियन हूं। 27 परसैंट जो रिजर्वेशन लागू हुई वह रिपोर्ट सारे देश में तो 1991 में लागू हुई लेकिन उसने हमारे प्रदेश में नहीं लागू होने दी । उस नॉन-जाट का नारा लगाने वाले ने उनका बीज मार दिया। 1995 में जाकर बड़ी मुश्किल से 27% रिजर्वेशन लागू की । छोटी नौकरियों में और बड़ी नौकरियों में, व अफसरों की नौकरियों में तो सारा छोड़ दिया। मुख्यमंत्री महोदय, आप इस सैशन के रहते लिस्ट निकलवाओ और देखो कि उस दौरान कितने बी०सी०ए० के भाई अफसर बने, पता लग जाएगा । यह पता लग जाएगा तो कोई उसको छुएगा भी नहीं । नॉन-जाट का कैसा चैम्पियन था, यह उनको पता लग जाएगा । क्या पंजाबी भाई भूल जाएंगे उनका तीन सीटों पर कब्जा खत्म कर दिया कालका, फतेहाबाद और टोहाना में कब्जा खत्म कर दिया । मात्र 100 में से 5 नौकरियां दी, वे कैसे भूल सकते हैं। भूलेंगे तो मैं याद दिलाऊंगा। जब तक सांस है तब तक याद दिलाऊंगा । इसी तरह से क्या ब्राह्मण भाई भूल जाएंगे ? उनका भी बीज मार दिया । 12 साल तक जब तक चीफ मिनिस्टर रहा उनको 3 या 4 से फालतू टिकट नहीं लेने दिये । किसी को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया । अगर कोई ब्राह्मण असल का बीज होगा तो नजदीक भी नहीं जाएगा । जाएगा तो मैं याद दिलाऊंगा । हमारे राम जी लाल जी साथ घूमते रहते हैं । वह देखते रहते हैं कि कौन सबसे बड़ा हाऊ है। उनको यह नहीं पता कि सबसे बड़ा हाऊ तो तुम्हारे पास ही बैठा है बैकवर्ड क्लास का नास करने वाला वही है । इसी तरह से उसने अग्रवाल 2, 3 या 4 से ज्यादा कभी नहीं बनाए । कहता है नॉन-जाट का चैम्पियन हूं। मेरे ताडे का कोई नेता नहीं। क्या नॉन-जाटनी के सारे बीज मर गए थे, जामने छोड़ दिये थे । सब जाम रखे थे। बड़े नेता तो बहुत थे पर वह आगे आने का मौका ही नहीं देता था । वह इतना खतरनाक बहरूपिया था कि हमारे जाट भाइयों को बहकाने उनके पास पहुंच गया । बनते ही हमारे जाट भाइयों को बहकाने लगा । मैं जाट हूं । हम जाट से बिश्नोई बने थे। है भी सच्ची बात । देसी खांड की जिसनै बान है तो वो अंग्रेजी क्यूं खाव । जाट का बीस और नोई । हमारे जाट कालेज में गया वहां कहने लगा कि मैं थारा भाई सूं। रेवेन्यू रिकार्ड निकलवा कर देख लो, मैं थारा भाई हूं। आपकी जितनी भी मांगे हैं बताओ, उनकी सारी मांगें मान भी ली और यूं सोची कि ये भाई भी नेता मान लेंगे। यह जो जाट कालेज के सामने एस०पी० का दफ्तर

[श्री राम कुमार गौतम]

चल रहा है, यह धर्मशाला के लिए दे दो। उन्होंने रिजैक्ट कर दिया और परवाना बांचने से इंकार कर दिया। फिर जाकर पंजाबियों को बहकाने लगा, कहने लगा कि मैं बहावलपुर का हूं। तुम भी रिफ्यूजी, मैं भी रिफ्यूजी। उनको भी बहका दिया और कुछ नहीं दिया। उनका भी बीज मार दिया। उसके बाद मुसलमान भाइयों के पास चला गया। उनको फरीदाबाद में बुला लिया। वहां एम०पी० बनने के लिए कहने लगा कि मेरा और तुम्हारा धर्म एक है। फर्क सिर्फ नाम का है। तुम भी मुर्दा गाड़ते हो, हम भी गाड़ते हैं। हम भी दफनाते हैं तुम भी दफनाते हो। इस तरह से उनको भी बेवकूफ बनाया। ब्राह्मणों को टिकट मिल जाता था उनका भी बीज मार दिया। करनाल की सीट से जितने नेताओं का आशीर्वाद लेकर चीफ मिनिस्टर बना, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चांद राम, डॉ. मंगलसेन और पंडित भगवतदयाल शर्मा और लाला बलवंत राय तायल जैसे उसने मार दिये। ये लोग कभी भूलेंगे नहीं, भूल भी जाएंगे तो मैं भूलण कोनी दूं। बहरूपियेपन की भी हद्द है। कुम्हार धर्मशाला में गया और कहने लगा कि भाइयों मुझे खुशी है कि मैं अपनी कौम में आ गया हूं। वहां कुम्हारों को कहने लगा कि मैं भी तुम्हारा भाई हूं तो कुम्हार कहने लगे कि तें क्यों गलत कहे हो, तें तो बिशनोई हो। तब कहने लगा कि भाई जात कभी जन्म से नहीं होती वह तो कर्म से होती है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : गौतम, साहब, आप और कितना समय बोलने के लिए लोगे क्योंकि उस दिन आप 34 मिनट बोल चुके हो।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समय और लूंगा। मैं सरकार का ध्यान बजट की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरी समझ में जो मोटी बात आई है वह यह है कि जो फोरैस्ट का बजट है वह 110 करोड़ रुपये का है। मैं यह समझता हूं कि यह बिल्कुल नाजायज बजट है। इसमें कहा गया है कि पांच करोड़ पौधे हर साल लगाये जाते हैं। कितने साल बीत गये। लगभग 10 साल से चल रहा है। आप वहां मौके पर जाकर देखिये सारे आंकड़े फ्रॉड हैं, फोरजरी है। जहां तक फूड सप्लाई विभाग की बात है इस विभाग को तो बन्द ही कर देना चाहिए क्योंकि गाँवों में राशन तो किसी को मिलता नहीं है या फिर वहां पहरेदार बिठाने चाहिएं ताकि अगर कोई राशन नहीं दे तो उसकी मरम्मत कर सकें। अध्यक्ष महोदय, कोआप्रेशन का बजट है यह 19 करोड़ रुपये का बजट है। इस बजट को और बढ़ाना चाहिए और गरीब लोगों के लिए ज्यादा लोनिंग का प्रावधान करना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी को जो लोन मिलता है वह या तो वक्त पर मिलता नहीं अगर मिलता है तो उसके लिए भी कमीशन देनी पड़ती है। गरीब आदमी तो चक्कर लगा-लगा कर मर जाता है। जहां तक पॉवर की बात है। पॉवर के लिए बजट 862 करोड़ 13 लाख रुपये मिला है यह बजट बहुत थोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, आज गांवों में पुरानी वायर बदलने के योग्य हो गई हैं। आज बिजली का सारा सिस्टम लड़खड़ा गया है। इसके कई कारण हैं क्योंकि बीच में ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार आई जिन्होंने लोगों को कहा कि बिजली के बिल न भरो मैं यो आया। जब लोग बिजली के बिल नहीं भरेंगे तो नेचुरली पैसा कहां से आयेगा और उसके बाद बेवकूफ बनाकर सी०एम० बनकर जिन लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे उनको गोलियों से भुनवाया। पॉवर के लिए यह बजट थोड़ा है। बिजली की ज्यादा से ज्यादा जनरेशन का इन्तजाम करना चाहिए और इन्फ्रास्ट्रैक्चर को बढ़िया से बढ़िया करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों के लिए बहुत थोड़ा बजट रखा गया है। स्कूलों की बिल्डिंग लगभग खराब पोजीशन में हैं। 10-10 एकड़ या 5-5 एकड़ में स्कूल बने हुए हैं। स्कूलों की बिल्डिंग इतनी खराब पोजीशन में हैं कि कोई भी मां-बाप अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते

और वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं चाहे वे प्राइवेट स्कूल एक कोठड़ी में ही क्यों न बने हों। अध्यक्ष महोदय, 10+2 स्कूल चाहे लड़कियों के लिए हों चाहे लड़कों के लिए हों, जितने होने चाहिएं उससे बहुत कम हैं। प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्कूलों के लिए बजट बढ़ाना चाहिए। एलीमैंट्री एजूकेशन में योगा कम्पलसरी करनी चाहिए क्योंकि एक बार योगा लागू हो गया तो बच्चे बीमार नहीं होंगे और प्रदेश से हैल्थ की प्रोब्लम खत्म हो जाएगी। हायर एजूकेशन के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है जो कि बहुत थोड़ा है, हमने मुख्यमंत्री महोदय से कई बार कहा कि हमारे नारनौंद और आस पास के गांवों की लड़कियां जब बस्ता उठाकर बसों में धक्के खाती जाती हैं तो हमारे लिए शर्म से डूब के मरने वाली बात हो जाती है । सारे गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर पहली बार मुख्यमंत्री महोदय को खाना खिलाया और उनसे एक मेन मांग की कि हमारे यहां लड़कियों के लिए एक कॉलेज और आई०टी०आई० बननी चाहिए। (इस समय सभापतियों की सूची में एक सदस्य आई०जी० शेर सिंह चेयर पर पदासीन हुए।) हम जब भी मुख्यमंत्री जी से हमारे यहां कॉलेज खोलने के बारे में पूछते हैं तो वे कहते हैं कि क्या करूं गौतम जी, बजट कम है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब पूरे हरियाणा प्रदेश में इतने कॉलेज खोले जा रहे हैं तो केवल हमारे इलाके के लिए ही बजट क्यों कम है ? हमारे यहां लड़कियों और लड़कों के लिए एक कॉलेज खोल दिया जाए तो हम आपके आभारी होंगें। सभापति महोदय, स्पोर्टस के लिए भी बहुत कम बजट रखा गया है। स्पोर्टस के मामले में हम आज दुनिया में बहुत पीछे हैं, हालांकि सरकार ने बनने के बाद कुछ स्टेडियम्स बनाए हैं लेकिन अभी भी हरियाणा में स्टेडियम्स की कमी है। स्टेडियम्स ज्यादा बनने चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दे सकें। सभापति महोदय, एक तरफ अर्बन डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट हैं और दूसरी तरफ टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट है। अर्बन इस्टेट सब जगह नहीं है इसलिए या तो सरकार कम्पलसरी कर दे कि जहां भी म्यूनिसिपल एरिया हैं चाहे क्लास सी० हो, चाहे क्लास बी० हो, यानि जहां भी म्यूनिसिपल कमेटियां बनी हुई हैं वहां अर्बन इस्टेट जरूरी हो और जब तक अर्बन इस्टेट नहीं बनती तब तक टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट वाले नोटिस देकर किसी का पीस आफ माइंड खराब न करें। जो भी अर्बन इस्टेट बन रहे हैं सरकार उसके लिए जमीन चाहे 20 लाख रुपये प्रति किला एक्वायर करें या 10 लाख रुपये प्रति किला एक्वायर करे लेकिन प्लाट का भाव 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार या 10 हजार रुपये भी गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए जो गरीब आदमी 1000 रुपये या 500 रुपये गज के हिसाब से प्लाट ले लेते हैं उनके लिए या तो कोई ऐसा अर्बन इस्टेट बनाया जाए जिसमें उनको स्पैशल रियायत हो और या जो कॉलोनियां बन चुकी हैं उनको रैगुलैराईज़ कर दिया जाए ताकि उनको भी राहत मिल सके। उन अनअथोराइजड कॉलोनियों को हटाने के लिए नोटिस न दिया जाए। सभापति महोदय, जहां तक लेबर एण्ड लेबर वैलफेयर की बात है तो अभी हमारे मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि हिन्दुस्तान में हरियाणा ही ऐसी स्टेट है जहां 3510/- रुपये हम अपने लेबर भाई को देते हैं लेकिन यह कहीं भी लागू नहीं है। ठेकेदारी प्रथा में लेबर को 2000/- रुपये प्रतिमास ही दिये जाते हैं चाहें तो इस बारे में विस मंत्री जी पता कर लें। जो पब्लिक हैल्थ में भी सरकार ने आदमी लगा रखे हैं उनको केवल 3 हजार रुपये प्रतिमाह ही देते हैं। फैक्ट्रियों में तो छोटे छोटे बच्चे लगा रखे हैं और 3500/- रुपये महीने की सैलरी किसी भी श्रमिक को किसी भी फैक्ट्री में नहीं मिल रही है इसलिए इसकी तरफ सरकार विशेष ध्यान दे और इसे सख्ती से लागू करवाये। इसमें बजट भी बढ़ाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, अब मैं वैलफेयर ऑफ एस०सी० एंड अदर बैकवर्ड क्लासिज के बारे में बात करना चाहूंगा कि इसमें 130

[श्री राम कुमार गौतम]

करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। 130 करोड़ रुपये इनके वैलफेयर के लिए बहुत थोड़ा है। हालांकि पहले वाली सरकार में तो इनके वैलफेयर के लिए न के बराबर बजट रखा जाता था। पिछली सरकार तो इन भाईयों के खिलाफ थी। उस समय एस०सी० भाईयों को गांवों में बसने नहीं दिया जाता था और तरह-तरह के जुल्म उन पर होते थे। यही कारण है कि पिछली सरकार के समय में एस०सी० भाई गांवों को छोड़कर चले जाते थे।

श्री सभापति : गौतम जी, आप क्या सुजैस्ट करते हैं ?

श्री राम कुमार गौतम : सभापति महोदय, मैं तो यही सुजैस्ट करता हूं कि वैलफेयर ऑफ एस०सी० एंड अदर बैकवर्ड क्लासिज के लिए बजट थोड़ा है, बजट बढ़ाना चाहिए। सभापति महोदय, एक दफा मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि सरकार इन भाईयों को दो-दो एकड़ जमीन खरीदने के लिए लोन देगी। यह स्कीम लागू भी की गई लेकिन थोड़ा बहुत लोन दिया गया और कई जगहों पर पैसा दिया भी नहीं गया। मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह से इस स्कीम को लागू किया जाये और कम से कम 5-5 एकड़ जमीन खरीदने के लिए इन भाईयों को लिबरल लोन बिना ब्याज के दिया जाना चाहिए या 100 साल के पट्टे पर जमीन दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इनको जो लोन दिया जाये उस पर सब्सिडी भी दी जानी चाहिए ताकि गरीब भाई भी ऊपर उठ सकें। यदि सरकार ऐसा करेगी तो जो अपोजीशन में जिन साथियों ने गलत पार्टी पकड़ रखी है वे अच्छे लोगों का साथ देंगे और मुख्यधारा में आ जायेंगे। सभापति महोदय, अब मैं वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन के लिए 653 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। यह पैसा ठीक है लेकिन इसमें कुछ बढ़ोत्तरी और करनी चाहिए। सभापति महोदय, मेरे हल्के में अनेक गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की बहुत समस्या है। मसूदपुर और डाटा गांवों में तो पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। मैं हर बार आवाज उठाता हूं कि मेरे हल्के के गांवों में पीने के पानी की बहुत समस्या है। सरकार इस तरफ ध्यान दे और वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन का बजट भी बढ़ाया जाये तभी जाकर सरकार हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कर पायेगी। सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि हमारे वहां पर एक ऐसा नया रजबाहा बना दिया जिसकी वजह से मसूदपुर गांव में पानी आना बंद हो गया। यह रजबाहा जिस अधिकारी ने बनवाया है उसके खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिए और इसे सुधारा जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को पानी की समस्या न हो। सभापति महोदय, हैल्थ सर्विसिज के बारे में कहना चाहूंगा कि हैल्थ सर्विसिज में नाम मात्र का बजट रखा गया है। आज के दिन ज्यादातर गांवों में किसी भी हैल्थ सैंटर में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। मेरे हल्के के बास गांव के हैल्थ सैंटर में डॉक्टर नहीं है। इस बारे में मैंने हैल्थ मिनिस्टर महोदया को कई बार बताया है और न ही वहां पर बिल्डिंग का निशान है। सभापति महोदय, छोटे-छोटे झोलाछाप डाक्टर जिनको किसी बीमारी का ज्ञान नहीं है वे बहुत पैसा कमा रहे हैं। कई लड़के आर०एम०पी० की नई-नई ट्रेनिंग लेकर आते हैं और आते ही सूआ लगाने का काम शुरू कर देते हैं। इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए सभापति महोदय, वूमन एंड चाइल्ड डिवैल्पमैंट के लिए भी बजट में बहुत कम पैसा रखा गया है। आज के दिन हमारी बेटियों की दशा काफी खराब है। आज कौन सी सदी का जमाना है, सारी दुनियां कहां से कहां चली गई है लेकिन हमारी बहन-बेटियां वहीं की वहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की सहूलियत हमारी बहन-बेटियों को अवश्य दी जाये कि किसी भी परिवार की बेटी को पैसे की दिक्कत की वजह से अपनी हायर लैवल की पढ़ाई बीच में न छोड़नी पड़े। इसके अतिरिक्त जो हमारी अनपढ़ महिलाएं हैं उनके लिए भी सरकार ऐसा इंतजाम अवश्य करे कि वे कम से कम चिट्ठी पढ़ सकें और अपने घर का हिसाब-किताब रख सकें। इसलिए बजट को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री सभापति : गौतम जी, आप कृपया वाईण्ड अप करें।

श्री राम कुमार गौतम : सभापति महोदय, एक बात मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जो वर्तमान बजट में रोड्ज और ब्रिजिज के लिए जो 620 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, यह बहुत ही थोड़ा है। पता नहीं यह वास्तव में थोड़ा है या हमें ही थोड़ा लग रहा है। पिछले बजट सैशन के दौरान वित्तमंत्री ने मुझे कहा था कि गौतम साहब तुम्हारी दो सड़कों को बनवाने की जिम्मेदारी तो मैं ले लेता हूं। सारी स्टेट के जो छोटे छोटे रोड थे वे सभी बन गये लेकिन जीन्द से हांसी का जो स्टेट हाईवे था वह अभी तक नहीं बना। बावजूद इसके कि इस सड़क को बनवाने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि इस रोड़ की मंजूरी हो गई है इसलिए यह बनेगा ही और माननीय वित्त मंत्री महोदय के द्वारा दो सड़कों को बनाने का जिम्मा लेने के बाद भी भगवान जाने हमारी यह सड़क अभी तक क्यों नहीं बनवाई गई। इसको भी टाल दिया गया । इसके अलावा हमारी एक सड़क थी सीसर से वाया भाटला-पेटवाड़, यह हमारी सबसे बड़ी मांग है। इस सड़क के बन जाने से आप सबके लिए भी सहूलियत हो जायेगी क्योंकि सीधे स्वॉरकी से सीसर भाटला-पेटवाड़ होकर नारनौंद और नारनौंद से उचाना होते हुए नरवाना तक यह एक ऐसी बढ़िया सड़क है लेकिन फिर भी इसको बनवाने की तरफ सरकार का ध्यान अब तक नहीं गया है। यह मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य के फाईनैंस मिनिस्टर द्वारा इसको बनवाने की जिम्मेदारी लेने के बाद भी यह नहीं बनी। दूसरी बात मैं ब्रिजिज के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे यहां जो खाण्डा का पुल है यह खाण्डा नहर पर नारनौंद से खाण्डा जाते वक्त आता है। नारनौंद से खाण्डा रोड पर नारनौंद की तरफ जो पहला पुल है वह बनवाना बहुत जरूरी है और एक बहुत बड़ी डिमाण्ड है। दूसरे राजली पुल से खानपुर होकर डाटा और राजली पुल से डाटा की तरफ गुराना से खानपुर रोड़ तक दोनों ही बहुत इम्पोर्टैंट रोड़ हैं। मैं इनको बनवाने के बारे में कई बार कह चुका हूं लेकिन ये भी अभी तक नहीं बने। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुन : सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलैक्शन होने के बाद की बात है जब डॉ० रघुबीर सिंह स्पीकर बने तो जो पास के गांव हैं उनमें स्पीकर साहब के गोत्री भाई रहते हैं तो वे कहने लगे कि अब तो हमारा भाई स्पीकर बन गया है अब तो हमारी सरकार है हमारा राज आ गया है। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा राज आ गया है यह बात तो ठीक है लेकिन तुम अपनी यह सड़क तो बनवा लो। लेकिन अब भगवान जाने कि वह सड़क कब बनेगी। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिला रहा हूं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि कम से कम ये जो इतनी इम्पोर्टैंट सडकें हैं इनको तो सरकार बनवाएगी ही। इसके साथ ही मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो खाण्डा नहर पर पुल बना हुआ है उस पर आने-जाने वाली गाड़ियां आमने-सामने से न टकरायें इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों द्वारा उस पुल पर रिटेनिंग वॉल बनाने की जो मांग की गई थी वह सरकार द्वारा रिटेनिंग वॉल बनाकर पूरी कर दी गई है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस पुल पर रिटेनिंग वॉल बनने से ही काम चलने वाला नहीं है रिटेनिंग वॉल बन जाने से ही पूरा फायदा लोगों को नहीं हुआ है क्योंकि यह पुल बहुत संकरा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से इस पुल को चौड़ा करने का भी अनुरोध करूंगा। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय के ध्यान में एक अति महत्वपूर्ण बात भी लाना चाहूंगा कि सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में संस्कृत विषय के लैक्चरर नहीं है। इस सरकार के आने से पहले पहली वाली सरकार के समय में जब भी स्कूलों को अपग्रेड किया जाता था तो संस्कृत के लेक्चरर की पोस्टें सभी स्कूलों में होती

[श्री राम कुमार गौतम]

थीं। इस बारे में शिक्षा मन्त्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संस्कृत प्राध्यापकों का शिष्ट मण्डल भी दो तीन बार मिल चुका है। उनको यही कहा जाता है कि जब किसी स्कूल में बच्चे संस्कृत विषय में दाखिला लेंगे तभी वहां पर संस्कृत के प्राध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। सभापति महोदय, जब स्कूल में प्राध्यापक ही नहीं होगा तो कोई बच्चा दाखिला कैसे लेगा। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि 10+2 के स्कूलों में बच्चों के दाखिलों से पहले ही संस्कृत विषय के प्राध्यापक होने चाहिएं तभी बच्चे संस्कृत विषय में दाखिला लेंगे और तभी हमारी संस्कृत भाषा का विकास होगा। यही संस्कृत भाषा हमारे ऋषियों की भाषा है और यही हमारे हिन्दुस्तान की पहली भाषा है जिससे अनेक भारतीय भाषाएं डवलप हुई हैं। दूसरी बात, संस्कृत टीचर बनने के लिए बहुत से लोगों ने छोटे-छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चे गुरुकुलों में दाखिल करवा दिये। कहीं किसी संस्कृत विद्यालयों में, कहीं रामरा के गुरुकुल में दाखिल करवा दिये। उनको इस बात का खतरा लगने लगा कि अगर ये बच्चे यहां पर रहे तो ये बेरोजगार बन जायेंगे। उन्होंने सोचा था कि अगर ये बच्चे ओ०टी० और शास्त्री कर जायेंगे तो संस्कृत टीचर लग जायेंगे। इसलिए चेयरमैन सर, ओ०टी० और संस्कृत के टीचर जरूर लगाने चाहिएं।

श्री सभापति : गौतम साहब, आप वाइंड अप करें।

श्री रामकुमार गौतम : सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब मोहम्मद गौरी, भारत पर हमला करता था तो वह अक्सर हार जाता था। मोहम्मद गौरी बहुत बार भारत से हारा है। उनको किसी ने यह बता दिया कि हिन्दुस्तान से जीतना तो बहुत आसान काम है। उसने पूछा कि कैसे आसान है ? उसको बताया गया कि यह देश धर्म का देश है। यहां लोग धर्म को बहुत मानते हैं और इस देश में उनकी कई माताएं हैं, जैसे भारत माता, गऊ माता और उनकी माता। जब लड़ाई शुरू हो तो गऊओं का च्यौणा छोड़ दो और ये हिन्दू लोग गऊओं पर हथियार नहीं उठायेंगे और ये हार जायेंगे। सभापति महोदय, उन्होंने गऊओं का च्यौणा छोड़ दिया और जो हमारे राजपूत राजा थे या और जो दूसरे हिन्दू राजा थे जो गऊ को अपनी माता समझते थे, उन्होंने हथियार नहीं उठाये। उसका नतीजा यह हुआ कि वे लड़ाई में हार गये। श्री ओमप्रकाश चौटाला को भी इसी प्रकार का फार्मूला मिल गया लगता है। वह भी कहीं पर तो अशोक अरोड़ा, कहीं पर सुभाष गोयल और कहीं पर रामभगल शर्मा और कहीं पर इंदौरा जी, इस प्रकार से वह इन सबको गऊओं के च्यौणे की तरह इस्तेमाल करके हरियाणा में सत्ता प्राप्त करना चाहता है लेकिन सभापति महोदय, उनका वक्त निकल चुका है अब उनका वक्त आने वाला नहीं है।

श्री सुभाष चौधरी (जगाधरी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने हरियाणा के बहुमुखी विकास के लिए, समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए जो बजट में सहूलियतें प्रदान की हैं वे अपने आप में सराहनीय हैं। सभापति महोदय, 3 साल पहले वह सरकार भी थी कि जिसने जाति के नाम पर, किसानों के नाम पर वोट लेकर उसी जाति के साथ धोखा दिया और उसका नतीजा यह रहा कि जनता ने उनको नकार दिया। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केन्द्र सरकार से मिलकर किसानों को कर्ज से उबारने के लिए किसानों के लोन माफ करवा कर उनको राहत प्रदान की है। भारत सरकार से किसानों का जो कर्जा मुआफ हुआ है उससे किसानों के

अन्दर उत्साह का संचार हुआ है। माननीय मुख्य मन्त्री जी के प्रयासों से समाज के हर वर्ग को राहत मिली है। हरियाणा के अन्दर एक नई आशा की किरण जगी है। हरियाणा प्रदेश तरक्की और नई गरिमा स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार मुख्यमन्त्री जी के नेतृत्व में तरक्की की ओर अग्रसर है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी को बधाई देता हूं। इस सरकार के राज में किसानों को बहुत राहत मिली है। किसानों का ब्याज मुआफ हुआ, कॉआपरेटिव के अन्दर भारत सरकार ने किसानों के कर्ज मुआफ कर दिये हैं, बिजली के बिल मुआफ हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को अपनी फसलों का जो भाव मिला है यह पूरे देश के अन्दर अपने आप में एक मिसाल है। किसी भी प्रदेश के अन्दर किसी भी फसल का भाव हरियाणा से ज्यादा नहीं है। चेयरमैन सर, मैं उस समय को भी याद करता हूं जब तीन-चार साल पहले का समय था तब किसान की फसल मण्डी में पड़ी रहती थी और किसान उस पर बैठ कर रोया करता था। जीरी औने-पौने भाव में बिका करती थी। उस समय एक बात चारों ओर सुनाई पड़ती थी **"चौटाला तेरे राज में जीरी गई ब्याज में।"** उस समय के पीरियड के बाद एक समय आज का है जब हमारी सरकार ने और हुड्डा साहब ने भारत सरकार से, सैंटर में बात करके हमें जीरी का जो रेट दिलाया है यह भी सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है और इसने भी एक नई मिसाल कायम की है और एक ऐसा माहौल आया है कि **"हुड्डा तेरे राज में जीरी चढ़ गई जहाज में।"** चेयरमैन सर, यह बात तो प्रदेश के हित में है और यह दर्शाती है कि सरकार की नीयत और नीति में क्या फर्क है। चेयरमैन सर, दो महीने पहले किसान को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। पाले के प्रकोप से किसान तबाह हो गया है। चेयरमैन सर, कल ही हमने सरसों काटी है और उसमें 6 या 7 क्विंटल भी फसल नहीं हुई है। पाले की वजह से किसान को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। छः एकड़ गेहूं की सोईंग है और फसल कटने वाली है। चेयरमैन साहब, आप इस बारे में जांच करवा सकते हैं कि उसमें एक भी दाना अनाज का नहीं है और उसमें से भूसा-भूसा ही बनेगा। चेयरमैन सर, इस पाले के कारण किसान को जो नुकसान हुआ है, इस बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री जी और माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि पाले से हुए नुकसान का भी कुछ न कुछ मुआविजा किसानों को जरूर दिया जाए। उसके लिए गिरदावरी करने का कोई न कोई प्रबन्ध जरूर किया जाए ताकि किसान लगातार फिर से नीचे न चला जाए। आज किसान इस स्थिति के अन्दर नहीं है कि फसल का घाटा बर्दाश्त कर सके। दूसरी फसल का घाटा बर्दाश्त करना किसान के लिए असम्भव होगा। पिछली सरकार के समय में हमें पॉपुलर का रेट नहीं मिला। हमारे यहां पर पॉपुलर की फसल होती है जिससे प्लाई की इंडस्ट्री चलती है। पॉपुलर का भाव देने में हमारी सरकार ने सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं। चौटाला साहब के राज में पॉपुलर का रेट 150/-रुपये मिलता था जब कि आज इसका भाव 600/-से 650/-रुपये मिल रहा है जो कि सरकार की नीयत को दर्शाता है। दोनों सरकारों में फर्क क्या है ? पिछली सरकार के समय में मुख्य मन्त्री और मन्त्री उगाही करवाया करते थे और एम०एल०एज० से भी उगाही करवाते थे। (विघ्न) आज हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की यह सोच है जिसकी वजह से किसानों को उसका भाव मिला है।

श्री बलवन्त सिंह : चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चेयरमैन सर, मेरे सम्मानित सदस्य कह रहे हैं कि उस समय के एम०एल०एज० से उगाही करवाई जाती थी। चेयरमैन सर, इनकी इस बात को सारे हरियाणा की जनता सुनने लग रही है। आज सदन में तमाशा सा बना रखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से यह कहना चाहता हूं कि ये विद प्रूफ उस एम०एल०ए० का नाम बताएं कि वह उगाही करता था और कौन उससे करवाता था। इस बारे में जो ये बात कह रहे हैं उसकी इन्क्वायरी करवाई जाए।

श्री सुभाष चौधरी : चेयरमैन सर, माननीय सदस्य भी जानते हैं कि मेरे जिले में प्लाई इन्डस्ट्री का शोषण हुआ था और वहां पर इनके समय में 20 लाख रुपए की मन्थली ली जाती थी। उस समय में वहां पर किसी एक उद्योगपति से एक करोड़ रुपए की डिमान्ड की गई थी लेकिन उसकी एवज में वह 70 लाख रुपए लेकर गया था लेकिन उसको एस0पी0 अम्बाला द्वारा रास्ते में ही रोक लिया गया और उसको कहा गया कि या तो एक करोड़ रुपए लेकर आ जाए नहीं तो तुझे गलत प्रापर्टी रखने के इल्जाम में अन्दर कर दिया जाएगा। इस बारे में बलवन्त सिंह सढ़ौरा जी भी जानते हैं।

श्री बलवन्त सिंह : चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय साथी जी ने अभी जो बात कही है इस बारे में मेरा कहना है कि जिस तरह से हाउस की पहले कमेटी बनाई गई है उसी तरह से इनके द्वारा कही बातों की सच्चाई जानने के लिए भी हाउस की एक कमेटी बनाई जाए और जो इन्होंने बात कही है उसके बारे में चैक किया जाए। इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री सुभाष चौधरी : चेयरमैन सर, पिछली सरकार ने 2003-04 में अपने वक्त में यमुनानगर शुगर मिल की मिलीभगत के साथ किसानों के 35 करोड़ रुपए की पेमेन्ट नहीं की थी। मैं इस बारे में सढ़ौरा जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात भी गलत है ? हमारी सरकार के आने के बाद ही मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों की वह पेमेन्ट दी है।

श्री बलवन्त सिंह : चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। उस समय किसान उस प्राईवेट मिल के खिलाफ कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट में जाने की वजह से ही उनकी पेमेन्ट का मामला लटका था न कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का उसमें हाथ था।

श्री सुभाष चौधरी : चेयरमैन सर, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान किसानों के उन ट्यूबवैल कनैक्शनों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनके ऊपर इण्डस्ट्रीयल रेट लगा हुआ है। चाहे वे ट्यूबवैल कनैक्शन, बागवानी, पशुपालन या फिशरी के लिए प्रयोग किए जाते हों। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन ट्यूबवैल कनैक्शनों को इन्डस्ट्रीयल रेट से निकाल कर एग्रीकल्चर स्लैब प्रणाली में शामिल किया जाए ताकि किसानों के ऊपर से आर्थिक बोझ कम हो सके। चेयरमैन सर, कोआप्रेटिव सैक्टर के अन्दर किसानों का ब्याज माफ किया है। इसी तरह से जो नॉन-एग्री के अन्दर गरीब लोगों को लोन मिलता है उसमें भी उन गरीबों को माफी मिलनी चाहिए। लेकिन उन गरीब लोगों को फायदा नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन लोगों का लोन भी माफ किया जाए जिससे उन गरीब लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी। चेयरमैन सर, सरकार की नीयत 36 बिरादरी की तरफ तब झलकती है जब सरकार सबके बारे में सोचे। चेयरमैन सर, सरकार ने देहातों में 11 हजार सफाई कर्मचारी सफाई के लिए लगाए हैं। यह बात दर्शाती है कि हमारी सरकार की नीयत क्या है। चेयरमैन सर, एक वह भी समय था जब छोटे वर्गों की इतनी अनदेखी होती थी कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। मुख्यमंत्री जी का यह फैसला कि देहात के अंदर 100-100 गज के प्लाट्स गरीब आदमियों को दिए जाएंगे, बहुत ही सराहनीय है। लोगों में इसको लेकर खुशी की लहर है। मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं। चेयरमैन सर, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा के अंदर जो सरकार ने नीति बना रखी है उसकी भी बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है। गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ सकें, उनको ज्यादा सहूलियतें मिल सके, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है, मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है ताकि गरीब लोगों को लाभ पहुंचे सकें। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। चेयरमैन

सर, सिंचाई के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यमुना नदी हमारे जिले में से गुजरती है इसलिए इस बारे में भी ख्याल करने की जरूरत है क्योंकि यमुना नदी का जो बहाव है वह हरियाणा की ओर ज्यादा है तथा यू०पी० की ओर कम है। इस बार पहाड़ों के अंदर पिछले बीस सालों के मुकाबले ज्यादा बर्फबारी हुई है इसलिए बरसात के दिनों में यमुना नदी में ज्यादा पानी आने की उम्मीद है। हमारे जिले में ऐसे हालात हैं कि हमारे यहां के कई गांव यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा पानी की आशंका के दृष्टिगत यमुना नदी के किनारे पर हरियाणा की तरफ से स्टड्स यानी ठोकरे लगवायी जाएं ताकि खेती की जमीन को बचाया जा सके और जो वहां पर गांव बसे हुए हैं उनमें ज्यादा नुक्सान न हो, फसले तबाह न हों। चेयरमैन सर, मुख्यमंत्री जी की अपार कृपा से पहली बार हमारे जिले में यमुना पार के किसानों के लिए बिजली के ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन मिले हैं। यमुना बैड के ऊपर करीबन 8 से 10 एकड़ की चौड़ाई यमुना की है अब वहां पर बिजली की लाईन डाली गयी है। विभाग ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और हमने भी इसके लिए बहुत साथ दिया है ताकि लाईन वहां पर खड़ी की जा सके, बिजली के पोल खड़े किए जा सकें क्योंकि बरसात में पानी बहुत ज्यादा यमुना में आता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो वहां पर रीवर बैल्ट पर बिजली के पोल हैं उनके ऊपर पत्थर की ठोकरे लगायी जाएं ताकि फ्लड के टाईम पर वे बह न जाएं। वैसे तो ये बीस फुट गहराई तक लगवाए गए हैं लेकिन फिर भी ज्यादा पानी की वजह से उनके बहने की आशंका तो बनी ही रहती है क्योंकि यमुना नदी में ढाई लाख, तीन लाख या चार लाख क्यूसिक पानी आता है। उस दौरान वे लाइनें बह न जाएं इसकी तरफ भी ध्यान रखना जरूरी है। विभाग ने इसके लिए मेहनत भी बहुत की है इसलिए इस पर ठोकरे लगाने का प्रबन्ध भी सरकार को करना चाहिए ताकि बिजली की लाईन सेफ हो सके। चेयरमैन सर, जहां तक इंडस्ट्रीज में सहूलियतें देने का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही उदारदिली दिखायी है। इंडस्ट्रीज को प्रदेश में बढावा मिले और प्रदेश तरक्की करे, इसके लिए सरकार ने बहुत काम किए हैं। चेयरमैन सर, कृषि तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सबको पता है। जमीन तो उतनी की उतनी ही है रबड़ नहीं है जो बढ़ जाए जबकि परिवार बढ़ गए हैं और खेत छोटे रह गए हैं। इंडस्ट्रीज में हरियाणा कांग्रेस पार्टी के इस राज में और मुख्यमंत्री जी की कृपा से विकास की ओर अग्रसर है। यह अपने आप में एक मिसाल है और यह मिसाल ही रहेगी। अब बहुत भारी फॉरेन इंवैस्टमैंट हरियाणा के अंदर आया है जबकि एक यह भी समय था जब हरियाणा से इंडस्ट्रीज उजड़कर राजस्थान, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट होने के कगार पर पहुंच गयी थी। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। जिन्होंने इंडस्ट्रीज को बढावा देने के लिए तरह तरह की सहूलियतें दीं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं जगाधरी फांस्टीथ्यूएंसी से चुनकर आया हूं। जगाधरी एक बहुत पुराना इंडस्ट्रियल टाउन है। यह पीतल की इंडस्ट्री के नाम से मशहूर है लेकिन आज वहां पर पीतल की इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर खड़ी हुई 16.00 बजे है। चेयरमैन सर, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दूसरे प्रदेशों ने इंडस्ट्रीज को बहुत सहूलियत दीं। जैसे उत्तरांचल, हिमाचल या राजस्थान प्रदेश हैं, इन्होंने टैक्स और बिजली में अपने यहां के उद्योगपतियों को बहुत सहूलियत दी । हमारे यहां की पिछली सरकारें इतनी सहूलियत नहीं दे सकीं जिसके कारण हमारी इंडस्ट्री पिछड़ गई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्तमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जगाधरी की मैटल इंडस्ट्री को बचाने के लिए मेहरबानी करके आप वैट टैक्स की दर एक परसैंट कर दें ताकि जगाधरी की मैटल इंडस्ट्री कम्पीट कर सके। इस बात की गारण्टी मैं लेता हूं कि रेवेन्यू हम जितना आज दे रहे हैं उससे कम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इससे हमारे यहां

[श्री सुभाष चौधरी]

की इंडस्ट्री दूसरे प्रदेशों से मुकाबला कर सकेगी । सभापति महोदय, वैट प्रणाली में कुछ खामियां हैं। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे एक आदमी 'ए' ने 'बी' से माल खरीदा और उसको माल की पेमेन्ट कर दी और टैक्स की पेमेन्ट भी कर दी । 'बी' ने टैक्स ले लिया और अपनी दुकान बंद करके नयी दुकान खोल ली और वहां से चला गया । बड़ी अजीब सी यह स्थिति है कि जिस आदमी ने टैक्स भी दे दिया अर्थात् 'बी' को 'ए' ने टैक्स दे दिया और नोटिस 'ए' को ही आ रहा है, नोटिस 'बी' को नहीं आ रहा है। इस सिस्टम में बड़े सुधार की जरूरत है। जो आदमी पहले ही टैक्स दे चुका वह किस बात का टैक्स दे। उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जिसने टैक्स लेकर खा लिया और खजाने में जमा नहीं कराया । मैं वित्त मंत्री जी से पुन: अनुरोध करूंगा कि यदि इस खामी में सुधार के लिए ऐक्ट में भी चेंज लाना पड़े तो लाया जाए । चेयरमैन सर, बिजली के मामले में प्रदेश की इस सरकार ने जो काम किया है वह बेमिसाल है। पिछले चालीस वर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है कि बिजली के मामले में क्या क्या होता रहा । ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यमुनानगर जिले में किसी सरकार के राज में आज तक कोई बिजली के उत्पादन की इकाई नहीं लगी थी, आज की सरकार के समय में इकाई लगी भी है और एक इकाई फंक्शन भी कर रही है और दूसरी इकाई चलने के लिए तैयार है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यमुनानगर की बिजली के उत्पादन के लिए तीसरी इकाई भी लगनी है उस तीसरी इकाई का काम जितनी जल्दी हो सके, शुरु किया जाए।

श्री सभापति : अब आप वाइंड अप करें ।

श्री सुभाष चौधरी : म्युनिसिपल सिटीज के अंदर अर्बन डिवेलपमैंट ने हाउस टैक्स माफ किया, उसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं। मेरा शहर भी 'ए' क्लास सिटी है । मेरे शहर के अंदर भी एक म्युनिसिपल पार्क बनाया जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने जनरल हॉस्पीटल को 40 से 60 बैड का अस्पताल करने की बात कही थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरे यहां के अस्पताल को 40 से 60 बैड का शीघ्र करवाया जाए । पीने के पानी के बारे में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि गांवों में पीने के पानी के ट्यूबवैल 'स्वच्छ जल धारा' योजना के अन्तर्गत बने हुए हैं । इनका बिल पंचायतें देती हैं लेकिन आज हालात यह हैं कि लोग बिल देते नहीं हैं और बिजली बोर्ड उनके कनैक्शन काट देता है या बिजली ही नहीं रहती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि 'स्वच्छ जल धारा' योजना के तहत सरकार उनको पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के थ्रू चलवाये । सरकारी कर्मचारियों के बारे में वित्त मंत्री जी ने बड़ी उदारता दिखाई है और तरह तरह की सहूलियतें देने की बात कही है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके बारे में और ज्यादा फिराखदिली से सोचें और उनको और ज्यादा सहूलियतें दें। They are also part and parcel of the Government. हरियाणा प्रदेश के 40-50 हजार कर्मचारी हैं इनकी सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता नौजवानों का बढ़ाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने छछरौली के अन्दर सरकारी कॉलेज बनाने की एनाउंसमैंट की थी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस कॉलेज को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। छछरौली में अब कोई रैस्ट हाउस नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार छछरौली में रैस्ट हाउस जल्दी बनवाये। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री साहिदा खान (तावडू) : चेयरमैन सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में कानून-व्यवस्था पहली चीज है। आज मेवात में निर्दोष लोगों पर केस लाद दिया जाता है और वहां पर जो अधिकारी हैं वे चुप बैठे रहते हैं। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है मेवात में यह लिखा हुआ नजर आता है, "नकली सोने की ईंटों से सावधान, हरियाणा पुलिस" इस कानून व्यवस्था की वजह से हमारी नाते रिश्तेदारी बन्द होने जा रही है। हमारी ग्रीवेन्सिज कमेटी के चेयरमैन साहब मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने भी उस नारे को पढकर देखा है कि मेवात जहां से शुरू होता है वहां यह लिखा हुआ होता है कि "नकली सोने की ईंटों से सावधान, हरियाणा पुलिस" । जब वहां पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं हैं और जो अधिकारी हैं वें भी पूरे तरीके से ध्यान नहीं देते तो फिर वहां पर गुण्डे आदमी और बढ जायेंगे जबकि सरकार भय मुक्त प्रशासन की बात कहती है। (विघ्न)

श्री नरेश कुमार प्रधान (बादली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो ये गुण्डाराज की बात कर रहे हैं तो गुण्डाराज तो इनकी सरकार की देन है। जब पिछली सरकार आई थी उस समय से गुण्डाराज चला आ रहा है। इनकी सरकार के समय जेलों के अन्दर रैस्ट हाउस जैसा माहौल बना दिया था। गुण्डों को सिक्योरिटी देकर शिमला तक घुमाकर लाया जाता था। आज कानून व्यवस्था की बात करते हुए इन्हें शर्म आनी चाहिए।

श्री साहिदा खान : चेयरमैन सर, माननीय सदस्य डायरेक्ट यह नहीं कह सकते कि शर्म आनी चाहिए। मेवात यहां से ज्यादा दूर नहीं है सिर्फ 325 किलोमीटर है। तीन साल पहले यह सरकार आई थी जब दोषियों को सरकार सजा न दे तो हमारी क्या गलती है। **(इस समय माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि आज कृषि की बात हो रही है। आज किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो चुका है। बार-बार यह कहा जाता है कि गेहूं का रेट एक हजार रुपये कर दिया है। मानते हैं कि इससे किसान को फायदा होगा। किसान आज कर्जे के बोझ से इतना दब गया है कि डी०ए०पी० और यूरिया का खाद उसे समय पर नहीं मिलता लम्बी लाईन लगानी पड़ती है। फिर भी खाद पूरे तरीके से किसानों को नहीं मिल पाती है। बल्कि ब्लैक में मिलती है। इससे किसान ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। अगर कोई मजदूरी के लिए चला जाए तो उसको सवा सौ रुपये दिहाड़ी से ज्यादा नहीं मिलता, इस प्रकार वह लगातार महीना भर जाएगा तो 3200 रुपये उसके बनते हैं। महीने में से कम से कम 22 दिन काम करते हैं और बाकी के 8 दिन मिस्त्री की थिक्कत आने से, छुट्टी पड़ जाने से और ईंट आदि मैटीरियल न होने की वजह से निकल जाते हैं। 3000 रुपये में गरीब आदमी अपना गुजर बसर नहीं कर सकता । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बात कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर पूरा विचार करें। पानी के लिए यहां बार-बार बात होती है। मेवात में पानी नाम की चीज नहीं। हांसी-बुटाना-लिंक नहर का बार-बार जिक्र आता है, यह नहर रिवाड़ी तक जरूर जा रही है लेकिन मेवात का उसमें कोई जिक्र नहीं है। इस नहर के बनने के बाद मेवात के बारे में कहा गया है कि यह नहर तैयार हो जाएगी तब मेवात में पानी आएगा। गुड़गांव कैनाल में जो आलरेडी पानी चल रहा है वह 200-250 क्यूसिक के आस पास है जबकि इस नहर की कैपेसिटी 3000 क्यूसिक की है। फरीदाबाद, गुड़गांव के सभी सम्माननित सदस्य बैठे हैं और इनको पता है कि इस नहर में 200-250 क्यूसिक से ज्यादा पानी नहीं है। पूरा फरीदाबाद, मेवात और गुड़गांव इस नहर से जुड़ा हुआ है और उसी के ऊपर निर्भर करता है। मैं समझता हूं कि तालाबों में भी यह पानी नहीं जा सकता। पिछली सरकार में कम से कम यह तो था

[श्री साहिदा खान]

कि तालाब तो भरे होते थे चाहे वे किसी भी तरह से भरे होते थे। अध्यक्ष महोदय, हालात यह है कि वहां दिन प्रति दिन सूखे का सामना करना पड़ रहा है। गरीबों के लिए एक नई बात आ रही है कि 100-100 गज के प्लाट मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं और इस स्कीम का स्वागत करता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि लोगों को प्लाट तो तभी मिलेंगे जब इनके नाम बी०पी०एल० में रहेंगे। बी०पी०एल० में जो धांधली हुई हैं वह सबके सामने है। सभी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। अभी कल परसों हमारे मेवात के डी०सी० ने एक पटवारी को सस्पैंड भी किया है। इस मामले में बहुत धांधलियां हो रही हैं, इस बात को सरकार ने और प्रशासन ने मान भी लिया है। गरीब लोगों को इस स्कीम का लाभ तभी मिलेगा जब उनका नाम बी०पी०एल० में होगा। जब बी०पी०एल० नाम की चीज नहीं होगी तो प्लाट क्या, कुछ भी नहीं मिल सकता। बी०पी०एल० स्कीम के तहत जो गुलाबी कार्ड और पीले कार्ड बने हुए थे उससे गरीब आदमी को अनाज और चावल मिलते थे जिससे वे अपना गुजर बसर करते थे और अपाहिज पेट भर खाना खा सकते थे। (शोर एवं व्यवधान) मैं लोगों की समस्या यहां बता रहा हूं न कि नाम कमाने के लिए यह बात कह रहा हूं।

श्री नरेश कुमार प्रधान (बादली) : अध्यक्ष महोदय, सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि बी०पी०एल० से प्लाट का कोई सम्बन्ध नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) सभी जातियों के लोगों को प्लाट मिलेंगे।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की बात है, हमारे तावडू हल्के में नहर का पानी नहीं आता। तावडू ब्लॉक और आस-पास के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे यहां न तालाब हैं और न ही जोहड़ हैं। इसी तरह मेवात में दो जगहें भयाना और सराज भी हैं जहां पानी नहीं है। हमारे तावडू ब्लाक में तो कम से कम ट्यूबवैल लग सकता है क्योंकि डेढ़ इंची के लगभग पानी लगता है। आज जो गेहूं की फसल हो रही है, उसका दाना भरा हुआ है,लेकिन बिजली की हालत बहुत गम्भीर है और बिजली का बहुत बड़ा संकट है। मेरे हिसाब से दिन में केवल डेढ दो घण्टे ही बिजली मिलती है और उसमें भी 10-10, 15-15 बार ट्रिपिंग हो जाती है। लोग बार-बार फोन करते हैं और हमें रात भर सोने नहीं देते। बिजली के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि हम मानते हैं कि सरकार के पास पूरी बिजली नहीं है लेकिन सरकार जितनी भी बिजली दे उसमें ट्रिपिंग न हो। बिजली लगातार आ जाये और रात के समय लगातार चलती रहे तो अच्छा रहेगा क्योंकि दिन में हवा चलती है और गेहूं खराब हो जाती है। बिजली के नाम की हरियाणा में चीज नहीं रह गई है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा। मेवात में पेयजल के लिए 'राजीव गांधी पेयजल संवृद्धि' परियोजना लागू हुई है। सरकार को मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाहूंगा कि कोटला झील का काफी बड़ा एरिया है वहां से यह प्रोजैक्ट पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए शुरू हुआ था। कोटला झील में 10 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। यमुना में बरसात के दिनों में जो फालतू पानी आता है अगर उस फालतू पानी को इस झील में डाल दिया जाए तो हमारा वाटर लैवल कम से कम 20 फुट ऊपर उठ सकता है क्योंकि हम वहां से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। इससे मेवात में सिंचाई अच्छे तरीके से हो सकती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बरसात के समय में बरसात के पानी को इस नहर में डालने की व्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त सरकार ने कहा था कि उस जमीन को एक्वायर किया जायेगा और किसानों को मुआवजा दिया जायेगा। इस तरफ भी सरकार ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है जब

से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से मेवात जिले में शिक्षा का ग्रोथ गिरता जा रहा है। मेवात में जिला हैड क्वार्टर बने हुए तीन-चार साल हो गए लेकिन वहां पर एक भी सरकारी सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। वहां पर एक हिंदू हाई स्कूल है और एक मेव डीग्री कॉलेज है जो कि दोनों ही प्राईवेट हैं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की तरफ तभी ध्यान दिया जा सकता है जब स्कूल होंगे। आज के दिन प्रदेश में मास्टरों की जो हालत बनी हुई है उसके बारे में सभी को मालूम है। मास्टरों के ऊपर नंगी तलवार लटकी हुई है। जो गैस्ट टीचर हैं वे अपनी नौकरी के लिए हर रोज स्ट्राईक करते हैं जिसके बारे में सभी को जानकारी है। यदि इसी तरह की स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक जारी रही तो शिक्षा का स्तर पूरे प्रदेश में गिरता जायेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेवात में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। मेवात हमेशा से पिछड़ा हुआ एरिया रहा है और अब भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आगे भी पिछड़ा ही रहेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने बजट अभिभाषण पर बोलते हुए सबसे पहले भय, आतंक और सुरक्षा की बात की है। सोहना, तावडू और मेवात एक साथ लगता हुआ क्षेत्र है। इस बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इनकी सरकार साढ़े पांच साल तक प्रदेश में रही। उस समय कानून व्यवस्था की प्रदेश में क्या हालत थी यह सभी को मालूम है। उस समय मेवात में कई गांव ऐसे थे जिनमें पुलिस भी नहीं जा सकती थी और यदि पुलिस को जाना पड़ता था तो दस-दस जिप्सियां एक साथ ले जानी पड़ती थी। अध्यक्ष महोदय, सोहना मेवात से जुड़ा हुआ एरिया है उस समय वहां पर एक-एक गांव से एक रात में दो-दो गाड़ियां चोरी हो जाती थीं। यदि कोई बैंक के बाहर अपनी मोटर साईकिल खड़ी करके बैंक से पैसे निकलवाने जाता था तो बाहर से उसकी मोटर साईकिल चोरी हो जाती थी। उस समय गऊ माता की हालत भी बहुत खराब थी जिस प्रकार से सीमेंट के कट्टे को हम उठाकर डालते हैं उस तरह से उस समय गऊओं को उठाकर डाला जाता था।

बैठक का स्थगन

Mr. Speaker : Hon'ble Members, as the sound system in the House is not properly working, the House is adjourned for 15 minutes.

(The Sabha then adjourned at 4.18 P.M. and re-assembled at 4.33 P.M.)

वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : At the time of the adjourment of the sitting, Shri Jaunapuria was on his legs. He may continue his speech.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कानून और व्यवस्था के बारे में बता रहा था कि इस मौजूदा सरकार के आने से पहले पिछले साढ़े पांच साल के दौरान कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल था और यह नौबत थी कि चाहे कहीं कितना भी बड़ा हादसा हो जाये और अगर कोई थाने में कम्पलेंट लिखवाने जाता था तो कोई एफ०आई०आर० नहीं लिखी जाती थी जब तक कि ऊपर के

[श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया]

आदेश न आ जायें। सबसे बड़ी बात यह थी कि सोहना, तावडू और मानेसर ये तीन पुलिस स्टेशन ऐसे थे कि इन तीनों थानों में शाम को 4 बजे तैयारियां की जाती थी और सुबह 10 बजे तक जितना भी पहाड़ों में जो ईललीगल काम था वह सारा उस समय के दौरान होता था और इससे जितना रात को पैसा इक्ट्ठा होता था वह सारे का सारा ऊपर भेजा जाता था। यह नौबत पूरे साढे पांच साल रही। आज इन तीन सालों के अन्दर हम बड़े गर्व और फख्र के साथ कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा जिसे कोई इललीगल साबित कर दे। उस समय सबसे बड़ी बात यह थी कि रोड के ऊपर चलते-चलते जो 10 टायरों की गाडियां होती थी उन 10 टायरों वाली गाडियों के ड्राईवर और कण्डक्टर को बांध कर गाडियां चोरी हो जाती थी और उसके बाद तक उनकी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं होती थी। यू०पी० में गुलावटी के पास एक गांव है उसमें एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा था। मेवात से उसकी सीधी रिश्तेदारी है। प्रशासन के साथ भी मेरी कई बार मीटिंग हुई और तब जाकर वह पूरा गिरोह पकड़ा गया। उनके पास से बहुत बड़ी मात्रा में मोटर साइकिल, बड़ी गाडियां, ट्रक इत्यादि पकड़े गये थे। प्रशासन ने थाने में लिस्ट लगा रखी थी कि अपनी-अपनी गाड़ियों की पहचान कर गाड़ी ले लें। अभी फिरौती की बात भी चल रही थी। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जिसमें पूरे देश के आदमी रहते हैं। उसके बावजूद भी साढे 5 साल जिस आंतक से वे जी रहे थे कोई आदमी अपने आपको सुरक्षित नहीं मानता था लेकिन आज मैं पूरे फख्र से कह सकता हूं कि आज किसी आदमी से कोई फिरौती नहीं मांगी जाती। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और प्रदेश के प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं कि 3 साल की अवधि में ही बहुत से मामले ठीक किये हैं वरना यह मामला बहुत बिगड़ चुका था। सबसे बड़ी बात जो केन्द्र ने, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक ऐसा अनोखा काम किया है कि किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किये हैं। इसी सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले की शुरूआत भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही सबसे पहले की थी। चाहे पहले बिजली के 1600 करोड़ रुपये के बिलों की माफी का मामला हो, चाहे 830 करोड़ करोड़ रुपये के आम गरीब आदमी के ब्याज का मामला हो। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए केन्द्र सरकार ने भी 60 हजार करोड़ रुपये के किसानों के कर्जे माफ किये हैं। इससे गरीब किसानों को राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव जिले में 17 गांव ऐसे हैं जिनकी तरफ हुड्डा का पैसा बकाया है। क्योंकि जमींदार की बात चल रही है, उनका केस हाई कोर्ट में चला गया था और उसमें हुड्डा जीत गया था और किसान हार गये थे। उस समय इन 17 गांवों के लोगों से चौटाला जी ने पब्लिक के बीच में बैठकर यह वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी और मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि तुम्हें कोई पैसा वापिस जमा नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब सरकार बन गई और उन लोगों ने झाड़सा में इक्ट्ठे होकर चौटाला जी से यह बात कही कि अब आप मुख्यमंत्री बन गये हैं हमारा 17 गांवों का 400 करोड़ रुपया जो हमें हुड्डा में वापिस जमा करवाना है उससे निजात दिलवा दो तो चौटाला जी ने 90-90 साल के लोगों को घोड़ा पुलिस पीछे लगा कर सोहना तक दौड़ा-दौड़ा कर पिटवाया था। उनकी पगड़ियाँ तथा जूतियाँ तक लूट ली गई जो कि सम्मान की निशानी होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का आश्वासन चाहूँगा कि जब प्रदेश के किसानों को इतनी राहत दी जा रही है और अगर उन गांवों के किसानों को भी राहत न दी गई तो हमारी तो आपस में रिश्तेदारी भी खराब हो जाएगी चूंकि जो जमीन मुआवजे के रूप में रखी हुई थी वह छूट नहीं सकती। अगर वे लोग अपना सब कुछ भी बेच दें तो भी

अपनी जमीन नहीं छुड़वा सकते । उनके रिश्तेदारों ने अपनी जमीन गिरवी रख कर वह जमीन छुड़वाई है। अगर मुख्यमंत्री जी की कृपा हो जाये तो उन बेचारे लोगों की जमीन फ्री हो सकती है और हमारी रिश्तेदारी भी टूटने से बच सकती है। यह कोई बहुत बड़ी राशि भी नहीं है, केवल 400 करोड़ रुपये हुडा का बकाया है वह माफ कर दिया जाये और जिन्होंने जमा करवा दिया है उनको भी राहत दी जाये ताकि वे भी अपनी बेटियों को घर से अच्छी तरह से विदा कर ससुराल भेज सकें और उनके रिश्ते बचे रह सकें। यह वायदा मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। स्पीकर सर, प्रदेश के सभी वर्गों को छूट मिलती जा रही है। स्पीकर सर, पिछली बार मैं गांव में गया था वहां पर जमींदार शहरी ब्राह्मण धौलीधार हैं। उस समय वहां पर एक ब्राह्मण सभा थी वहां पर उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आजकल सरकार सभी वर्गों के बारे में सोच रही है मगर पण्डितों ने ऐसा क्या बुरा किया है जो हमारे प्रति कोई सोच नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि अगर आपकी बात ठीक है तो मैं आपकी बात को विधान सभा में उठाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, वे लोग कई-कई सालों से वहां पर बैठे हैं उन पण्डितों को भी अधिकार दिया जाए कि वे अपनी जगह ले सकें। वे लोग वहां पर 30 साल से ज्यादा समय से बैठे हुए हैं। स्पीकर सर, कोर्ट ने भी यह बात कही है कि जो मालिक है उसका कब्जा है उसी का मालिकाना हक भी है इसलिए उनको उनका हक दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर भी गौर करें जो पण्डित धौलीदार बैठे हैं। उनको भी उनका हक मिलना चाहिए ताकि वे भी अपनी जमीन खरीद सकें, बेच कर सकें क्योंकि उस पर उनका हक बनता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी और अहम बात यह है और इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि गुड़गांव और फरीदाबाद ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको सारे हरियाणा में जाना जाता है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने मैट्रो रेल की शुरूआत वहां पर करवाई है और मैट्रो के लिए उन्होंने काफी पैसे का भी प्रावधान किया है। मैं इस बात को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं कि गुड़गांव तक तो ठीक है लेकिन गुड़गांव के अन्दर लाखों गाड़ियां हर रोज मानेसर, आई०एम०टी० तथा बावल तक जाती हैं। अगर मैट्रो रेल को मानेसर तक चलाया जाए या बावल तक बढ़ा दिया जाए तो इससे लोगों को बहुत ही फायदा होगा और लोग वक्त पर अपनी फैक्टरियों में पहुंच सकेंगे तथा इससे ट्रैफिक भी कण्ट्रोल हो जाएगा। जो लाखों गाड़ियां डेली गुड़गांव तक जाती हैं वे बन्द हो जाएंगी और उनसे भी बचत हो सकेगी। सड़क और परिवहन के बारे में माननीय वित्त मन्त्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि गुड़गांव में जो पुराने सैक्टरज़ हैं वहां तक तो बस सर्विस है लेकिन राजीव चौक से सैक्टर 50,55 तथा सैक्टर 56 में जो लोग जाते हैं उनके लिए प्रोपर बस की व्यवस्था नहीं है। गरीब आदमी रिक्शा में वहां तक जा नहीं सकता है और अपनी गाड़ी उनके पास नहीं है जिसके कारण उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार ने काफी नई बसें भी खरीदी हैं इसलिए अगर उन सैक्टरों के लिए बस का इन्तजाम हो जाए तो इससे उन लोगों को काफी फायदा मिल सकेगा। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मैं एक बात होस्पीटल के बारे में भी कहना चाहता हूं। गुड़गांव एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि कम से कम ऐम्ज जैसा होस्पीटल बनाना बहुत जरूरी है। आज आबादी बढ़ती जा रही है और हर बात के लिए हमारे लोगों को ऐम्ज में जाना पड़ता है। मेरा यह निवेदन है कि वहां पर ऐम्ज जैसे होस्पीटल का होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ 3510/-रुपये जो मिनिमम मजदूरी लागू की गई है यह छोटी बात नहीं है। किन जगहों पर यह लागू हो गई है इस बारे में तो पता नहीं लेकिन बहुत जगहों पर यह लागू हो गई है इसकी शुरूआत भी माननीय मुख्यमन्त्री जी ने की है गरीब आदमी को इससे काफी मदद तो नहीं मिल पाएगी लेकिन 1000/- रुपये जब वह अपने

[श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया]

परिवार में ले कर जाएगा तो उससे उसके परिवार को बड़ी राहत मिलेगी। अगर वह किराये के मकान में रह रहा है तो 100-50 रुपये उसका किराया बढ़ने से उसके मकान मालिक को यानि जमींदार को फायदा मिलेगा और उनके बीच का जो गैप है वह इससे खत्म हो सकेगा। सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे गरीब आदमी को बहुत फायदा मिल सकेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की बात है, बिजली को ग्रहण लगा हुआ है और प्रदेश में बिजली की बड़ी दिक्कत है। इस बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बहुत अच्छी शुरूआत भी की है। मगर शुरूआत जो की गई है हम समझते हैं कि आने वाले अढ़ाई तीन साल से पहले पूरी बिजली लोगों को नहीं मिल सकेगी। जैसे कि पिछली बार भी फसलों के लिए बिजली पूरी नहीं मिली थी जिसके कारण फसलों को नुकसान हुआ था। पिछली बार की तरह इस बार एक बार भी बारिश नहीं हुई। पहले सर्दियों में बारिश हो जाती थी लेकिन इस बार वह भी नहीं हुई है। जिसके कारण बिजली की पूर्ति में कमी हो रही है। बिजली की आपूर्ति बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इतना जरूर हुआ है कि ट्रांसफार्मरज़, खम्भे और तार की कोई कमी नहीं हैं। पहले जब कोई ट्रांसफार्मर जल जाता था या कोई तार टूट जाती थी तो 6-6 महीने तक लोग रोते रहते थे और वे बदले नहीं जाते थे। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज कोई अधिकारी यह नहीं कह सकता है कि ट्रांसफार्मरज की कमी है या तार अथवा खम्भे नहीं हैं। आज इसकी सारी व्यवस्था ठीक है लेकिन बिजली की सप्लाई की कमी है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली चाहे किसी भी रेट पर मिले वह खरीद कर प्रदेश के लोगों को दी जाए।

श्री अध्यक्ष : अब आप कन्क्लूड करें क्योंकि और सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : स्पीकर सर, मैं पांच मिनट में कन्क्लूड कर लूंगा। सिंचाई के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। पिछले 4-5 दिन से गुड़गांव में पानी की भारी किल्लत है। इस बारे में मैंने सिंचाई मन्त्री जी से बात भी की थी कि हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री आगरा कैनाल की तरफ से जाती है दूसरा सिस्टम यह हो सकता है कि गुड़गांव कैनाल के लिए दमदमा झील में पानी का स्टोरेज किया जा सकता है। हमने पानी के टैंकर गुड़गांव में से सभी जगहों से मंगवा लिए हैं लेकिन फिर भी वहां पर पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। अगर आगरा कैनाल से दमदमा लेक में पानी दे दिया जाए तो उससे गुड़गांव के पीने के पानी की दिक्कत खत्म हो सकती है। यह नहर एक या डेढ़ किलोमीटर लम्बी ही बननी है और उसके लिए जमीन एक्वायर की हुई है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। यह जो पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था है इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 40 सालों में एक गांव में एक ट्यूबवैल ही हुआ करता था और आज इस सरकार के आने के बाद एक गांव में चार-चार, पांच-पांच या छः-छः ट्यूबवैल हो गए हैं, लेकिन अगर वहां पर बिजली चली जाए तो लोगों को पानी नहीं मिलता है। अगर बिजली होगी तो ही पानी की पूर्ति हो पाएगी इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बिजली की भी समुचित व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के सोहना शहर में गर्म पानी निकलता है और लोग उसको या तो बर्फ से ठण्डा करते हैं या फिर फ्रिज में लगा कर पीने के लायक ठण्डा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पानी की प्रोब्लम को दूर करने के लिए एन०सी०आर० में 65 करोड़ रूपए सैंक्शन किए हुए हैं। आप इस पैसे को दिलवा दें तो वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़क और पुलों की बात करना चाहूंगा। यह ठीक बात है कि आज हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा

हुआ है। मेरे हल्के सोहना में सोहना रोड को अलवर तक डबल कर दिया जाए, जो कि मंजूर भी हो गया है। इसी तरह से अंधेरिया मोड़ से रोड बननी है जो कि वाया जौनपुर माण्डी होते हुए गुड़गांव को जाएगी। दूसरी रोड बसन्त कुंज थाने से आयानगर बार्डर पर मिलेगी, उस बारे में अभी तक अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अगर अधिकारी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो इस सड़क का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। अध्यक्ष महोदय, पलवल से रेवाड़ी 71(b) नैशनल हाई-वे बना हुआ है और इस सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है जिसकी वजह से वह सड़क टूट गई है उसको भी रिपेयर करवाया जाए। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव से फरीदाबाद की जो सड़क है वहां पर भी ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से जाम लगा रहता है इसलिए इस सड़क को डबल किया जाए ताकि वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से राजीव चौक से खेड़की दौला तक टोल टैक्स लगा हुआ है। वहां पर 10-12 गांव साथ में लगते हैं। अगर किसी का रिश्तेदार आ जाए और वह गलती से रास्ता भूल जाए तो उसको 16 किलोमीटर का चक्कर काटकर अपने घर जाना पड़ता है। अगर कोई सब्जी लेने के लिए जाए तो उसको 50 रूपए की सब्जी 500 रूपए में पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वे नैशनल हाई-वे अथौरिटी से बात करें कि वहां पर अन्डर बॉय पास बनाया जाए ताकि वहां के गांवों के लोगों को सुविधा मिल सके।

श्री अध्यक्ष : जौनपुरिया जी, आप बैठें। आपकी जो भी बातें हैं आप उनको लिखकर भेज दें। आनन्द सिंह डांगी जी, आप बोलें।

श्री आनन्द सिंह डांगी (मेहम) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, 18 मार्च, 2008-09 को वित्तमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने हरियाणा की जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए समाजिक एवं कल्याणकारी प्रशासन प्रदान किया है। पिछली सरकार के समय में जो भय, आतंक और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी गई थी, उस बारे में आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी और उनके साथी मंत्रियों के सहयोग से आज हरियाणा प्रदेश में शांति और सामंजस्य कायम है, सामाजिक सद्‌भावना कायम है। किसी प्रदेश के राजा या मुख्यमंत्री का अपनी जनता के प्रति सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उसकी जनता में सद्‌भावना हो, आपस में प्यार प्रेम हो, एकजुटता हो, एक भावना हो और हर प्रकार से भय मुक्त हों तथा एक दूसरे के प्रति हर तरह से लगाव बढ़े। अध्यक्ष महोदय, इसी का परिणाम आज यह है कि आज हरियाणा प्रदेश में हर व्यक्ति बड़े सुख की नींद सोता है। पिछले शासन काल में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल था, गुण्डागर्दी का माहौल था, आतंकवाद का माहौल था उसको पिछले तीन सालों में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले खत्म करने का कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, यह होना भी चाहिए था। कानून व्यवस्था को ठीक करना भी एक बहुत बड़ा कार्य हमारी सरकार ने किया है। कानून व्यवस्था के बारे में आज हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि आज हमारा प्रदेश पूर्ण रूप से शांतिप्रिय प्रदेश है और किसी प्रकार की अफरा तफरी आज प्रदेश में नहीं है। आज हमारा प्रदेश उन्नति और तरक्की की तरफ अग्रसर है। अध्यक्ष महोदय, यह सारा काम किसी की नीति, नीयत और निष्ठा के बल पर होता है। नीति, नीयत और निष्ठा की सबसे पहले मुखिया को जरूरत होती है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह करके दिखायी है। अध्यक्ष महोदय, नीयत के साथ ही बरकत होती है और उसी का नतीजा आज है कि हरियाणा आज हर फील्ड में, हर लाईन में चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ते हुए गौरवमयी ढंग से बुलंदियों पर पहुंचने का कार्य कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह कार्य आपसी टीम

[श्री आनन्द सिंह डांगी]

के साथ मिलकर किया है जिसकी गूंज आज भारतीय संसद में गूंज रही है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश या देश का विकास और तरक्की उसकी कानून व्यवस्था और उसकी अर्थ व्यवस्था पर निर्भर होती है। हमें आज इस बात के ऊपर बड़ा फख्र है कि ये दोनों चीजें हमारे प्रदेश में ठीक हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम आज का बजट और पिछले तीन सालों का बजट देखें तो वह यह दर्शाता है कि जहां तीन साल पहले इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ 2200 करोड़ रूपये का बजट हुआ करता था वह आज 6650 करोड़ रुपये का हो गया है। 6650 करोड़ रुपये का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस हरियाणा प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने एक लगन के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। यह किसी के कहने की बात नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज हरियाणा प्रदेश हिन्दुस्तान के मानचित्र पर एक अलग ही स्थान रखता है। चाहे विकास की वजह से हो या चाहे कानून की वजह से हो, हर तरह से पूरे प्रदेश में सदभावना और प्यार प्रेम है। हर तरह के भाई चारे के हिसाब से हमारा प्रदेश अलग है। यह सारे का सारा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को जाता है क्योंकि इनकी नीति, नीयत और निष्ठा बहुत अच्छी है और साथ ही उन्होंने टीम वर्क का सहयोग लेकर इस प्रदेश को हर तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है। हर तरह का सहयोग लेने की लगन उनमें है और वे इस बारे में प्रयत्नशील भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषक हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान अपनी मेहनत से हर किसी का पेट पालता है इसलिए यदि उस कृषक की मेहनत उसको ठीक ढंग से न मिले तो उसका न तो सामाजिक विकास हो पाता है और न वह खुले मन से मेहनत करके अपने प्रदेश और देश के लिए काम कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिसने कृषि के लिए और कृषक के लिए विशेष रूप से चाहे वह सबसिडी देने की बात हो, चाहे किसान को ऐग्रीकल्चर इम्प्लीमैंट्स के लिए उसकी और जिंस के अच्छे भाव देकर के किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने की बात हो, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि किसान की जिंस के लिए उन्होंने एक सही वक्त पर और सही समय व सही स्थान पर आवाज उठाई जिसकी वजह से किसान जो आज गेहूं की, धान की और दूसरी फसलें पैदा करता है उसका सम्मानजनक मूल्य किसान को मिलता है । आज किसान को गेहूं का एक हजार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट मिला है । यह भाव किसान ने सोचा भी नहीं था । इससे पहले जो सरकारें रहीं, किसी ने 10 रुपये भाव बढ़ा दिया किसी ने 5 रुपये बढ़ा दिया,या किसी ने 20 रुपये बढ़ा दिया । इस प्रकार के रेट बढ़ाकर उसको सम्मानित करने की बजाय बेइज्जत किया जाता था । आज की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी की रहनुमाई में, प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर किया है। सारा हरियाणा प्रदेश और सारा देश जानता है कि जिस दिन झाड़ली में श्रीमती सोनिया गांधी जी बिजली के कारखाने का उद्घाटन करने आईं, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने उनसे किसान की जिंस के भाव के लिए आवाज उठाई और 1100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव की मांग रखी और उसका असर तीन दिन के अंदर सामने आया। तीसरे दिन ही यू.पी.ए. की सरकार ने एकदम से एक हजार रुपये प्रति क्विंटल के रेट की घोषणा की और एकदम से 350 रुपये प्रति क्विंटल की रेट में बढ़ौतरी की। इस सरकार ने किसान को जो सम्मान दिया है, किसान को उसकी मेहनत का फल दिया है, यह काबिले तारीफ है। पंजाब खाद्यान्न उत्पादन में हमारे से आगे हुआ करता था लेकिन आज किसान

की मेहनत की वजह से और पानी के ठीक ढंग से बंटवारा होने की वजह से आज हरियाणा प्रदेश कृषि क्षेत्र में पंजाब से आगे जाकर अच्छा नाम कमा रहा है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के और गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किए हैं वह पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। जिस तरह से उनको 100-100 गज के प्लॉट देने की बात कही है, यह बहुत बड़ी बात है। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अनुसूचित जाति के गरीब भाइयों को अनुदान के रूप में, मदद के रूप में अपना जीवन ठीक ढंग से व्यतीत करने के लिए 100-100 गज के प्लाट देने की बात कही है । यह गरीब आदमी को प्रोत्साहित करने वाली बात है। आज के दिन हम जमीन के भाव देखें तो वह आसमान छू रहे हैं । 100 गज का प्लॉट आज के दिन चाहे कहीं भी ले लो उसकी कीमत एक लाख रुपये से कम नहीं है। यदि गरीब आदमी को इस तरह की राहत मिल जाए तो यह बहुत सराहनीय है । इसी प्रकार से किसान के लिए और हर गरीब आदमी के लिए भी ब्याज माफी की जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणायें कीं और उनको अमली जामा भी पहनाया तो यह भी गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी । अध्यक्ष महोदय, आज किसान इतना अधिक दबा हुआ है उसके खेत की जो उपज है उस उपज के हिसाब से वह अपने बच्चों का पालन पोषण भी मुश्किल से कर पाता है। खेती की अच्छी पैदावार लाने के लिए किसानों को कर्जा लेना आवश्यक हो जाता है लेकिन अगर उसकी अदायगी के वक्त उसके ऊपर तरह-तरह के दबाव डाले जायें और जबरदस्ती वसूली की जाए तो किसान बेसहारा होकर अपने मन को मारकर बैठ जाता है। उसकी जो मेहनत होती है उस पर उसको पछतावा होता है लेकिन आज यू०पी०ए० की सरकार ने, श्रीमती सोनिया गान्धी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो 60,000 करोड़ रुपये की कर्जा माफी की घोषणा की है वह बहुत ही सराहनीय कदम है जिसकी पूरे किसान वर्ग में, हर समाज में जबरदस्त वाह-वाही हुई है। इससे किसानों को जबरदस्त राहत मिली है और एक हौंसला अफजाई हुई है। साहूकारों और आढ़तियों के ब्याज के लिए रोजाना सरकार की नीति और नीयत सुनने में आती है । साहूकारों और आढ़तियों से गरीब किसानों ने जो लोन ले रखे हैं या जो जरूरत के वक्त अपनी जीन्स डालकर थोड़े से पैसे लेकर आता है उस पर ब्याज बढ़कर इतना कर्जा हो जाता है कि किसान और गरीब आदमी की बस की बात नहीं रहती कि वह उतार सके। आज मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को जो उनकी तरफ से यह बात आई है कि साहूकारों और आढ़तियों से जो कर्जा किसानों के ऊपर है उसको ठीक ढंग से निपटाने की जो बात आई है जिससे किसान भी बचेगा और साहूकार तथा आढ़ती जिनसे कर्जा ले रखा है उसके ऊपर भी आंच नहीं आयेगी। इतनी बड़ी सोच इतना बड़ा फैसला इतने अच्छे ढंग से इसका निपटारा करना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पूरी उम्मीद के साथ जल्दी कदम उठाकर हमारी सरकार ने गरीब भाईयों और गरीब किसानों को राहत दी है। मेरा निवेदन इस बारे में यह है कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो छोटे-छोटे कामों के लिए लोन ले लेते हैं। जैसे भैंस के लिए या दूसरे कामों के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, बच्चों के पालन-पोषण के लिए लोन लेते हैं, मेहनत करके कमाता खाता है उसके लिए कर्जा लेकर अपना काम जोड़ रखा है, उनके ऊपर हमारी सैंटर की सरकार और स्टेट गवर्नमैंट इस बारे में विचार करे ताकि उनको इसके लिए भी राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारी सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी के लिए बहुत बड़ा काम किया है।

श्री अध्यक्ष : डांगी साहब, आप कितना टाईम और बोलोगे ?

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर एड्रैस पर भी नहीं बोला। आज मुझे बोलने का मौका मिला है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप तीन मिनट और बोलिए।

श्री आनन्द सिंह डांगी : तीन मिनट नहीं, तीस मिनट और दीजिए।

श्री अध्यक्ष : डांगी साहब, आप लिखकर दे दीजिए।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े तो बोल नहीं रहा, दूसरा लिखा हुआ हो तो ऐसी भी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप पांच मिनट और बोल लें। (पिच्च) डांगी साहब, आप बजट पर बोलें।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सड़क-परिवहन के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत बढ़िया इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया है यह सब जनता के सामने है। विकास के बारे में अच्छी सड़कें देकर, परिवहन को अच्छे रास्ते देकर जो कार्य सरकार ने किया है वह बहुत ही सराहनीय है क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास और तरक्की अच्छी परिवहन व्यवस्था और अच्छी सड़कों से जुड़ी हुई है। यह बड़े फख्र की बात है कि आज हरियाणा प्रदेश में चाहे ओवर ब्रिज बनाने की बात हो, सड़कों की वाईडनिंग करने की बात हो, सड़कों की स्ट्रैथनिंग की बात हो,यह सब बड़े जबरदस्त ढंग से किया गया है। आज हरियाणा प्रदेश इस मामले में पूरे देश के अन्दर सबसे आगे है। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए न्यूनतम दिहाड़ी 3510/-रूपये मासिक करना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा इस मामले में सारे हिन्दुस्तान में सबसे अग्रणी है। यह श्रेय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है क्योंकि गरीब आदमी की मेहनत का अगर सही मूल्यांकन न हो और उसकी मेहनत का ठीक पैसा न मिले तो गरीब आदमी के आँसू ही निकलते हैं और वे आँसू ठीक नहीं होते। जो गरीब आदमी के लिए मिनीमम मजदूरी 3510/- रूपये करने का काम किया गया है, वह एक सराहनीय कार्य है। समाज के कमजोर वर्गों व अनुसूचित जातियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए और उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति शिक्षा प्रोत्साहन" नामक स्कीम के तहत एक क्रांतिकारी योजना शुरू की गई है। जो गरीब आदमी अपने बच्चों की फीस भरने की हिम्मत नहीं करता था आज हरियाणा की सरकार ने उनको अनूठा प्रोत्साहन दिया है जिससे मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा और हर व्यक्ति को पढ़ने का मौका मिलेगा। गरीब छात्रों को 100 रूपये से 300 रूपये प्रतिमास तथा छात्राओं को 150 रूपये से 400 रूपये प्रतिमास तक छात्रवृत्तियां देने का काम इस सरकर द्वारा किया गया है। यूनिफार्म, लेखन सामग्री तथा स्कूल बैग इत्यादि पर 740 रूपये से 1450 रूपये तक का जो खर्चा आता है, वह सारा खर्चा अनुसूचित जातियों के सभी विद्यार्थियों को देने का सराहनीय काम सरकार द्वारा किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बिजली की हमारे प्रदेश में बहुत कमी है, उस कमी को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने सार्वजनिक रूप से माना है। यह बहुत बड़ी समस्या है। उन पिछली सरकार के लोगों की तरह से ये लोगों को बरगलाते नहीं क्योंकि ये लोग जहां कहीं भी जाते थे तो कहते थे कि 31 जनवरी के बाद हरियाणा की जनता को 24 घण्टे बिजली मिलेगी और फिर कहते थे कि 31 मार्च के बाद 24 घण्टे बिजली मिलेगी लेकिन 6 साल तक लोगों को बहकाकर इस प्रदेश में राज करके ये लोग चले गए लेकिन इन्होंने कभी कहीं एक यूनिट बिजली का कारखाना लगाकर इस समस्या का समाधान करने के बारे में नहीं सोचा। मगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस समस्या को हरियाणा प्रदेश से जड़मूल से खत्म करने के लिए झाड़ली में, खेदड़ में, झज्जर में और यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए जो कार्य किए हैं वह जबरदस्त सराहनीय कार्य है और यह काम वही

व्यक्ति कर सकता है जो नीयत से काम करता है और जिसकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जनता ने जिसका साथ दिया होता है और कुछ करने की बात जिसके दिमाग में होती है, अपने फर्ज को निभाने की जिसमें बात होती है। हरियाणा की जनता इसके लिए हर कदम पर सरकार को बधाई देती है और सरकार की सराहना करती है। आने वाले वक्त में हमें पूरी उम्मीद है कि इस समस्या का जड़मूल से समाधान होगा। ये काम वही करता हैं जो जनता के प्रति जवाबदेही रखता हो। जनता के साथ झूठे वायदे करके, जनता के साथ ठगी करके राज काज में आकर जो मौज मस्ती करते हैं उनका यही हश्र होता है जो आज हमारे सामने बैठे इन लोगों का हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई की बात है तो सिंचाई के मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री की रहनुमाई में एक लम्बा संघर्ष हरियाणा की जनता ने किया है और उस संघर्ष का मतलब एक ही था कि हरियाणा प्रदेश के किसान को पानी के मामले में जहां उसका जितना हक बनता है वह हक मिले। नहरी पानी और पीने का पानी भी उसको उतना मिले जितना उसका हक बनता है। आज पूरा हरियाणा इस बात के लिए मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता है और पूरा हरियाणा एक स्वर में आज मुख्यमंत्री महोदय के साथ खड़ा है। जहां जिसका जितना पानी का हक बनता था उतना पानी देने का कार्य इस सरकार द्वारा किया गया है और इस काम को अमली जामा पहनाने के लिए दो-तीन नहरों की शुरूआत की गई जैसे हांसी-बुटाना-लिंक नहर और दादुपुर-शाहबाद-नलवी और इसी प्रकार जवाहर लाल नेहरू फीडर की क्षमता बढ़ाने का काम भी किया गया है। इसी तरह से जो नीयत और लगन से काम किया गया है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है इससे किसानों को एक नई रोशनी मिलेगी और किसानों को पेट भरने के लिए नया रास्ता और ताकत मिलेगी। जो ये लोग दोगली बातें करते हैं, सदन में कुछ कहते हैं और सदन से बाहर कुछ कहते हैं, जैसे सदन में कहते हैं कि हम इसका विरोध नहीं करते और सदन से बाहर जाकर उसी वक्त प्रैस में कुछ और कहते हैं। एक बेटा कहता है कि खून की नदियां बह जाएंगी लेकिन पानी नहीं आने देंगें। जब श्रीमान से बेटे के बारे में पूछा जाता है कि आपके बेटे ने यह बात कही है या नहीं तो वे उस बात से मुकर जाते हैं और ऐसा आभास होता है वे अपने बेटे के बारे में भी कुछ शक सा जाहिर करते हैं । यह तो एक रीति है क्योंकि आदमी की एक मानसिकता होती है, नीयत होती है और एक लाईन होती है। एक बार जो आदत पड़ जाती है वह छूटनी आसान नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि जिस समय चौधरी देवी लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ प्रदेश की बागडोर सम्भाल रखी थी। उस समय ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत बड़ा कलंक उन पर लगाया था जिसके कारण चौधरी देवी लाल जी को मजबूरन ऐसी बात कहनी पड़ी थी जो आज चौटाला जी अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं। आज भी प्रदेश में वही हालत बने हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटे के बारे में स्पष्ट बात नहीं कर पाये। इस बारे में प्रदेश के लोगों के लिए सोचने वाली बात है। इस तरह के लोग जनता को बार-बार झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। इस तरह के लोग जनता से झूठ बोलकर वोट लेते हैं और अपना राजनैतिक तंत्र स्थापित करने की कोशिश करते हैं लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश में चारों तरफ विकास कार्य किए हैं जो कि अपने आप में एक मिसाल है। आज के दिन प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। आने वाले समय में दूसरे प्रदेशों के लोग हरियाणा प्रदेश की तरक्की को, यहां होने वाले विकास कार्यों को और जो इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार ने जनता को मुहैया करवाया है उसको देखने के लिए आयेंगे। अगर किसी प्रदेश की सरकार की नीयत ठीक होगी तो वे हमारा अनुसरण भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक हफ्ते से बजट पर अनेकों बात कई माननीय सदस्यों ने रखी हैं

[श्री आनन्द सिंह डांगी]

लेकिन मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शहरी तर्ज पर सरकार गांवों का विकास करने जा रही है वह अपने आप में एक मिसाल है। मौजूदा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का चहुमुखी विकास करने तथा शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 91 गांवों का चयन आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त गरीब आदमियों के घरों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने एक अनूठी योजना चलाई है जिसके तहत गरीब आदमियों को मुफ्त में पानी के कनैक्शन के साथ टूटी और पानी की टंकी भी दी गई है ताकि गरीब आदमियों के घरों में भी पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके और उनकी सेहत भी ठीक रहे। जबकि पिछली सरकारों के समय में गरीब आदमियों के पूरे मौहल्ले में पानी की एक टूटी भी मुश्किल से मिलती थी। गरीब आदमियों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए पहले किसी ने नहीं सोचा। पहली बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब आदमियों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की पहल की है और बहुत अच्छा प्रोत्साहन गरीब आदमियों को देकर उनकी काया-कल्प करने का काम किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के उत्थान के लिए 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति गांव उत्थान एवं मलिन बस्ती विकास योजना' नामक नई स्कीम शुरू की है। जिसके तहत वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या वाले सभी 391 गांवों में 50 लाख रूपये प्रति गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए खर्च किए जायेंगे जिससे प्रदेश के अंदर बहुत बढ़िया और स्वच्छ वातावरण पैदा होगा तथा प्रदेश के हर आदमी को अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त गांवों से गंदगी दूर करने के लिए और स्वच्छता लाने के लिए पूरे हिन्दुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनियां में एक अनूठा प्रोग्राम हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि प्रदेश में 11000 सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे जोकि गांवों में स्वच्छता की स्थिति को सुधारने में लाभप्रद साबित होंगे। इस स्कीम के तहत 11000 गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे उनको रोजी-रोटी भी उपलब्ध होगी। अध्यक्ष महोदय, एक सफाई कर्मचारी को 3500 रूपये प्रति माह के हिसाब से सैलरी दी जायेगी। यदि किसी को अपने ही गांव में, अपने ही घर में 3500 रूपये प्रति माह के हिसाब से मिल जायें तो मैं समझता हूं कि वे 3500 रूपये 35000 रूपये के बराबर हैं। अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में हमें हर गांव में सफाई नजर आयेगी और प्रदेश के लोगों को स्वच्छ वातावरण रहने को मिलेगा जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा तथा लोगों को बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के तहत इच्छुक व्यक्तियों को गांवों में या गांव के निकट एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए न्यूनतम दिहाड़ी पर रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। पहले यह स्कीम दो जिलों में चल रही थी अब पूरे प्रदेश में इस स्कीम को लागू किया जायेगा। इसी प्रकार से शहरी विकास में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। शिक्षा एवं खेलों के बजट में भी तीन गुणा वृद्धि की गई है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवा के लिए और दूसरे सभी महकमों के लिए सरकार ने बजट को तीन गुणा करके दिया है। यह एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। सरकार ने वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, विकलांगों के लिए पैंशन का प्रावधान किया है और यहां तक कि किन्नरों के लिए और बौनों के लिए भी मौजूदा सरकार द्वारा पैंशन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ऐसे परिवारों के लिए जिनमें केवल लड़कियां हैं, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत इनको इतना जबदरस्त प्रोत्साहन दिया गया है कि आज गरीब आदमी अपने बच्चों को बोझ नहीं मानता। इसी प्रकार

से गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 15 हज़ार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। जबकि इससे पिछली सरकार द्वारा इसके अन्तर्गत केवल 5100 रूपये ही बड़ी मुश्किल से दिये जाते थे। यह जो गरीब कन्याओं के लिए सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है इससे एक गरीब आदमी 15 हज़ार रूपये में अपनी बच्ची के हाथ पीले करके अगले घर भेज सकता है और सुख शांति से अपना गृहस्थ जीवन चला सकता है। यह एक बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कार्य है। इसी तरह से महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार द्वारा लाड़ली पैंशन योजना शुरू की गई है उसी के तहत यह 15 हज़ार रूपये वाली बात भी आती है। इसी प्रकार से उद्योग धंधों में 33 हज़ार करोड़ रूपये का निवेश आज हमारे प्रदेश में होने लग रहा है और बाहर से यहां पर लोग उद्योग लगाने के लिए अग्रसर हैं जिससे 66 हज़ार करोड रूपये का निवेश पाईपलाईन में हैं। जिनके शीघ्र ही स्थापित होने की सम्भावना है। इसका श्रेय भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है जिन्होंने चारों तरफ एक शांत वातावरण उद्योगों के लिए उपलब्ध कराया जिससे कि किसी भी इण्डस्ट्रीलिस्ट को जो हरियाणा में उद्योग लगाना चाहे उसको किसी प्रकार की असुविधा न हो। इन सब बातों के कारण ही हर कोई हमारे प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अग्रसर है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। जहां तक एस०ई०जैड० का सम्बन्ध है तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश में जो एस०ई०जैड० की स्थापना का प्रावधान किया गया है यह एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे कुछेक साथी हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे प्रदेश में जो तरक्की और विकास के लिए अब तक किया गया है और भविष्य में जो किया जायेगा उसमें मन मार कर लोगों में जाकर के इस प्रकार की बात कहते हैं कि एस०ई०जैड० किसानों को उजाड़ने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अगर एस०ई०जैड० नहीं होंगे तो हमारा प्रदेश चहुंमुखी विकास नहीं कर सकेगा और न ही हमारे बच्चों को रोजगार मिल सकेगा। मैं इस सदन में इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं अपने महम हल्के की 10 हज़ार एकड़ जमीन एस०ई०जैड० और उद्योगों की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ऑफर करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे हमारे महम हल्के में एस०ई०जैड० की स्थापना करें और उद्योगों की स्थापना करे। हमें इस बात की बड़ी खुशी होगी। एस०ई०जैड० और उद्योगों की स्थापना से हमारे बच्चों को रोजगार मिल सकेगा और बेरोजगारी की समस्या से भी हमें निज़ात मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पिछले तीन सालों में तीन गुणा जो बजट हमारे वित्तमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं तथा विभागों को दिया है उसका आबंटन दर्शाता है कि यह बजट जनहितकारी, जनकल्याणकारी और चहुंमुखी विकास के साथ-साथ सुख शांति के लिए हरियाणा प्रदेश को देश के परिदृश्य पर नम्बर एक की पोजीशन पर ले जाने वाला बजट है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से इस बजट को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करूंगा। इसके साथ ही मैं इस विकासपूरक बजट के लिए वित्तमंत्री महोदय, अधिकारीगण और जिन्होंने इस बजट को बनाने में सहयोग दिया और सबसे बढ़कर आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो इस प्रदेश को हर प्रकार से तरक्की और विकास के मामले में आगे बढ़ाने के लिए फैसले लिए हैं और काम किए हैं उनकी एक लम्बी सूची है उन सबके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं और इसी के साथ यह आशा करता हूं कि जिस नीति और नीयत के साथ आज सरकार कार्य कर रही है अगर सरकार ऐसे ही कार्य करती रही तो आने वाले वक्त में हरियाणा प्रदेश इस देश का सिरमौर होगा। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

डॉ० सीता राम (डबवाली, अनुसूचित जाति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री महोदय ने जो 2008-09 का वार्षिक बजट पेश किया है इस पर आपने मुझे चर्चा करने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्तमंत्री जी बड़े सुलझे हुए डैमोक्रेटिक आदमी हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जनता को अच्छा बजट देने का प्रयास किया है। लेकिन बजट पेश होने से पहले आम जनता को इस बजट से बहुत आशाएं थी और बजट से लोगों को उम्मीद होती भी है। आम आदमी को उम्मीद होती है कि उसको इस महंगाई के दौर में खाने पीने की चीजें सस्ती उपलब्ध होंगी। उद्योगपतियों को भी आशा होती है कि किसी तरीके से वैट में या करों में राहत दी जायेगी लेकिन इस बजट को पढ़ने के बाद और इसका आंकलन करने के बाद यह लगता है कि यह बजट लोगों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। इस बजट में बजट एट ए ग्लांस के अन्दर दिखाया गया है कि रिवैन्यू रिसीट्स के अन्दर बड़ा भारी इन्क्रीज हुआ है, जो 2005-06 में 29.6 परसैंट के करीब इन्क्रीज है अगर उसको हम 2008-09 में देखें तो यह घटकर तकरीबन 10 परसैंट के करीब हो गया है। इसी तरह से नॉन प्लान एक्सपैंडिचर है वह भी बढ़ा है। पॉवर सैक्टर में 2007-08 में जो प्लान एक्सपैंडीचर था वह 872.52 करोड़ रूपये था लेकिन इस साल 2008-09 में घटकर यह 866.88 करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट में जो प्लान बजट था वह 90 करोड़ से ज्यादा था जो कि घट कर 68.17 करोड़ हो गया है। मैं सिर्फ उन बिन्दुओं पर प्रकाश डाल रहा हूं जहां पर सरकार अपनी कमियों को दूर कर सके और जिन डिपार्टमैंटस का बजट घट गया है उनको बढ़ाया जा सके। अर्बन डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट का भी 2007-08 में प्लान बजट 314.16 करोड़ था उसको घटाकर 291 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह से कंसोलिडेटिड फंड्स पॉवर सैक्टर में जो बजट 2007-08 में 14.34 परसैंट था वह डिक्रीज हो कर 13.36 परसैंट हो गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट का भी बजट जो 2007-08 में 3.59 परसैंट था वह घट कर 3.22 परसैंट हो गया है। सिंचाई विभाग का बजट भी पिछले साल 2007-08 के 6.25 परसैंट के मुकाबले घट कर 5.59 परसैंट हो गया है। इसी तरह से जो वॉटर सप्लाई और सैनिटेशन का 2007-08 का बजट था वह 5.10 परसैंट था जो घटकर इस साल 4.68 परसैंट हो गया है। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग का बजट 2007-08 में जो 13.44 परसैंट था वह भी घटकर 12.86 परसैंट हो गया है। सोशल वैल्फेयर का बजट भी 5.12 परसैंट से घटकर 4.79 परसैंट हो गया है। इसी तरह से हैल्थ डिपार्टमैंट का बजट भी 2007-08 में 2.65 परसैंट था जो कि घट कर 2.59 परसैंट हो गया है। इसी प्रकार से पुलिस विभाग का बजट 3.67 परसैंट से घट कर 3.39 परसैंट हो गया है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इसके अन्दर जो इन्क्रीज 2005-06 में रेवैन्यू रिसीट्स में दर्शाई गई है वह 29.6 परसैंट है जबकि इस वर्ष 2008-09 में जो प्रपोज किया गया है वह 10% के करीब है। इससे ऐसा लगता है कि जो इन्क्रीज हुई है। वह मेनली वैट की वजह से तथा मंहगाई बढ़ने की वजह से हुई है, स्टॉम्प ड्यूटी बढ़ने की वजह से हुई है क्योंकि जो क्लैक्टर रेट बढ़ा है उसकी वजह से स्टॉम्प ड्यूटी भी बढ़ी है। मंहगाई बढ़ने की वजह से तथा वैट बढ़ने से यह इन्क्रीज हुई है लेकिन अब डाउन ट्रैंड चल रहा है और अगले साल जब वैट डाउन आएगा या मंहगाई में कमी होगी तो अगले साल पता चलेगा कि हरियाणा के अन्दर आर्थिक स्थिति कैसी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो अन्य विषय हैं मैं उनको टच नहीं करूंगा जिन पर हमारे साथी बोल चुके हैं लेकिन मैं पावर सैक्टर पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। यहां पर यह बात बार-बार कही गई कि पिछली सरकार ने एक भी यूनिट बिजली पैदा नहीं की लेकिन हमारी सरकार के समय में प्रदेश में बिजली की स्थिति बहुत अच्छी थी। स्पीकर सर, जैसे कि आज बिजली की कमी के कारण कट्स और जाम लगते हैं वैसे कट्स और जाम हमारी सरकार के वक्त

में नहीं लगते थे। हमारी सरकार ने पानीपत की दूसरी यूनिट, छटी यूनिट, सातवीं यूनिट और आठवीं यूनिट चालू की और इसके साथ ही साथ हमें फरीदाबाद से भी बिजली मिली। स्पीकर साहब, यह रिकार्ड की बात है और यह हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में दर्ज भी है। यह सरकार का छपा हुआ सर्वेक्षण है इसके अन्दर लिखा हुआ है कि 1565 मेगावाट बिजली हमारी सरकार के अन्दर प्रोडयूस हुई थी। (विघ्न) स्पीकर सर, टोटल 4000 से कुछ अधिक बिजली उत्पादित की गई। आप यह फिगर देख सकते हैं अगर यह गलत है तो आप कह सकते हैं यह आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट छपी है जिसमें से मैंने यह फिगर कोट किया है यह इसके अन्दर मैंशन किया हुआ है। आप इसको उसमें से निकाल दीजिए। (विघ्न) मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है यह आपकी बुक में छपी हुई है। यह जो साथी कहते हैं कि राज में खुशहाली है। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने जनता के मन में यह भय डाल दिया कि वैट लागू करके हमारी सरकार ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। हमने उस वैट को लागू नहीं करना था । अध्यक्ष महोदय, यहां पर विधान सभा में तो ये लोग कहते थे कि वैट से प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। इन लोगों ने व्यापारी, मजदूर और किसान तथा आम आदमी के मन में यह बात डाल दी थी कि पिछली सरकार ने वैट लागू करके प्रदेश को बर्बाद कर दिया। वैट को लेकर इन लोगों ने मजूदरों और किसानों को भड़काया लोगों को गुमराह करने का काम किया (विघ्न) इसके कारण हमारी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हुआ। स्पीकर सर, दूसरी बात यह है कि हमारे ये साथी जब विपक्ष में थे तो यह बात कहा करते थे कि कोल बेस्ड पावर प्लांट नहीं लगने चाहिएं उस समय इन्होंने यह घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम गैस बेस्ड प्लांट लगाएंगे। हमने उस वक्त यह भी कहा था कि गैस अथोरिटी ऑफ इण्डिया ने कहा हुआ है कि भारत वर्ष के अन्दर वर्ष 2009 तक गैस अवेलेबल नहीं हो सकती है। यहां पर विधान सभा में ये कहते हैं कि गैस की उपलब्धता हमारे हाथ में नहीं है। इस गैस बेस्ड प्लांट को बनाने की घोषणा इन्हें नहीं करनी चाहिए थी और इसकी नींव नहीं रखनी चाहिए थी। ऐसी बात इन्हें नहीं कहनी चाहिए थी जो पूरी नहीं हो सकती थी। यह जो न्यूक्लीयर पावर प्लांट की चर्चा की गई है, मैंने इस के बारे में अपना सवाल भी किया था। तीन साल हुए न्यूक्लीयर पावर प्लांट पर कोई कार्य नहीं हुआ है। किसी को यह नहीं पता कि यह पावर प्लांट कहां लगेगा, कब लगेगा, इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। इस पर कितना पैसा लगेगा और बिजली प्रति यूनिट उपभोक्ता को कितने में मिलेगी ? स्पीकर सर, मेरा एक सुझाव है कि आज बिजली की बेहद कमी है और हर साल बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। हम मानते हैं कि अभी तक सरकार ने कोई ऐसे प्रयास नहीं किये हैं जिससे इस बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, लोग पहले ही भयभीत हैं, गर्मी का सीजन आने वाला है गर्मी में बिजली की सप्लाई के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है ? इसके बारे में आश्वासन दें कि आने वाले समय में लोगों को बिजली मिलेगी। बिजली की डिमाण्ड अगर पूरी नहीं की गई तो लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। पिछले साल भी लोगों को बिजली की कमी झेलनी पड़ी थी। स्पीकर सर, इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि सोलर ऐनर्जी को हम डिवैल्प कर सकते हैं। सौर ऊर्जा डिवैल्प कर सकते हैं उसके अन्दर आप इनवैस्ट कीजिए क्योंकि छोटे-छोटे प्लांट लगाकर हम मांग पूरी नहीं कर सकते और सोलर ऐनर्जी सस्ती भी पड़ेगी। इसके अन्दर जो पूरा खर्चा है वह सरकार स्वयं वहन करे जिस प्रकार से जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के अन्दर सौर सिस्टम में डिवैल्पमैंट हुई है। हमारे यहां पर धूप की दिक्कत नहीं है इसलिए उस सिस्टम को डिवैल्प करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस सिस्टम से बिजली की कमी को दूर किया जा सके। कृषि के बारे में सदन में चर्चा की गई है, इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कृषि के अन्दर विकास दर की राष्ट्रीय औसत है वह 2.6 दर्शाई गई है लेकिन हमारी हरियाणा की

[डॉ० सीता राम]

सरकार ने इसकी विकास दर के बारे में बताया है कि आने वाले समय में यह 4.5 प्रतिशत होगी, यह ठीक है कि हरियाणा का किसान मेहनती है। हमारी हरियाणा की सरकार उनको बिजली और पानी नहीं दे पाई है, फिर भी उस किसान ने फसल की प्रोडक्शन में बढ़ौतरी करी है। यह बढ़ौतरी किसान ने कैसे करी है यह मैं सदन में बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, किसान ने अपने खेतों में डीजल फूंक फूंक कर इस प्रोडक्शन में बढ़ौतरी की है। आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर बड़ा सा एरिया ऐसा है जहां पर जमीनी पानी अच्छा नहीं है, उस पानी में शौरा बहुत ज्यादा है। आज किसान उस पानी का प्रयोग अपनी फसलों को पकाने के लिए कर रहे हैं। इस पानी की वजह से आने वाले समय में उस जमीन की ऊपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। इस बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में हिसार के अन्दर एक मात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अध्यक्ष महोदय, सी०ए०जी० की रिपोर्ट के अन्दर यह दर्शाया गया है कि वहां पर शिक्षकों की कमी है। उसके बाद रिपोर्ट में यह भी कहा है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नए बीज बनाने के लक्ष्य को भी नहीं पा सकी है जिससे पर-एकड़ की प्रोडक्शन बढ़ सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस यूनिवर्सिटी के फंड्ज को ज्यादा करने के बारे में व्यवस्था करनी चाहिए। रिपोर्ट के अन्दर जो पर-एकड़ प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में बात कही गई है सरकार को इस बारे में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उसमें किसान की लागत कम आए और किसानों की प्रोडक्शन बढ़े। सरकार को किसानों के लिए अच्छे पानी का प्रबन्ध करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च एक्टीविटिज हैं वे भी बहुत कम हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह सरकार किसान हितैषी होने की बात करती है। लेकिन जब प्रदेश में भयानक ठण्ड पड़ी और पाले की वजह से किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ तब इस बारे में सरकार ने यह कहा कि यह नुकसान नैचुरल कलैमिटी के अन्दर नहीं आता है इसलिए हम उनको मुआवजा नहीं दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हरियाणा प्रदेश का बजट सरप्लस है फिर इस सरकार को उन किसानों को पैसा देने में क्या दिक्कत है। अगर यह सरकार किसानों की हितैषी है तो इनको उस सरप्लस पैसे को उन किसानों को देना चाहिए जिनका पाले की वजह से नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सदन में डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्राप्स की बात की जाती है। लेकिन हकीकत में डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्राप्स नहीं हो पा रही है। इसमें दिक्कत यह है कि किसानों को गेहूं और जीरी के अच्छे दाम मिलते हैं और सरकार उनको ऑयल पैदा करने वाली फसलों की पैदावार करने के लिए कहती है। अध्यक्ष महोदय, इसमें किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। उनको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। उसकी भरपाई के लिए सरकार द्वारा बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अगर आप डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्राप्स करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसानों के नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, आज तो डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्राप्स भी नहीं कर सकते है क्योंकि देश में अन्न की बड़ी भारी कमी है। आज हमें महंगे दामों पर अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता है (विघ्न) यह सिर्फ कागजों के अन्दर ही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि किसानों को अपनी फसल बेचने का पूरा अधिकार होना चाहिए। वह जहां पर भी अपनी फसल बेचना चाहे, वहां पर बेच सके। चाहे वह उन फसलों को सरकारी मण्डियों में बेचे या चाहे तो प्राईवेट मण्डी में बेचे। अध्यक्ष महोदय, यह अधिकार उन किसानों को होना चाहिए। किसान अगर किसी प्राईवेट को भी बेचना चाहे तो उसको यह अधिकार मिलना चाहिए। इसी तरह से किसान को अपने गन्ने को कहीं पर भी ले जाकर बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा हुई कि हरियाणा के अंदर काफी नये उद्योग लगे हैं लेकिन इसके

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा से बहुत से उद्योग धंधे पलायन भी कर गए हैं। कौन से उद्योग पलायन कर गए हैं उनकी भी मेरे पास कटिंग्ज हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो जो दवाई बनाने की यूनिट्स हैं वह करनाल, अम्बाला क्षेत्र से शिफ्ट होकर हिमाचल प्रदेश के अंदर चली गयी हैं क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा इंसेंटिव्ज सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। उनको इन्कम टैक्स के अंदर छूट है। इसके अलावा और भी बहुत सी छूट उनको वहां पर दी जा रही हैं। इसी तरह से अम्बाला का जो मिक्सी उद्योग है, जो ग्राइंडर उद्योग है उसकी भी कई यूनिट्स अम्बाला से शिफ्ट होकर चली गयी है। मेन बात शिफ्ट होने की यह है कि एक तो हिमाचल के अंदर ज्यादा टैक्स में छूट है और दूसरे बिजली की कमी की वजह से, भी वे हरियाणा से शिफ्ट हो रही हैं। बिजली न मिलने की वजह से वे अपना माल पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकते हैं जिसके कारण उनको घाटा उठाना पड़ता है। हरियाणा से उद्योग धंधे पलायन न करें इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि जब से यह सरकार आयी है हम हरियाणा प्रदेश को नम्बर एक पर लाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे समय में भी इन्कम के मामले में गोवा के बाद हरियाणा दूसरे नम्बर पर था और आज भी हरियाणा की पोजीशन वही है। तीन साल बीत गए पहले नम्बर पर हरियाणा कब आएगा। हर बजट में इसकी चर्चा होती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि अगर इतनी धीमी गति से हम चलते रहे तो एक नम्बर पर हरियाणा को लाने का प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट है उसके अंदर भी कई अनियमितताएं हुई हैं। कैथल डिपो के अंदर, सिरसा डिपो के अंदर या और कई डिपो भी ऐसी होंगी जिनके अंदर 49 बसिज ऐसी थीं जिनके टायर्ज न होने की वजह से महीनों तक बसिज खड़ी रहीं जिसके कारण ट्रांसपोर्ट विभाग को कम से कम एक करोड़ रुपये से ज्यादा का नुक्सान हुआ। इसी तरीके से जो बसिज यू०पी० में आपरेट करती हैं उनको भी ज्यादा टैक्स देने से नुकसान हुआ । अध्यक्ष महोदय, आज हर एक व्यक्ति ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट से संबंधित है। आज आम आदमी रोड पर चल नहीं सकता क्योंकि रोड्ज पर बहुत कंजैश्न हो गयी है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है। आम आदमी को बड़ी भारी दिक्कत है उसको चलने की जगह नहीं मिलती है। कहीं रोड़ पर फुटपाथ नहीं है और कहीं नेशनल हाई वे पर ही ऊंट गाड़ी वाले या बैल गाड़ी वाले चलते हैं। शाम के समय नजर नहीं आता सामने से लाईट पड़ती है जिसके कारण रोड्ज पर बहुत ज्यादा ऐक्सीडैंट्स होते हैं इसलिए सरकार को इस बारे में प्रयास करने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक तो यह करना चाहिए कि जो ड्राईविंग लाईसैंस बनते हैं उनके बारे में स्ट्रिक्ट नोर्म्ज फॉलो करने चाहिएं दूसरे यह करना चाहिए कि अगर सड़क पर चलने वालों के लिए जगह नहीं तो पैदल चलने वालों के लिए या तो फुटपाथ बनाए जाने चाहिएं या नैशनल हाई-वे की साईड में ही छोटे रास्ते बनाए जाने चाहिएं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप बैठिए।

डॉ० सीता राम : सर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। जो न्यूनतम मजदूरी 3510 रुपये है उसके बारे में भी मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि यहां पर बहुत से साथियों ने जिक्र किया कि यह मजदूरी किसी को मिल नहीं पाती है। अगर कोई प्राईवेट मजदूरी करता है तो उसको 1500 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह से न्यूनतम मजदूरी को सही तरीके से इम्प्लीमैंट किया जाना चाहिए। दूसरे सर, यह कहूंगा कि हरियाणा के अंदर जो अभी जूडीशियरी के अंदर आफिसर्ज की नियुक्ति हुई है उसके अंदर अनुसूचित जाति के जो आफिसर्ज थे वे बहुत ही कम संख्या में आए हैं । उनके लिए जो रिजर्वेशन के तहत पास मार्क्स 45 परसैंट होने चाहिए। यह नियम थ्रू आउट इंडिया में है लेकिन उनको जनरल कैंडीडेट की तरह ही 50 परसैंट मार्क्स पास होने के लिए दिये गये थे।

श्री आनंद सिंह दांगी : सीताराम जी, माइंड का रिजर्वेशन तो नहीं होना चाहिए ।

डॉ० सीता राम : आप रिजर्वेशन की सुविधा दे ही रहे हैं तो नॉर्म्स के अनुसार फौलोअप होना चाहिए । जिनके 45 परसैंट मार्क्स होने चाहिए, उनके लिए दोबारा से इंटरव्यू लेकर के जो उनमें योग्य लोग हैं उनको नौकरियों में मौका दिया जाना चाहिए । इसके अलावा 85वां संविधान संशोधन जो हुआ वह मूल रूप में शुरु से लागू करना चाहिए था । जो कर्मचारी है उनको प्रमोशन इत्यादि का जो लाभ बनता था वह लाभ उनको मिलना चाहिए था । इन शब्दों के साथ बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

Major Nirpender Singh Sangwan(Dadri): Sir, thank you very much for granting me time to speak on the Budget Estimates. I take this opportunity to thank and congratulate the Hon'ble Chief Minister for creating conducive conditions to sustain economic growth in Haryana.

Today, the rule of law prevails in the State which has instilled the sense of confidence in the people of Haryana. A sound foundation for a sound fiscal management in all-around development of the State has been laid. The Gross State Domestic Production(GSDP) has increased by 10.1% over the last year. The agricultural sector is expected to grow at 4.5% which is higher than the national growth rate. The industry is expected to grow at 10%, the services sector at 12%, the per capita income is expected to be pegged at Rs.38720/- only, that is second to Goa. Good fiscal management in the State has achieved a revenue surplus. State's own tax revenues at Rs.10928 crores have shown a growth of 20.37% over the last year. All these are the highlights of the Budget in the beginning. In the annual plan, the Planning Commission has approved a plan size of Rs. 6650/- crores for 2008-09, and this marks an increase of three-fold over the 2000 mark which the previous Government had achieved. The welfare schemes to benefit of our Scheduled Castes brethren and other below the poverty line, have been looked into. 21.55% of the plan funds are to be spent on the welfare schemes for this poverty or below the poverty line brethren. Hundred square yards residential plots to eligible BPL SC families are on the annals. The new initiatives - There were cases of extreme rural indebtedness leading distress to harassed farmers going to the extent of committing suicide. I take this opportunity to convey our sincere gratitude to the UPA Chairperson, Smt. Sonia Gandhi for ensuring the small and marginal farmers' indebtedness is taken care of. For this a waiver of Rs.60,000/- crores has been included in the present Budget at the Centre. Speaker Sir, Waiver Scheme of Bank Loans for small and marginal farmers is an unprecedented bold step. Speaker Sir, incentive to farmers who have paid their loan in time should also be looked into because this shall give incentive to farmers to pay bank loan in time. Intention to lower the stamp duty by another one per cent also shows the good intention of the Government. This is a great step towards the farmers being self-reliant to save some money. The Metro Rail Link from Delhi to Gurgaon is in full swing and it should be completed by the year 2010. Speaker Sir, I am sure that the Metro Rail Link to Faridabad and Bahadurgarh will also come through. An establishment of the Health University at P.G.I., Rohtak and opening to medical College with postgraduate facilities at Faridabad is also a great step towards self-

reliance in the health sector. Speaker Sir, Government has given incentive to employees by raising House Building Advance from Rs. 7.50 lakh to Rs. 12.50 lakh and for Repair and Extension of House from the existing amount of Rs. One lakh and Rs. 1.80 lakh to Rs. Two lakh and Rs. 2.50 lakh respectively. Speaker Sir, education is one of the most important areas today not only for our State but also for the whole country. A revolutionary initative has been launched as 'Mukhyamantri Scheduled Castes Shikha Protsahan Scheme'. This scheme takes care of Scheduled Castes' children who dropout after primary or high school and this scheme will go a long way. Speaker Sir, to make it sure, the Scheduled Castes boys and girls studying in Government schools will be given a monthly stipend ranging from Rs. 100 to Rs. 300 per month for boys and Rs. 150 to Rs. 400 per month for girls. Speaker Sir, our Government is opening another Sainik School in Rewari District, this is one step which is going to a long way for taking care of the children of Servicemen and Ex-servicemen. Speaker Sir, one more Sainik School is required in Bhiwani and Hisar to take care of the children of serving and Ex-servicemen because the serving soldiers and Ex-servicemen, give the best part of their life to the nation for looking after their frontiers and in this process they are not able to look after their children at the correct time. Speaker Sir, such schools will give them an opportunity to study and compete at the same level with other children. Speaker Sir, in power sector, one 1200 MW coal-based Rajiv Gandhi Thermal Plant at Khedar, Hisar and another coal-based Thermal Power Plant of 1500 MW capacity at Jhadli, Jhajjar, highlights towards self reliance in power sector which the State is going to be achieved. The separation of rural, urban and agriculture feeders is another great step. Speaker Sir, repair of transmission lines and changing of old lines which are hanging low in most of the villages is a propriety because this leads to accidents and power failure at many times. Speaker Sir, iron poles and the transmission lines in some of the villages need to change. Distribution lines in old towns, are very old and it also need to change. This sector needs to look into. In the irrigation sector, equitable distribution of water throughout the State is being achieved. We are eagerly waiting for completion of the BML-Hansi-Butana Branch in Dadri and looking forward to get more water. The Hon'ble Chief Minister and the Minister has agreed to increase the water from 2.4 to 3.05 MAF I would suggest that escape reservoirs should be made at all the pump-houses so that these can recharge the water table in the area.

Under the Indira Gandhi Drinking Water Scheme, household connections are being given free of cost to the Scheduled Castes houses, but it needs strict vision for its implementation. Sanitation in town needs to be looked into so that new sewerage lines which are being laid, should cater up to at least 2025.

Unprecedented growth of industries in the industrial hubs of the State are the hallmark of our Government. I request that an industrial hub be created for under-privileged areas like Dadri. Talking about Dadri, I would say infrastructure available at Dadri is unprecedented. Land is available at reasonable prices there. Trained man power is available with the IT which is coming up in Dadri itself. It has a rail head. Moreover, it is only few kilometres away from Jhadli where power plant is coming up. Dadri has the best road network with the rest of India. Speaker Sir, therefore, I would request through you that an industrial hub may be created at this place shortly.

[Major Nirpender Singh Sangwan]

The Government has given best priority to the road net-work in the State. I am proud to say that the Rajiv Gandhi Bridges and Roads Infrastructure Development Programme involving Rs. 3000 crore was started from Dadri by Hon'ble Smt. Sonia Gandhi herself. I thank the Hon'ble Chief Minister for having chosen Dadri for the avenue. The rural roads under construction need to be checked for quality. This is one bench-mark that we have to look into.

The agriculture department needs to do more. Agriculture Department needs to tie up at the lower level and at the ground level with the farmers. The department needs to do more demonstrations in the villages. The representatives of Agriculture Department can go and demonstrate the new seeds, pesticides & secticides in the villages. They can demonstrate how the new crops are grown and it should be shown to the farmers. This department has to show how it is sown. Speaker Sir, the Animal Husbandry Department needs more revenue, more funds to be injected into this department because we need new veterinary clinics, more staff, more hospitals for this. Speaker Sir, in the Education Sector also more funds are required. I would suggest a new Sports University for Haryana because Haryana has the potential to produce all kinds of sportsman in the field of sports. So, therefore, we need to pump it more money and enthusiasm in this field.

Sir, I am sorry to say that the Health Department needs a lot of overhauling. There is a paucity of staff and the staff which is available, is not willing to work in the rural areas. Sir, मुझे आपको एक बात बतानी पड़ेगी। आज की तारीख में जितने डाक्टर्ज दादरी में पोस्टिड हुए हैं वे सारे के सारे अपनी बदली करवाकर जाते रहे, 10 डाक्टर्ज में से केवल 3 ही पोस्टिड हैं। आज किसी भी PHC में डाक्टर नहीं है । वहां पर कोई डॉक्टर काम करने के लिए राजी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय डॉक्टर्ज की नियुक्ति की जाये उस समय उनको बताया जाये कि उनको रूरल टाऊन्ज में पोस्टिंग दी जायेगी, जैसे दादरी है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वाईड-अप करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (नौलथा) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा में वर्ष 2008-09 का जो कर रहित बजट माननीय वित्तमंत्री जी ने पेश किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बजट सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का एक दर्पण है। इसमें सभी योजनागत खर्चों का विस्तार से वर्णन किया हुआ है और समाज के सभी वर्गों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, सही मायने में यह बजट विकास पूरक बजट है। वित्तमंत्री जी का यह चौथा प्रयास है और इन्होंने पिछले वर्षों की तरह से इस बार भी सभी विभागों के बजट में बढ़ौतरी की है। इस बजट की मुख्य विशेषता यह है कि सामाजिक आधार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 84 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी रिकार्ड की बात है कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से 21.35 प्रतिशत बजट का हिस्सा रखा गया है जबकि प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.33 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, आज से तीन साल पहले जिस समय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बागडोर

संभाली थी उस समय प्रदेश में अराजकता, आतंक और भय का वातावरण था जिसको ठीक करने की चुनौती हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारी थी। आज हमें इस बात की खुशी है कि जिन बदमाश लोगों को पहले सरकार का समर्थन मिलता था आज वे या तो प्रदेश छोड़कर चले गये हैं या प्रदेश की मुख्यधारा में शामिल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप रैपीटेशन न करें। यदि आपको कोई नई बात कहनी है तो आप कहें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या के लिए आपको अपनी तरफ से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सदस्या इस सदन की सबसे पुरानी सदस्या हैं इसलिए इनको अपनी बात कहने का पूरा-पूरा मौका दिया जाये।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अब मैं इस सदन का ध्यान कृषि क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहती हूं। आज से तीन साल पहले जब माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने सत्ता सम्भाली थी तो उस समय प्रदेश का सारे का सारा हिसाब किताब बिगड़ा हुआ था। तरह-तरह के कर्जों का भार किसानों के ऊपर था। चौधरी देवी लाल जी ने लोगों को यह कहा था कि बिजली के बिल कोई न भरे जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो एक कलम से सारे कर्जे माफ कर दूंगा। सत्ता हथियाने के लिए तत्कालीन राजनेताओं के द्वारा किए गए इस प्रकार के वायदों से किसानों का बिजली का बिल साल दर साल बढ़ता गया लेकिन किसी भी भूतपूर्व सरकार द्वारा किसानों का यह बिजली का बिल माफ नहीं किया गया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों के इस दर्द को समझकर 1600 करोड़ रुपये के किसानों के बिजली के बिल माफ करने का अभूतपूर्व कार्य किया और इसके साथ ही मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन सिंह और भारत सरकार को भी बधाई देती हूं। जिसने इस देश के किसानों का 60 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ करके एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। हमारे देश का किसान कर्ज़ के बोझ तले बुरी तरह दबा हुआ था और अनेक जगहों से उसके द्वारा आत्महत्यायें करने के समाचार प्राप्त हो रहे थे। किसान को भी पूरी मेहनत करने के बावजूद अपना पूरा हक नहीं मिलता था। यह भी एक बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है इसके साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी ने जो एक बात का वर्णन किया है जो साहूकारों का कर्जा है उसके बारे में भी कोई न कोई निर्णय जल्दी ही लिया जायेगा। कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाला जायेगा। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा को-आपरेटिव बैंकस के कर्जो के ऊपर जो 830 करोड़ रुपये के ब्याज को भी माफ किया गया है, यह भी एक सराहनीय कार्य है। लेकिन मैं एक बात सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों को भी फायदा हो और छोटे किसानों को भी लाभ हो लेकिन इनके अलावा जो भूमिहीन लोग हैं जिन्होंने छोटे-छोटे लोन ले रखे हैं किसी ने बुग्गी के लिए, किसी ने छोटी मशीन के लिए तो किसी ने चक्की के लिए लोन ले रखा है उनकी भी अगर इसी प्रकार से मदद की जाये तो सोने पर सुहागा हो जायेगा। मैं यह समझती हूं कि सरकार को इस बारे में भी कुछ कारगर कदम उठाने चाहिएं जिससे इस प्रकार के भूमिहीन लोगों को भी कुछ राहत मिल सके।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो यह भूमिहीनों के कर्जों के बारे में चर्चा की है इस बारे में हरियाणा सरकार की यह नीति थी कि जिन्होंने कॉआपरेटिव सैक्टर में नॉन एग्रीकल्चर लोन ले रखा था उनका हम पहले ही सारे का सारा ब्याज माफ कर चुके हैं। इस स्कीम से 1 लाख 6 हज़ार 17 लोगों ने लाभ उठाया है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहती हूं कि जैसे किसानों का पूरा कर्ज़ा एक बार में ही माफ कर दिया गया है इसी प्रकार से अगर इनके लिए भी कुछ किया जायेगा तो इससे इनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और यह भी एक बहुत अच्छा और सराहनीय कदम होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह भी सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि जो भूमिहीन लोग हैं जो अपने काम धंधों के लिए छोटे-छोटे लोन लेते हैं उनको 10 हज़ार रुपये से ज्यादा लोन नहीं मिलता। अगर इस लोन सीमा को भी बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये कर दिया जाये तो इससे उनको ज्यादा सहूलियत होगी क्योंकि 10 हज़ार में तो अब कुछ भी नहीं आता। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे उनको अपना काम करने में भी बहुत अच्छी सहूलियत मिलेगी। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में सारे काम बड़ी सूझ-बूझ के साथ कर रहे हैं और किसी भी वर्ग को कोई दिक्कत नहीं होती । बैंको द्वारा उदारवादी दृष्टिकोण के तहत लोन देने और अन्य कल्याणकारी नीतियों के कारण किसी को भी पैसे की कमी कहीं भी नज़र नहीं आती और कोई भी काम अधूरा नहीं रहता है। शिक्षा की दृष्टि से हमने बहुत तरक्की की है। भारी तादाद में स्कूलों को अपग्रेड किया है और कई ऐसे फैसले भी लिये हैं जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। कुण्डली में राजीव गाँधी ऐजूकेशन सिटी का जो निर्माण किया जा रहा है जिसमें विश्व प्रसिद्ध संस्थाएं आयेंगी उसमें 25 परसैंट सीटें हमारे अपने प्रदेश के बच्चों के लिए होंगी जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी प्रकार से मुरथल में मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज को दीन बंधु सर छोटू राम साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, यह एक सराहनीय कदम है। पूरे उत्तर भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय खानपुर में बना और उसमें कुलपति से लेकर सभी कर्मचारी भी महिलाएं ही होंगी। इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि खानपुर में ऐसी दयनीय हालत होती थी कि केवल तीन कमरे थे और उनके आगे घास-फूस का छप्पर होता था। बरसात के दिनों में वह भी सारा टपकता रहता था। किसी ने उसके हाई स्कूल तक अपग्रेड होने की बात भी नहीं सोची थी लेकिन आज वह एक यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है। यह पूरे उत्तर भारत में एक मिसाल है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को बधाई देती हूं कि यह महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहुत सारे स्कूल अपग्रेड हुए हैं लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि लड़कियों के लिए स्कूल भी ज्यादा तादाद में अपग्रेड किये जायें। आज के हालात के मुताबिक हर जिले में कम से कम एक कॉलेज लड़कियों के लिए, जहां भी बनाया जा सकता हो, जरूर बनाना चाहिए उससे आजकल का जो माहौल है उसको थोड़ा सा सुधारने में राहत मिलेगी। इसी प्रकार से सिंचाई के लिए बहुत अच्छे कदम उठाये हैं। पहले जितना पानी आता था चौटाला जी उस पूरे पानी को सिरसा में ही पूरा कर लिया करते थे और 42 दिन तक नहर में पानी नहीं आता था लेकिन जब से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आई है उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले पानी के समान बंटवारे के लिए एक सिस्टम बनाया। मैं जहां तक समझती हूँ कि अब किसी को भी 2 सप्ताह से ज्यादा पानी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। हरेक को उसके हिस्से के मुताबिक पानी मिलता है। बी०एम०एल० हांसी बुटाना ब्रांच के बनने के बाद इस में और भी ज्यादा सहूलियत हो जायेगी। उसका 90 परसैंट काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी बाकी का काम भी पूरा हो जायेगा। इसी प्रकार से दादूपुर-नलवी नहर का निर्माण जो पिछले 20 साल से ठण्डे बस्ते में पड़ा हुआ था वह शुरू हो चुका है। इस नहर के निर्माण के बाद शाहबाद और अम्बाला का जो एरिया है उसको भी पानी मिल सकेगा। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार को बधाई देती हूं। इसी प्रकार से सड़कों का काम बहुत तेजी से हो रहा है और सब जगह हो रहा है। जो सड़कें 12 फुट चौड़ी थी उनको 18 फुट चौड़ा किया गया

है। मुझे 6 बार इस सदन में आने का मौका मिला है। जहां संयुक्त पंजाब में एक एम०एल०ए० 5 साल तक अगर 5 किलोमीटर की सड़क बनवा लेता था तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता था लेकिन आज मुझे खुशी है कि सड़कों की कमी नहीं है। कहीं पर प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें बन रही हैं और कहीं पर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सड़कें बनाई जा रही हैं। किसी को कमी महसूस नहीं होती कि उनके यहां सड़कों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा जिन सड़कों की मुरम्मत की जाती है उसमें थोड़ी देरी हो जाती है उन पर भी अगर थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाये तो और भी अच्छा होगा। जी०टी० रोड़ पर मेरे हल्के का एक गांव है सिवाह, उसमें मार्केटिंग बोर्ड की एक सड़क बनी हुई है। यह जो सड़क है यह बाईपास के साथ मिलती है। यह सड़क तो बनी हुई है। लेकिन इस सड़क की हालत खराब हो गई है और इसकी रिपेयर नहीं हुई है। मैं इसके बारे में एक साल से लिख रही हूं तथा दो साल से मैं इसके बारे में सवाल उठा रही हूं। अगर इसकी रिपेयर हो जाए तो इससे यहां के लोगों को काफी फायदा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। महिलाओं के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है और इसके साथ ही साथ अध्यापकों के पदों में 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है जो कि इस सरकार का सराहनीय कार्य है। मकानों की जहां तक बात है, हाउसिंग बोर्ड और हुड्डा द्वारा बनाए गए मकान और डिवैल्प किए गए प्लॉट्स में इस सरकार ने 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किये हैं जो कि इस सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए इस सरकार ने 100-100 गज के प्लाट्स दिए हैं। पहले ये प्लॉट्स श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गरीबों को दिए गये थे लेकिन इस बात को काफी समय हो गया है और उन परिवारों की दो-दो या तीन-तीन पीढ़ियां हो गई हैं। उन लोगों के पास अब बैठने तक को जगह नहीं है। 100 गज जमीन उनको बहुत बड़ी दिखाई देती है हालांकि आम आदमी के लिए 100 गज जमीन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है लेकिन गरीब परिवारों के लिए यह बहुत बड़ी चीज है जिससे उनको बहुत सहारा मिल रहा है। ये प्लॉट्स मिलने पर वे परिवार ठीक प्रकार से गुजारा कर लेंगे। सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है और मैं इसके लिए अपनी सरकार को बधाई देती हूं। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं स्वास्थ्य के मामले में कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि पी०जी०आई०, रोहतक को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, यह बहुत ही अच्छी बात है। सी०एच०सी०, पी०एच०सीज० और सब-सैंटर्ज बनाए गए हैं। लेकिन मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि जो 10-10 या 20-20 हजार की आबादी के गांव हैं वहां पर सब-सैंटरज होते हैं। बड़े-बड़े गांव जो कुछ ब्लॉक में भी आते हैं इनमें पी०एच०सी० या सी०एच०सीज० बनाने के बारे में सरकार विचार करे कि उनके लिए क्या स्कीम बनाई जा सकती है ? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से खाद्य पदार्थों की सप्लाई की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाउंगी। वैसे तो खाद्य पदार्थों और दूसरी चीजों की प्रदेश में कोई कमी नहीं है लेकिन वे मंहगे रेट्स पर मिलती हैं। इनमें कोई दो राय नहीं है कि अनाज महंगा होने से किसानों को लाभ हुआ है और उसको उसकी मेहनत की कीमत मिलनी शुरू हुई है। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी है कि वह गरीब आदमी जिसने अनाज खरीद कर खाना होता है उसको इस मंहगाई के कारण काफी दिक्कत होती है। 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम अनाज कार्ड के साथ प्रत्येक गरीब परिवार को दिया जाता है। मैं यह समझती हूं कि यह अनाज उसके परिवार के लिए थोड़ा है और उसको कम से कम 50 किलोग्राम कर दिया जाए तो उसको इससे ज्यादा सहूलियत मिल सकेगी और खाने पीने की उसकी दिक्कत कम होगी। यह महंगा अनाज खरीद

[श्रीमती प्रसन्नी देवी]

कर अपने परिवार को नहीं खिला सकता है। इसी प्रकार से मिट्टी का तेल है उसकी सप्लाई के लिए ठीक इन्तजाम किया जाए। पहले मिट्टी का तेल एक परिवार को पांच लीटर मिलता था लेकिन अब इसको तीन लीटर कर दिया गया है और अब पांच लीटर की बजाए उनको तीन लीटर मिट्टी का तेल मिल रहा है। स्पीकर सर, कार्ड का सिस्टम ऐसा करना चाहिए कि वे किसी दूसरे कार्ड के भरोसे न रहें बल्कि जो राशन कार्ड है उसी पर सारी चीज मिल जाए। उसी राशन कार्ड पर अनाज भी मिल जाए और मिट्टी का तेल भी मिल जाएगा तो इससे गरीब आदमी को बहुत सुविधा हो जाएगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं तथा माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करती हूं। यह बजट प्रदेश में तरक्की लाएगा क्योंकि इस बजट में हर मद के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे की व्यवस्था की गई है जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। जय हिन्द !

विधान कार्य--

1. दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैंशन ऑफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2008

Mr. Speaker : Hon'ble members now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in clause 2. He may move his amendment.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

"That in clause 2 of the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2008 for the proposed sub-section (1) of Section 7A of the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1975, the following sub-section shall be substituted, namely :—

(1) Every person shall be paid a pension of five thousand rupees per mensem if he has served as a member for a period not exceeding five years and an additional pension of one thousand rupees per mensem for every additional year or part thereof exceeding a period of five years and if the period of the first membership falls less than the term of five years of the Assembly, it will be treated as full period of five years for the purpose of pension :

Provided that family pension shall be admissible, as may be prescribed, to surviving spouse and after his or her death to the children (upto the age of eighteen years) of members who had been drawing pension under this Act."

Mr. Speaker : Motion moved—

"That in clause 2 of the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2008 for the proposed sub-section (1) of Section 7A of the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1975, the following sub-section shall be substituted, namely :—

(1) Every person shall be paid a pension of five thousand rupees per mensem if he has served as a member for a period not exceeding five years and an additional pension of one thousand rupees per mensem for every additional year or part thereof exceeding a period of five years and if the period of the first membership falls less than the term of five years of the Assembly, it will be treated as full period of five years for the purpose of pension :

Provided that family pension shall be admissible, as may be prescribed, to surviving spouse and after his or her death to the children (upto the age of eighteen years) of members who had been drawing pension under this Act."

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल का प्रस्ताव हमारी सरकार लेकर आई है इस बारे में हमारे बहुत से माननीय साथी मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उनसे दो अनुरोध किये थे। इसमें पहला अनुरोध यह था कि 5000 रुपए प्रति माह जो पैंशन हमारे साथियों को मिलती है उसमें यह प्रोवीजन था कि अगर पहली टैन्यौर उसकी पांच साल से कम की होती थी और अगर वह दूसरी बार जीत कर आता है तो उसके उस टैन्यौर के समय को उसकी पांच साल की टैन्योर को पूरा करने के लिए काऊंट कर लिया जाता था। इस बारे में कई साथियों की शिकायत थी कि कई बार विधान सभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है तो इस वजह से कई सदस्यों को पैंशन का नुकसान होता था। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस बिल के माध्यम से एक अमैंडमैंट लेकर आई है कि अगर एक मैम्बर एक बार इलैक्ट हो जाता है तो उसे पूरे पांच हजार रुपए पैंशन मिलेगी, irrespective of whether he has completed the tenure of 5 years or not. उसके बाद जो उसकी सैकेंड टैन्यौर है उसमें हर साल 1000/- रुपए उसको पैंशन मिलेगी। पहले 90 दिन का प्रावधान था कि उसको मिनिमम सर्व 90 दिन करना है तो हमारी सरकार ने उसको भी डिलीट कर दिया है। If fraction of even one day in a year is completed, he will be entitled to Rs. 1000/- as pension. So, these are the two beneficial provisions, which we have brought for the members who retire.

Mr. Speaker : Question is—

> "That in clause 2 of the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2008 for the proposed sub-section (1) of Section 7A of the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1975, the following sub-section shall be substituted, namely :—
>
> (1) Every person shall be paid a pension of five thousand rupees per mensem if he has served as a member for a period not exceeding five years and an additional pension of one thousand rupees per mensem for every additional year or part thereof exceeding a period of five years and if the period of the first membership falls less than the term of five years of the Assembly, it will be treated as full period of five years for the purpose of pension :
>
> Provided that family pension shall be admissible, as may be prescribed, to surviving spouse and after his or her death to the children (upto the age of eighteen years) of members who had been drawing pension under this Act."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

2. दि हरियाणा स्पैशल इकोनोमिक जोन (अमैंडमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

डॉ० सुशील इंदौरा (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार स्पैशल इकोनोमिक जोन (अमैंडमैंट) बिल लेकर आयी है। कोई भी बिल जब लाया जाता है तो वह उसकी सरलीकरण के लिए, उसकी मजबूती के लिए लाया जाता है। स्पैशल इकोनोमिक जोन क्योंकि व्यापारी से भी, उपभोक्ता से भी और हरियाणा प्रदेश के आम नागरिक से भी जुड़ा हुआ है इसलिए सरलीकरण के साथ-साथ इसको मजबूती से भी लागू करना होता है और इसके लिए यह जरूरी है कि संशोधन किए जाएं और ऐसे संशोधन किए जाएं कि कहीं भी पावर्ज को एक हाथ में न लिया जाए that should be decentralized. इनको डिसैंटरलाइज भी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के बारे में मेरा एक सुझाव है कि जो परियोजना अनुमोदन समिति का गठन किया गया है उसके जितने भी मैम्बर्ज हैं वे सारे के सारे सरकारी अधिकारी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में और प्रदेश में ऐसे अनुभवी लोगों की कमी नहीं है और वे स्पैशल इकोनोमिक जोन के बारे में अच्छी जानकारी दे सकते हैं, अच्छी राय दे सकते हैं, अच्छा मशविरा दे सकते हैं। इसलिए इस समिति में दो चार ऐसे लोग भी होने चाहिए थे जिनको अनुभव हो, जो स्पैशलाइज्ड हों, जो व्यापारियों से जुड़े हुए लोग हों, जो मशीनरी से जुड़े हुए लोग हों या कोई और ऐसे लोग हों जो इससे जुड़े हुए हों। इस तरह के दो चार लोग इस समिति में जरूर होने चाहिए थे। जिस तरह से समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुमोदन करके सरकार को भेजे, ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करके एक पड़ाव डाल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, होना यह चाहिए था कि एक समयबद्ध एस०ई०जैड० का प्रोग्राम होना चाहिए था। अगर एस०ई०जैड० का कार्यक्रम समयबद्ध हो तो इससे व्यापार में बहुत लाभ मिलता है। अगर आज जमीन ऐक्वायर कर ली और यदि पांच-पांच साल तक उस पर एस०ई०जैड० नहीं बना तो किसान की वह जमीन खाली ही रहेगी। वह जमीन न तो किसान के काम आएगी और न व्यापारी के काम आएगी। जिस तरह से हुडा द्वारा मकानों को बनाने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया जाता है उसी तरह से अगर इस बारे में समय सीमा फिक्स करते तो अच्छा रहता। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का भी संशोधन लाने की जरूरत थी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और जरूरी अहम बात कहना चाहूंगा। जैसे कल को मान लो कि प्रोजैक्ट फेल हो गया, इसके कई आर्थिक कारण हो सकते हैं और अगर इस पर कोई कार्यवाही न हो तो ठीक नहीं है क्योंकि जो सरकार द्वारा अधिग्रहित की गयी जमीन की कीमत है या व्यापारी ने जो सस्ते दाम पर जमीन खरीदी है, उस जमीन की कीमत बढ़ेगी। सरकार ने जो जमीन अधिग्रहण की है वह जमीन व्यापारी बेचकर अपना घाटा पूरा करेगा लेकिन जिस तरह से किसान को वह जमीन मिली थी उससे उसका तो नुक्सान होगा। इसमें यह भी संशोधन किया जाना चाहिए जैसे कल को कोई प्रौजैक्ट फेल हो जाता है तो या तो वह जमीन सरकार अपने पास रखे या फिर वह जमीन जिस किसान से ऐक्वायर की गई थी, उसी किसान को वापस कर दी जाए और जिस रेट पर उससे ली गई थी उसी रेट पर वापस कर दी जाए, ऐसा संशोधन इसमें और किया जाए, यह मेरा सुझाव है। इस बारे में एक कमेटी और बनाई जाए जो कि इसे विस्तार से देखे कि जहां व्यापारी की जिम्मेदारी डालना चाहते हैं वहां व्यापारी की जिम्मेदारी डाली जाए लेकिन जहां सरकार की जिम्मेदारी बनती है वहां सरकार की जिम्मेदारी भी डाली जाए। यह मेरा सुझाव है। सरकार अगर बिजली नहीं दे पाती तो सरकार उसमें जिम्मेदार होनी चाहिए, अगर पानी समय पर

नहीं दे पाती है तो सरकार भी जिम्मेदार होनी चाहिए और इसमें यह भी करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में सरकार उसकी भरपाई कैसे करेगी, यह भी बताना चाहिए। कल को यदि व्यापारी छोटा सा प्रौजैक्ट एस०ई०जैड० में लगा लेता है और बड़ा प्रौजैक्ट बाहर लगा लेता है और बाहर किए हुए प्रौडक्शन को यहां दिखा देता है तो इससे सरकार को आर्थिक नुकसान होगा और रैवैन्यू कलैक्शन नहीं हो पाएगा। अत: इस बारे में मेरे द्वारा दिये हुए संशोधन को शामिल करने में सरकार का फायदा है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर इंदौरा जी ने इस बिल पर अपने सुझाव दिये मैं दो बातें आपकी अनुमति से सदन और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो यह अमैंडमैंट है वह एसैंशियली फौर्मल अमैंडमैंट है और जो एस०ई०जैड० ऐक्ट है, इसे इसी सदन में सर्वसम्मति से पारित करवाया था। उसके अंदर हर चीज की सीमित सीमा लिखी गई है कि इतनी अवधि के अंदर अमुक परमीशन देनी है। मैंने उस दिन भी इस बारे में प्वायंटआउट किया था। पहली बार टाइम पीरियड में इसको कानूनी अमली जामा पहनाया है । अब जो मैंने बिल पढ़ा है यह सारे अगर उस पीरियड में आने होते तो automatically, it will be a deemed approval. उसमें लिखा है कि इस अमैंडमैंट ऐक्ट के दो लक्ष्य हैं। एक तो दो अलग-अलग कमेटी थी । अब इसमें एक प्रौजैक्ट इवैल्यूऐशन कमेटी बना दी है । इसके साथ ही एक और चिन्ता माननीय सदस्य ने जाहिर की है कि इसके अंदर केवल अधिकारीगण हैं और इसमें नैसैसरी टैक्नीकल ऐक्सपर्टीज या पौलिटिकल इन्पुट इसके अंदर होने चाहिए, नहीं तो यह कमेटी निर्णय नहीं ले पाएगी, इस बारे में मैं माननीय सदस्य की शंका का निवारण करने के लिए बताना चाहूंगा कि इसको आगे पढ़ें, Speaker Sir, this is only a Project Evaluation Committee. Finally, this will go to the Government and the Government will apply its own mind and it has right to reject, it has a right to amend and it has a other rights also. It can lay down conditions one, two, three, four and further. Speaker Sir, so, this Project Evaluation Committee's report is not sacrosanct, as if it can never be changed by the Government. The Government has discretion to change it. Thirdly, Speaker Sir, by amending this legislation, I want to draw Hon'ble learned Member's attention to clause 7 of this Bill, where we have said that we have proposed to amend Clause (i) of Sub-section (1) of Section 11. इससे पहले तो डिवैल्पर भी वैट और दूसरी चीजों का यूनिट के साथ साथ बैनीफिट ले सकता था लेकिन अब हमने उसे रूलआउट कर दिया है । अब जो यूनिट लगाएगा वह वैट का लाभ उठा सकेगा। पर डिवैल्पर नहीं उठा सकता इसलिए इसमें हम क्लॉज 7 में क्लॉज (i) ऑफ सब- सैक्शन (1) ऑफ सैक्शन 11 को अमैंड करके लेकर आए हैं । बाकी सभी फॉर्मल है इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह जो अमैंडिंग बिल है इसको पारित किया जाए ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय दस मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। हाउस का समय दस मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

दि हरियाणा स्पैशल इकोनोमिक जोन (अमैंडमैंट) बिल, 2008 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 6 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 7 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 8 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. दि हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर (प्रिवैंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

वाक-आउट

डॉ० सुशील इंदौरा (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, यह जो दि हरियाणा स्टेट लेजीस्लेचर (प्रिवैंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 2008 सदन में लाया गया है। यह व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए लाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि जिस तरह से ये पारदर्शिता की बात करते हैं। जिस पार्टी से ये संबंधित हैं। उसकी अध्यक्षा और यू०पी०ए० की चेयरपर्सन ने लाभ के पद पर रहते हुए रिजाईन देकर दोबारा से चुनाव लड़ा था। उस पार्टी से संबंधित होते हुए हमारे सदन के नेता आज सदन में बिल लेकर आये हैं। जिस माननीय सदस्य को हरियाणा स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्ज कमीशन का चेयरमैन बनाया है उनको लाभ देने के लिए यह बिल लाये हैं अच्छा तो यह होता कि पहले उन माननीय सदस्य से रिजाईन करवाते और फिर उनको इस कमीशन का चेयरमैन बनाते और फिर बिल में संशोधन लाते। क्या जरूरत पड़ी थी इस अमैंडमैंट को लाने की ? इस संशोधन में यह नहीं बताया गया कि क्या समय सीमा निर्धारित की गई है और जब यह खत्म हो जायेगा तो उसकी क्या जरूरत पड़ेगी ? अगर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए आपने कुछ करना है तो बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, बोर्ड बने हैं, कमीशन बने हैं, इन सबको भी इसमें ले आईये, बार-बार संशोधन लाने की क्या जरूरत है ? बहुत से चेयरमैन आपने कवर किए हुये हैं जैसे एम०आई०टी०सी० के चेयरमैन को पहले ही कवर किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह गलत हो रहा है क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए यह बिल लाया गया है। इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं और एज ऐ प्रोटैस्ट सदन से वॉक आउट करते हैं।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वॉक- आउट कर गये)

दि हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर (प्रिवैंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 2008 (पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब ने जो बात कही है कम से कम उनको अपनी बात का जवाब तो सुनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आपने जो बात कही है उसका जवाब तो आपको सुनना चाहिए। It is your moral duty. सदन की कुछ गरिमा है। वाक आउट करने से पहले आपको जवाब तो सुनना चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी ने इल्जाम लगा दिया कि व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए सरकार ये अमैंडिंग बिल लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, वे भूल गए कि जब वे पहली बार बजट पर बोले तो यह उनकी मांग थी कि हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्मस कमीशन बनाया जाए। एक तरफ तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्मस कमीशन बनाने की मांग करते हैं और दूसरी तरफ आप उसका विरोध करते हैं। आप हैं किस तरफ। इसलिए मैंने उनसे सादर अनुरोध किया था कि कम से कम आप जवाब तो सुनले जाएं। उनकी लगातार यह मांग थी कि हरियाणा में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्मस बनाया जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी यह बात मान ली है। आज अगर ओफिस आफ प्रोफिट से उसको निकाल रहे हैं तो इसमें कोई अतिश्योक्ति या अनहोनी बात नहीं है। इन्दौरा जी, आप भूल गए कि आपके समय में ऐसी बहुत सी अमैंडमैंटस आई हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जिनकी बात आप कह रहे हैं, they are all included here. आप सैक्शन 3(1) (ए) से क्लाज (के) तक पढ़कर आए होते तो आपको पता चल जाता कि इसमें बहुत सी श्रेणियां हैं जो इसके अंदर इन्क्लयूडिड हैं। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जिसने लगातार लोकदल के साथियों के कच्चे चिट्ठे खोलने का काम किया है उस व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए यह किया गया है। पीड़ा एक व्यक्ति से है तो अलग बात है पर इसमें कोई संवैधानिक या कानूनी दिक्कत नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि संविधान के इस अमैंडिंग एक्ट को पारित कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

> That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in clause 2. He may move his amendment.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That in Clause 2 of the Bill, after clause (l), the clause (m) may be added as follows:—
>
> "(m) Deputy Chairman 20-Point Economic Programme."

Mr. Speaker : Motion moved—

That in Clause 2 of the Bill, after clause (l), the clause (m) may be added as follows:—

"(m) Deputy Chairman 20-Point Economic Programme."

Mr. Speaker : Question is—

That in Clause 2 of the Bill, after clause (l), the clause (m) may be added as follows:—

"(m) Deputy Chairman 20-Point Economic Programme."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 25th March, 2008.

18. 38 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 25th March, 2008.)

44396—H.V.S.—H.G.P., Chd.